हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 मार्च, 1988

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 29 मार्च , 1988

पृश्ठ संख्या

स्थगित ताराकित प्र न एवम उत्तर	(10)1
ताराकित प्र न एवम उत्तर	(10)2
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(10)28

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	
15 मार्च, 1988 को भारत बन्द में सम्मिलित होने के लिए आ रहे व्यक्तियों पर लाठी चार्ज करने सम्बन्धी	(10)52
समितियों की रिपोर्टस पेश्र करना –	
(i) कमेटी औन पब्लिक अकाऊंटस की 26वीं और 27वीं रिपोर्टस	(10)57
(ii) कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की 27वीं रिपोर्टस	(10)58
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 1) बिल, 1988	(10)58
वर्श 1988–89 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(10)60

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 29 मार्च , 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्र ान एवम उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, सबसे पहले पोस्टपोन्ड स्टार्ड क्वैश्चन्ज की लिस्ट टेक–अप की जाएगी।

श्री टेक चनद नैन का स्टार्ड क्वैश्चन *336 लिस्ट पर है जिसके लिए कृशि राज्य मंत्री ने और ऐक्सटैन्शन मांगी है जोकि ग्रान्ट कर दी गई है। उनसे आया पत्र इस प्रकार हैः–

''तत्काल

विधान सभा कार्य

विशय:– विधान सभा तारांकित प्रश्न न. 336 जो श्री टेक चन्द नैन, विधायक द्वारा पूरा गया है, के बारे उत्तर देने बारे।

हरियाणा विधान सभा तारांकित प्रशन संख्या 336 जो कि श्री टेक चन्द जैन, विधायक द्वारा पूछा गया है, का उत्तर दिनांक 16.3.88 को हरियाणा विधान सभा अधिवेशन में देय था, जिसमें कम से कम एक सप्ताह के लिए समय वृद्धि ली थी। यह

प्रश्न प्रतिपूरक अनुसूची के अनुसार दिनांक 29.3.88 को उत्तर हेतू पुनः निश्चित है किन्तु वांछित उत्तर बारे पूर्ण सूचना प्राप्त न होने के कारण उत्तर तैयार नहीं है। अतः उनसे अनुरोध है कि प्रश्न का उत्तर तैयार करने हेतू रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कण्डक्ट आफ बिजनैस इन दी हरियाणा विधान सभा के नियम 41 के परन्तुक (2) के अनुसार कम से कम सप्ताह और की बढ़ौतरी दें।

हस्ता/–

राज्य मंत्री, कृशि

हरियाणा

सेवा में,

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।

अशाः क्रमांक 802–कृ.अ. (1)–88/5855 चण्डीगढ दिनांक 28.3.88

पृश्ठा. क्रमांक 802–कृ.अ. (1)–88/ चण्डीगढ़, दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेशित की जाती है।

1. प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, हरियाणा

2. मुख्य सचिव, हरियाणा

(राजनैतिक शाखा में)

3. अधीक्षक, मुख्य मंत्री सचिवालय,

हरियाणा।

राज्य मंत्री कृशि,

हरियाणा

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब आज के क्वैश्चन की रैगुलर लिस्ट टेक–अप की जाएगी।

Water logging in District Sirsa

***415. Sh. Ranjit Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the lands of the following villages–

(i) Surtia,

(ii) Rori,

(iii) Phaggu,

(iv) Maleri,

(v) Bhinwa,

(vi) Thiraj

(vii) Dadu,

(viii) Desu,

(ix) Jhorar Rohi,

(x) Panjwala,

(xi) Jhiri, and

(xii) Rohan,

of Rori Constituency in District Sirsa have become un-cultivable and unfertile due to to constant water logging with the result that farmers of these villages have suffered economically; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to control the water logging int he above villages and other villages of that area.

Irrigation and Power Minister (sh. Verender Singh):

(a) Yes.

(b) Originally a scheme was approved to excavate Rori-Ghaggar drain for disposal of flood water into river Ghaggar. This scheme has since been revised. It is now porposed to excavate deep drains in the area and pump the subsurface/flood water into nereby irrigation channels.

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बताना चाहता हूं कि मेरे इलाके में कम सक म 15 गांव ऐसे हैं जोकि फलड की वजह से बिल्कुल तबाह हो जाते हैं और सरकार की ओर से कोई उपाल इसकी रोकथाम के लिए नहीं किए गए है। अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इसके लिए एक स्कीम एप्रूव की गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चहता हूं कि जो स्कीम बनाई गई है, वह किस स्टेज पर है या वह अभी कागजों में ही है? क्या इस स्कीम के लिए कोई पैसा भी सेंक्शन किया गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस स्कीम से सम्बन्धित पेपर्ज सैक्रेटरी साहब के पास आ चुके हैं और बहुत जल्द ही इस स्कीम को सैंकशन कर दिया जाएगा और फाइनैंस विभाग से इसके लिए पैसा सैक्शन करवा लिया जाएगा।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर सर, बरसात के दिनों में हमारा सारा इलाका तबाह हो जाता है और 15 गांव मेरे हल्के के ऐसे हैं जहां पिछले 20 सालों के कोई फसल नहीं हो रही है। अगर उस बरसाल के पानी को उठाकर कहीं और नहर में डाल दिया जाए तो सारे पानी में प्वायजन हो जाता है जिससे फसलें

और तबाह हो जाएंगी। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जुलाई की बरसात आने से पहले पहले क्या ड्रेनज की खुदाई करवा के उनको चालू कर दिया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मौजूदा स्कीम से पहले एक और स्कीम बनाई गई थी जो फल्ड वाटर को ड्रेन आउट करने की स्कीम थी लेकिन उसको जब दोबारा ऐग्जामिन किया गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यह फल्ड वाटर की प्रौब्लम नहीं है। इस इलाके में जो पानी इकट्ठा हो गया है, वह सलाईन वाटर है और इस वाटर को हम उठाकर नई स्कीम के तहत पम्प करके, जो चैनल वहां से गुजरती है, उसमें डालेंगे। यह ऐसा इलाका है जो कि वेरियस चैनलज से मिला हुआ है उस एरिया में वाटर लौगिंग हो गई हैं। वहां का जो वाअर स्लाइन है उसको टैस्ट भी करवाया गया है। टैस्टिंग से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन वाअर को अगर हम रनिंग चैनलज में डालेंगे तो उससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी ई.सी. वगैरह भी टैस्ट की गई है। फसलों को कोई नुक्सान नहीं होगा और जो जमीन तबाह हुई है वह भी बच जाएगी।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के कुछ गांव समूह ऐसे हैं कि जहां पानी खारा है और भूमिगत जल स्तर भी काफी नीचा है। वहां बरसात न होने की स्थिति में किसी प्रकार की कोई पैदावार नहीं हो पाती। रेवाड़ी के आसपास जैसे 10–12 गांवों का समूह है और इसी तरह से माजरा श्योजरा में भी

10–12 गांवों का समूह है जहां पानी खारा है। क्या इन गांवों की सुविधा के लिए राज्य सरकार कोई विशेश सिंचाई योजना बनाने का विचार रखती है जिससे कि इस इलाके के लोगों को राहत मिल सके।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से हरियाणा प्रान्त का आधे से ज्यादा एरिया ऐसा है जहां का जल स्तर नीचा है और पानी खारा है और इसके लिए जो मौजूदा इरीगेशन का सिस्टम है, वह तो है ही, लेकिन एस.वाई.एल. का पानी मिलने के बाद ही उस एरिया के लिए हम वाटर की डिस्ट्रिब्यूशन कर पाएंगे, करेंगे। यह फिलहाल हमारी स्कीम हैं।

Buses purchased by Haryana Roadways

***456. Sh. Surinder Kumar Madan**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state –

(a) the number of buses purchased by the Government during the period from January, 1987 to December, 1987;

(b) the number of buses, out of those referred to in part (a) above allotted to each depot separately; and

(c) whether, there are any such depots in the State which have not, so far been provided with Video Coaches togetherwith the time by which these are likely to be provided there?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह):

(क) जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1987 तक 393 बसें खरीदी गई।

(ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई जोकि सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) हां, वीडियों बसें उन आगारों को दी गई हैं जो उन मार्गों के अन्तिम छोर पर स्थित हैं जिन पर ये चलती हैं। इन बसों के चलाने के जब अन्य नए मार्गों की पहचान हो जाएगी तब ऐसी बसें उन आगारों को उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा, जिन्हें अब ये नहीं जुटाई गई हैं।

अनुबन्ध

वर्श 1987 में हरियाणा राज्य परिवहन के विभिन्नय डिपुओं में बसों के वितरण का विवरणः–

डिपो	बसों का वितरण
चण्डीगढ़	21
करनाल	20
कैथल	18
जीन्द	36
यमुनानगर	23

सोनीपत	22
अम्बाला	24
हिसार	41
फरीदाबाद	25
रिवाड़ी	39
गुड़गावां	19
रोहतक	44
भिवानी	33
दिल्ली	5
सिरसा	23
	393

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, बसों की अलाटमैंट के बारे में जो लिस्ट दी गई है उनके अन्दर कैथल डिपो को 18 बसें, गुडगांवा डिपों को 19 बसें और दिल्ली डिपो को 5 बसें दी गई बताई गई हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन डिपुओं को इतनी कम बसें क्यों अलौट

की गई हैं और डिपुओं को बसें अलौट करने का क्या क्राइटेरिया है? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन डिपुओं को ज्यादा बसें अलौट की गई हैं उनमें से किन–किन डिपुओं के अन्दर घाटा है?

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगा कि जिन डिपोज में ज्यादा बसें दी गई हैं वे रिप्लेसमैंट के कारण दी गई हैं। जो बस 6 लाख किलोमीटर बच लेती है या 8 साल पूरे कर लेती है उस बस को रिप्लेस कर दिया जाता है। जिन जिन डिपोज में बसों की ज्यादा रिप्लेसमैंट की गई है उन डिपोज में बसों की संख्या ज्यादा है और जिनमें रिप्लेसमैंट कम की गई हैं उनमें संख्या कम है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि जनवरी 1987 से दिसम्बर 1987 तक 393 बसें खरीदी गई हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले जनवरी, 1987 से लेकर जून, 1987 के आखिर तक कितनी बसें खरीदी गई और पहली जुलाई, 1987 से दिसम्बर, 1987 तक कितनी बसें खरीदी गई?

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल यानी जनवरी, 1987 से मार्च, 1987 तक हमने 96 बसें खरीदी और बाकी की 257 बसे नए साल में खरीदी हैं।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, अभी मत्री जी ने बताया कि जिन–जिन डिपोज में ज्यादा बसें अलौट की गई हैं वे डैमेज्ड बसों की रिप्लेसमैंट के कारणा की गई हैं। हिसार डिपो सभी डिपोज से बसों में डौमिनेट करता है क्योंकि पिछले 7–8 साल से चौ. भजन लाल चीफ मिनिस्टर रहे जिसकी वजह से हिसार डिपो में बसें ज्यादा दी गई। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या रिप्लेसमैंट औफ बसिज का क्राइटेरिया वही रखा जाएगा यह उसको चेंज किया जायेगा।

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिसार जिले में से ही सिरसा और भिवानी जिले बनाए गए हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सिरसा जिले के साथ कांग्रेस राज में केवल रोडवेज डिपार्टमैंट से संबंधित ही नहीं बल्कि सभी महकमों से संबंधित मामालों में भेद भाव बरता गया है क्योंकि वह जिला चौ. देवी लाल जी का गृह जिला है। इसके आलवा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिन बसों का टाईम पूरा हो जाता है उन्हीं बसों को रिप्लेस किया जाता है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हू कि बसिज परचेज करने के लिए जो परचेज कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी के मैम्बर कौन कौन महानुभाव थे?

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, यह हाई पावड कमेटी होती है और चेयरमैन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं और उस

परचेज कमेटी में मैम्बर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, कंसर्न्ड डिपार्टमैंट के मिनिस्टर और बाकी सैक्रेटरीज वगैरह होते हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है कि उस हाई पावर्ड कमेटी में से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को हआ दिया गया? अगर हटा दिया गया तो क्यों हटा दिया गया?

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने हाई पावर्ड परचेज कमेटी के बारे में पूछा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस परचेज कमेटी को वाई डैजिगनेशन जो भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होता था वह प्रिजाइड किया करता था। किसी भी मंत्री को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उस कमेटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री जी हैं और उसके मैम्बर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पहले भी थे और अब भी हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने यह बात इसलिए पूछी थी क्योंकि इस बारे में अखबारों में छपा था। To keep the record straight, I wanted to know about it.

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सोनीपत के लिए विडीओ कोच चलाने का सरकार का विचार है?

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, इस बारे में मैंने अपने जवाब के भाग 'ग' में अच्छी तरह से बताया हुआ है। माननीय सदस्य उसको ध्यान से पढ़ें।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, पिछले दिनों अखबार में एक स्टेटमैंअ आई थी कि जितने भी हरियाणा रोडवेज के डिपोज हैं उन सभी से वीडियों कोच बसिज चलाई जायेंगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैथल डिपो को इस सुविधा से वंचित क्यो रखा जा रहा है।

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, भिवानी और हिसार की तरफ जाने वाली वीडियो बसें वाया कैथल ही गुजरती है।

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डीलक्स कोचिज के लिए कितने वीडियीज खरीदे गए हैं और खरीदे गए वीडियोज में से आमतौर पर कितने खराब रहते हैं।

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, अब तक जितने भी वीडियोज खरीदे गए हैं उनके बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि वे खराब रहते हैं। दूसरे घटिया वीडियोज खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कंडम बसों को रिप्लेस करने का क्या तरीका है और कितने दिनों बाद एक बस को कंडम माना जाता है? क्या एक एक बस को नीलाम किया जाता है या बसें 'बल्क' में यानि इकट्ठी नीलाम की जाती है?

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, जो बस 8 साल में 6 लाख कि.मी. चल चुकी होती है उसको हम कंडम घोशित करते हैं। अब डिपो वाईज बसों को नीलाम किया जाता है। एक बार सरकार ने यह सोचा था कि केवल 2 स्थानों से ही बसें नीलाम की जायें परन्तु यह सोच कर इस फैसले को बदल दिया कि इससे नीलामी देने वाले लोगों को अधिक परेशान होगी।

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रत्येक डीपो से कितनी बसें वीडियो कोच चलाई जा रही हैं?

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर साहब, करनाल, अम्बाला, रोहतक, कैथल, सोनीपत, जीन्द और फरीदाबाद डिपोज से वीडियों कोचिज बसें नहीं चलाई जा रहीं बाकी सभी डिपोज से वीडियो बसें चलाई जा रही हैं।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो वीडियो कोचिज बसें चण्डीगढ़ से दिल्ली चलाई जा रही हैं और जो वीडियों बसें चण्डीगढ़ से सिरसा की तरफ

चलाई जा रही है क्या उनकी सुविधाओं में कोई अन्तर है? दूसरे क्या इनके किराये में भी कोई फर्क है?

श्री धर्मबीर सिंह: किराये में अन्तर जरूर है। साधारण बस से इन बसों में डेढ़ गुणा किराया अधिक लिया जाता है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि क्या इन दोनों स्थानों की तरफ जाने वाली वीडियों कोचिज की सुविधाओं में कोई अन्तर है, इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई अन्तर नहीं है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, हर डिपो से जब वीडियो कोचिज बसें चलाई जा रही हैं तो करनाल डिपो से वीडियों बस नहीं चलाई जा रही, इसका क्या कारण है?

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि करनाल, अम्बाला और कुछ दूसरे ऐसे डिपो हैं जो नैशनल हाई वे पर पड़ते हैं। इन डिपोज में दूसरे डिपोज की वीडियो बसिज गुजरती हैं इसलिए वहां से वीडियो कोच नहीं चलाई जा रही है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि वर्श 1987 के अन्दर 393 नई बसें खरीदी गई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुड़गांव डिपो को आने वाले वर्श में कितनी नई बसें दी जायेंगी?

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आने वाले वर्श में 300 नई बसें रिप्लेसमैंट होने वाली बसों के अलावा खरीद रहे हैं।

जिस डिपो का जितनी बसों की जरूरत होगी उस हिसाब से उस डिपो को नई बसें ही जाएंगी।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोयद से जानना चाहता हूं कि जो पिछले वर्श 393 बसें खरीदी गई हैं कौन कौन सी कम्पनीज से खरीदी गई हैं?

श्री धर्मबीर सिंह: हमने ये बसें टाटा और लीलैन्ड कम्पनी से खरीदी हैं। ये दो ही सप्लायर्ज हैं।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कंडम बसों की नीलामी की जाती है क्या वह 'बल्क' में की जाती है या एक एक बस की नीलामी की जाती है? मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों रिवाड़ी में 23 बसें एक साथ ही नीलाम की गई जिसके कारण बहुत से इच्छुक लोगों को बसें खरीदने का मौका ही नहीं मिल पाया।

श्री धर्मबीर सिंह: एक एक बस की नीलामी करते हैं। श्री रघु यादव जी ने ही यह बात बतायी है कि इकट्ठी नीलामी की नई हैं। जहां तक रिवाड़ी में बसों की नीलामी का सम्बन्ध हैं वहां नीलामी में बसें पहले कम कीमत में जाती थीं लेकिन इस बार ज्यादा कीमत पर गई हैं।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा सरकार वीडियो

कोच बसों में हरियाणा पब्लिक रिलेशन विभाग द्वारा हरियाणा की अचीवमैंट और डिवैल्पमैंट के बारे में तैयार की हुई फिल्में और हरियाणवी फिल्मों को दिखाने के बारे में विचार करेंगी?

श्री धर्मबीर सिंह: इस बारे में सोचा जाएगा।

श्री सरदूल सिंह: स्पीकर साहब जो बसें चण्डीगढ़ से चलती हैं वे कुछ ऐसे अड्डों पर खड़ी होती हैं जो रोडवेज के नहीं हैं और न ही वहां पर सरकार की दुकानें हैं। वे ड्राईवर और कन्डवर की मर्जी से खड़ी हैं। होटल वाले मन–मर्जी के रेट सवारियों से चार्ज करते हैं। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ताकि यात्रियों को न लूटा जाए?

श्री धर्मबीर सिंह: हमारी बसें ज्यादातर बस स्टैंडज पर ही खड़ी होती हैं, वहां दुकानों पर रेट लिस्ट भी लगी होती है। यह पिछली कांग्रेस सरकार के टाईम में परम्परा रही है कि बसों को ड्राईवर और कन्डक्टर अन–अथोराइज्ड अड्डों पर रोक लेते थे। जहां से भी शिकायत आयेंगी हम ऐक्शन लेंगे।

श्री देवी दास: स्पीकर सर, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि करनाल और कैथल डिपो से वीडियों कोच बस चलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां से दूसरे डिपोज की बसें आती हैं। सोनीपत से सोनीपत डिपो की या किसी और डिपो का वीडियों कोच बस या डीलैक्स बस नहीं आती है इसलिए मैं मंत्री

महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सोनीपत से भी वीडियों कोच बस, डीलैक्स या सैमीडीलैक्स बस चलाने का विचार है?

श्री धर्मबीर सिंह: हम इसको ऐग्जामिन करवा करके कोशिश करेंगे कि वहां से भी चलायी जाये।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, करनाल की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए क्या वहां पर लोकस बस चलाने का सरकार का विचार है?

श्री धर्मबीर सिंह: लोगों की डिमांड को देखते हुए आप लिख कर दे दें। हम जरूर चलायेंगे।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर साहब ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि हरियाणवी फिल्म और लोक सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की गई फिल्म दिखाने के बारे में सोचा जायेगा। स्पीकर साहब, हमारे पहले से चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी जो आजकल किसी पब्लिक ऐन्टरप्राइज के चेयरमैंन हैं, ने भी एक फिल्म में हीरो का रोल अदा किया था। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वह फिल्म भी दिखायी जायेगी? (हंसी) (इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री महा सिंह: स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने कहा कि सोनीपत से डीलक्स बस चलाने के मामले को ऐग्जामिन कराया जायेगा। इस बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि

डीलक्स बस चलाने का क्या क्राईटेरिया है, इसे कितने दिनों में ऐग्जामिन करा लिया जायेगा, तथा कितने दिनों तक बस चला दी जायेगी?

श्री धर्मबीर सिंह: स्पीकर सर, जैसे ही डिमांड आयेगी, विचार कर लिया जायेगा। डीलक्स बस का दुगुना किराया है और सैमी–डीलक्स का डयोढ़ा किराया है। जिस क्षेत्र के लोग किराया सहन कर सकते हैं, वहां बस जरूर चलायेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि डीलक्स या साधारण बस चलाने से पहले उसकी सफाई कराई जाती है?

श्री धर्मबीर सिंह: सफाई तो होती है। (इस समय बहुत से सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए)।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल पर अब और कोई सप्लीमैंटरी नहीं होगा। क्योंकि इस पर पहले ही 20 मिनट डिस्कशन हो चुकी है।

B.K. Hospital and E.S.I. Hospital, N.I.T. Faridabad

***317. Sh. Kundan Lal Bhatia**: Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the number of

doctors and the provision of equipments, medicines etc. in B.K. Hospital and E.S.I. Hospital at N.I.T. Faridabad; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialise?

स्वास्थ्य एवम् आयुर्वेद मंत्री: (श्रीमती कमला वर्मा)

(क)	(i)	बी.के. अस्पताल, फरीदाबाद	नहीं
	(ii)	ई.एस.आई. अस्पताल, एन.आई.टी. फरीदाबाद में	जी हां
(ख)	(i)	बी.के. अस्पताल, फरीदाबाद	प्रश्न ही नहीं उठता।
	(ii)	ई.एस.आई. अस्पताल, एन.आई.टी. फरीदाबाद में	डाक्टरज कर्मचारी राज्य बीमा व निगम से स्वीकृती उपकरण प्राप्त होने के पश्चात्। दवाईयां धन राशि उपलब्ध होने पर।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: अध्यक्ष महोदय, बी.के. अस्पताल, फरीदाबाद का निर्माण 30–35 वर्श पहले हुआ था जब

इस शहर की आबादी लगभग 30 हजार थी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या फरीदाबाद शहर की आबादी के अनुपात में इस अस्पताल को बढ़ाने का कोई विचार है या नहीं?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष जी, बी.के. अस्पताल, फरीदाबाद 200 बिस्तर का अस्पताल है जो कि इस समय चल रहा है। इसके अतिरिक्त 200 बिस्तर का एक ई.एस.आई. अस्पताल अलग से चल रहा है। अभी इन अस्पतालों की ऐक्सपैंशन करने का कोई विचार नहीं है। बी.के. अस्पताल के भवन के लिए ज्यों ही जगह उपलब्ध हो जाएगी इसमें नया भवन बनाने के बारे में विचार कर लिय जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, ई.एस.आई. अस्पताल व डिस्पैंसरिया बनाने के लिए 90 प्रतिशत रकम ई.एस. आई.सी. द्वारा दी जाती है और हरियाणा सरकार को केवल अस्पताल व डिस्पैंसरी के लिए जगह ही उपलब्ध करवानी होती है। जगह उपलब्ध न करवा सकने के कारण पिछले 10–15 साल से ई. एस.आई. डिस्पैंसरियों का काम रूका हुआ है। 68 ई.एस.आई. डिस्पैंसरियां मन्जुरशुदा हैं जिन पर काम चालू नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या मजदूर कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम जल्दी से चालू करवाएंगी।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि कोई भी अस्पताल वे डिस्पेंसरी स्टेट गवर्नमैन्ट के कारण नहीं रूकी है। ई.एस.आई. स्कीम सैन्ट्रल स्पौन्सर्ड स्कीम है। इस समय इस स्कीम के अन्तर्गत हमारे राज्य में तीन अस्पताल तथा 68 डिस्पैन्सरियां चल रही है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हमारे पास भूमि उपलब्ध हो और हमने उस पर भवन न बनाया हो। सिर्फ बहादुरगढ़ में जमीन ली जानी है और ज्यों जी जमीन उपलब्ध हो जाएगी वहां पर भवन बना दिया जाएगा। ई.एस.आई. का अपना निर्माण विभाग सी.पी. डब्ल्यू. है। उसके माध्यम से ही सारा भवन निर्माण का काम कराया जाता है।

चौ. तैयब हुसैन: अध्यक्ष महोदय, बी.के. अस्पताल फरीदाबाद का नाम बादशाह खान यानी ''फ्रंटियर गांधी'' के नाम पर रखा गया है। जैसे की आपको मालूम है कि ''फ्रंटियर गांधी'' का निधन हो गया है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या ''फ्रंटियर गांधी'' की यादगार में इस अस्पताल को बड़ा और आधुनिकतम बनावाएंगे?

श्रीमती कमला वर्मा: जरूर बनवाएंगे। इस अस्पताल के लिए ली हुई जमीन झगड़े वाली जमीन है। इस जमीन पर एक गुरूद्वारा बना हुआ है और कुछ जगह पर झुग्गी वालों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। ज्यों ही रिहैबिलिटेशन डिपार्टमैंट वाले इस

जगह को क्लीयर कर देंगे इस अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री जगपाल सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि वर्श 1988–89 में किस–किस जगह अस्पताल, प्राथमिकता केन्द्र, सब–सैन्टर्ज आदि बनाए जाने हैं?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं स्थान तो नहीं बता सकती कि किस–किस जगह बनाए जाने हैं लेकिन इतना बता सकती हूं कि अगले साल बीस कम्युनिटी हैल्थ सैण्डर्ज बनाए जाने हैं जिनमें से अम्बाला में 2, भिवानी में 1, फरीदाबाद में 1, गुडगांव में 1, हिसार में 3, जीन्द में 2, करनाल में 2, कुरूक्षेत्र में 3, रोहतक में 3, और सोनीपत में 2 बनाए जाएंगे। इसी प्रकार 108 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओर 140 सब–सैण्टर्ज खोले जाने का प्रोविजन है। ये संस्थान जमीन की उपलब्धि और आवश्यकता को देखकर ही बनाए जाएंगे।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अपने एक उत्तर में कहा है कि दवाइयां धनराशि उपलब्ध होने पर उपलब्ध की जाएंगी। मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा कि इस बजट में इवाइयों के लिए कितनी राशि उपलब्ध है और फरीदाबाद के लिए कितनी राशि रखी गई है?

श्रीमती कमला वर्मा: दो करोड़ पचास लाख रूपये की राशि का प्रावधान इस बजट में दवाईयों के लिए रखा गया है। (व्यवधान) बी.के. अस्पताल, फरीदाबादके लगभग चार–पांच लाख रूपये की दवाइयां दी जाती रही हैं। इस साल फरीदाबाद अस्पताल के लिए 549630/– रूपये की दवाइयों का प्रावधान किया गया हैं।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इनके महकमें की तरफ से आज ही मुझे एक लैटर मिला है जिसके जरिए दर्शाया गया है कि एलनाबाद में हस्पताल के निर्माण के लिए जगह नहीं है। क्या मंत्री जी खुद देखकर नहीं आई थीं कि वहां पर दो–अढ़ाई एकड़ जगह पड़ी है? जहां रूरल डिस्पैंसरी बनी हुई हैं वहां पर हस्पताल बना दिया जाए। वहां के लोगों की यह मांग भी है?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ये 30 बैडिड कम्युनिटी हैल्थ सैंटर चाहते हैं। इस सैंटर के लिए हमें चार–पांच एकड़ जमीन चाहिए। जो जमीन ये बता रहे हैं यह केवल 7 कनाल और कुछ मरले है। वहां पर न रैजीडैंशियल क्वार्टर बन सकते हैं और न ही हस्पताल की बिल्डिंग बन सकती है। भागी राम जी जगह दिलवा दें तो हम हस्पताल का काम शुरू करवा देंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दवाइयां हस्पतालों में मुहैया की जाती हैं

वे ऐक्चुअली लोगों के हाथ में पहुंचती हैं या वहां के डाक्टर बेच जाते हैं। जैसे फूड एंड सप्लाइज मंत्री महोदया ने बताया था कि उन्होंने एक सब कमेटी बनाई हुई है क्या उसी तरह से ये भी एक सब कमेटी बनाएंगे ताकि दवाईयों को चैक किया जा सके?

श्रीमती कमला देवी: अध्यक्ष महोदय, पहले तो हमारे एम.एल.ए. साहेबान ही इन संस्थाओं में थोड़ा समय देकर व निगरानी रखकर सुधार कर सकते हैं फिर भी इस काम के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं ताकि हस्पतालों की मैनेजमैंट के अन्दर सुधार हो।

श्री बलबीर सिह चौधरी: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई ऐसी सर्वे करवाया है जिससे यह पता लगता हो कि जिन गांवों में हस्पतालों या प्राईमरी हैल्थ सैंटर की बहुत पहले जरूरत थी वहां पर वे अब तक भी नहीं बने हैं? क्या कोई ऐसी नौर्मज हैं जिससे यह पता चल सके कि कहां पर हस्पताल खोलना है और कहां पर प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोलना है?

श्रीमती कलमा वर्मा: अध्यक्ष महोदय, नौर्मज हमारे पहले ही बने हुए हैं। हम हर पांच मील की दूरी पर स्वास्थ्य सेवाल देना चाहते हैं। पांच हजार की आबादी के ऊपर हम एक सब सैंअर खोलते है। पहले एक लाख की आबादी पर एक स्वास्थ्य केन्द्र होता था अब वह तीस हजार की आबादी पर है इसी प्रकार से

आसपास के गांवों की आबादी को मिलाकर जहां पर एक लाख या एक लाख बीस हजार की आबादी हो वहां पर हम सी.एच.सी. खोलते हैं जिसमें पांच स्पैशल सर्विसिज दी जाती हैं। जैसे मैडिसिन, सर्जरी, बच्चों का स्पैशल डाक्टर, डैन्टल सर्जन और महिला रोग विशेशज्ञ। इस प्रकार पांच स्पैशल सर्विस देने के लिए एक लाख की आबादी पर 30 बैड का हस्पताल होगा। इसमें और सोचने की गुंजायश ही नहीं रह जाती।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने भागी राम जी से कहा कि आप जमीन उपलब्ध करवा दें तो हस्पताल बना देंगे। मैं राई हल्के की तरफ से दस, बीस या पचास एकड़ जमीन देने की औफर करता हूं। क्या मंत्री जी वहां पर हस्पताल बना देंगी?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अगर राई के आस पास कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं होगा तो वहां पर अवश्य बनाने का विचार किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, जिस वक्त ग्रामीण लोग हस्पतालों में जाते हैं उस वक्त लाइट नहीं होती और शाम को पांच बजे लाईट आती है। तो क्या हस्पतालों में हौट लाइन का प्रबन्ध करेंगे?

श्रीमती कमला वर्मा: यह तो मैं वीरेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करूंगी कि हस्पतालों में वे बिजली का प्रबन्ध पूरा रखें और वहां विघुत कट नहीं लगे।

श्री कुन्दर लाल भाटिया: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि फरीदाबाद हस्पताल में पांच लाख रूपए की दवाइयां दी गई। पिछली सरकार के टाईम पांच लाख रूपए की दवाइयां एन. आई.टी. को मिलती थीं लेकिन अब नहीं मिलतीं, इसका क्या कारण है?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, 549630 रूपए की दवाइयां फरीदाबाद हस्पताल को मिल चुकी हैं। ये कहते हैं कि एन.आई.टी. को अलग दवाइयां मिलती हैं, मेरे को तो कभी इस बात की शिकायत नहीं आई कि वहां दवाई नहीं मिल रही है। दवाई पहले ही वहां पर बहुत अधिक दी जा रही है।

10.00 बजे

श्री क्रान्ति प्रकाश भल्ला: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से एक बात जानना चाहता हूं। चंडीगढ़ के पास ही पंचकूला एक नया शहर बसने जा रहा है। वहां पर एक छोटी सी डिस्पैंसरी है। क्या सरकार वहां पर कोई अस्पताल बनाने के बारे में सोच रही है।

श्रीमी कमला वर्मा: जी हां यह विचाराधीन है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अभी मेरे एक साथी ने यह बताया कि जिस टाईम पर पेशैन्टस आते हैं, बिजली नहीं होती, बिजली की किल्लत रहती है। इसके अलावा चूंकि ऐक्सरे मशीनें अकसर खराब रहती हैं इसलिये गरीब आदमियों के ऐक्सरे फ्री नहीं हो पाते। क्या मंत्री जी बताएंगी कि अस्पताल के अन्दर ही कोई जनरेटर वगैरा का प्रबन्ध सरकार करेगी?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जनरेटर्ज से तो सारा अस्पताल का काम चल नहीं सकता चाहे हम कितना ही बड़ा हाई पावर का जनरेटर लगा लें, ऐक्स–रे यसा अन्य आप्रेशन थियेटर के काम नहीं चल सकते। फिर भी वही समस्या रहेगी क्योंकि जनरेटर अकसर खराब रहेगा। यह तो ऐमरजैंसी सर्विसज हैं। बिजली डिपार्टमैंट वाले भी अकसर जब कट लगात है तो उसे अस्पताल को एक्सक्लूड करके अस्पताल को बिजली दी जाती है। यह समस्या तो कहीं कहीं पर कभी ही आती है।

Setting up of Sub-Station in Radaur Constituency

***461. Sh. Rattan Lal Kataria**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state whether any new power sub-Stations in Radaur Constituency are proposed to be set up; if so, the places thereof and the time by which these are likely to be set up?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): हां। जठलाना तथा बबैन में 1990–91 तक।

श्री रतन लाल कटारिया: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या भूतपूर्व घोशणा मुख्यमंत्री महोदय ने रादौर हल्के में बरथली, गजलाना, नेहरा, और पालेवाला गांवों में जन सभाओं को सम्बोधित करते हुए कोई ऐसी घोशणा की थी कि रादौर हल्के में इन जगहों पर 33 के.वी.के सब–स्टेशन बनाये जायेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जहां तक भूतपूर्व घोशणा मुख्य मंत्री का सवाल है, उन्होंने तो हरियाणा में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर घोशणा ने की हो। वह घोशणा जबानी रह जाती थी, न उसका कोई रिकार्ड अवेलेबन है न कोई लेना है न कोई देना है। पत्थर आपको जरूर कहीं–कहीं पर मिल जायेंगे।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, बबैन के अन्दर आलरैडी एक पावर स्टेशन है जो 10 साल पहले का बना हुआ है उसको क्या 33 के.वी. से बढ़ाया जाएगा क्योंकि वहां पर वाटर लैवल 80 फुट नीचे चला गया। (व्यवधान व शोर) मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पावर स्टेशन का दर्जा बढ़ा कर इसको 66 के.वी. का बनाया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, बबैन में 33 के.वी. का सब–स्टेशन पहले से ही है। मौजूदा सब–स्टेशन को अपग्रेड करके 66 के.वी. का बनाया जायेगा। यह 1990–91 तक पूरा कर दिया जायेगा।

श्री जगपाल सिंह चौधरी: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि शहजादपुर जिला अम्बाला के लिए जो एक सब–स्टेशन मंजूर हुआ पड़ा है, वह कब तक मुकम्मल हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: अब आप देखिये कि कहां का सवाल कहां पर चला गया। सवाल का तो उसी जगह से सम्बन्धि रहने दो। थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाओ तो कोई बात नहीं। नैक्सट क्वैश्यन, प्लीज।

Dagging of Canals and Distributaries

***547. Sh. Harnam Singh**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to dig Ladwa and Shahbad Nalvi canals and their distributaries; and

(b) if so, the time by which the said work is likely to be started and completed?

Irrigation & Power Minister (Sh. Verender Singh):

(a) Yes.

(b) The schemes are yet to be cleared by the Central Water Commission and Planning Commission.

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय को यह अर्ज करना चाहता हूं कि 1985–90 का जो ऐप्रूव्ड प्लान है यह उसका एक हिस्सा है। उसके मुताबिक यह नहरें बननी हैं।

Mr. Speaker: This is not the way to put a supplementary. Comrade Sahib, you put the question.

श्री हरनाम सिंह: मैं मंत्री जी को यह दिखा दूंगा। क्या यह बात सही नहीं है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, जब तक सैन्ट्रल वाटर कमीशन और प्लानिंग कमीशन इन स्कीमों को क्लीयर नहीं कर देता तब तक अगर हम फंडज एलोकेट कर दें तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इनकी यह बात ठीक है कि उसमें 1985–90 तक जो जरूरी लिया होगा लेकिन एलोकेशन आफ फंडज करना तो तभी ठीक होगा जब इनकी क्लीयरैंस हो जाएगी। इन एंटीसिपेशन हमने लिख दिया होगा कि हमें क्लीयरैंस मिल जायेगी परन्तु हम क्लीयरैंस प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए। जब तक किसी काम की क्लीयरैंस नहीं मिल जाती, तब तक हम उस काम को शुरू नहीं कर सकते।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, माइनर्ज और नहरें कई इलाकों में से गुजरती हैं लेकिन कुछ इलाका ऐसा रह जाता है जिनको इनसे पानी नहीं मिलता। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनका सर्वे करवाकर, जहां माइनर्ज चल रहे हैं और नहरें चल रही हैं, क्या उन इलाके के लोगों को भी पानी मिलेगा जिनको पानी नहीं मिल रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अगर इनके हल्के में कोई समस्या इस प्रकार की है तो नोटिस में लाएं उसको हल करेंगे और जहां तक पानी दे सकेंगे पानी देंगे।

श्री जगपाल सिंह चौधरी: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लाडवा, शाहबाद नलवी कैनाल कहां से निकलेगा और कौन से इलाके को सैराव करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह नहर दादुपुर से निकलेगी और इन का इलाका तो बीच में आ ही जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रोजैक्ट को जल आयोग और प्लानिंग कमिशन से एप्रूव कराने के लिए इसी साल कार्यवाही की है या इससे पहले भी की है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, बहुत दिनों से कार्यवाही चल रही है। प्लानिंग कमिशन और सैंट्रल वाटर कमिशन के लोग यह कहते हैं कि आप लोग पहले रावी ब्यास का पानी जो एस. वाई.एल. को मिलता है उसकी ऐलोकेशन करवाइए उसके बाद फैसला होगा।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वह डा. हरनाम सिंह के सवाल से ही सम्बन्धित है। हमारे पास रिकार्ड है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट के सैवन्थ फाइव ईयर प्लान में इस प्रोजैक्ट को ऐप्रूवल मिल चुकी है। क्या मंत्री महोदय बताने

की कृपा करेंगे कि जो कुछ हम कह रहे हैं और जो कुछ जवाब दिया जा रहा है उसमें क्या कुछ अन्तर है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, डौकुमैंट बिल्कुल ऐप्रूवड है। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अभी स्कीम की एप्रूवल नहीं है। हर स्कीम की अलग ऐप्रूवल होती है।

श्री भागमल: स्पीकर साहब, जो नलवी नहर बननी है उसमें कई जगह पर रूकावटे आ रही हैं और कुछ शक्तिशाली लोग अलाइनमैंट को सीधा नहीं होने देते। क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है और क्या सरकार किसी के प्रभाव में नहीं आयेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चो. देवी लाल की सरकार तो सिकी के प्रभाव में नहीं आती केवल जनतार के प्रभाव में आती है। जहां तक शाहबाद नलवी नहर का ताल्लुक है, पांच किलोमीटर जमीन ऐक्वायर हो चुकी है। चौदह किलोमीटर लैग्थ के लिए सैक्शन चार और छः की कार्यवाही हो चुकी हे और बाकी जीरो आर.डी. से पांच किलोमीटर जमीन की ऐक्वीजीशन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वहां पर एक ओवर चैनल निकालने की प्रोपोजल हमारे अन्डर कंसीड्रेशन है जिससे थोड़ीा बहुत बिजली पैदा होने की गुंजाइश हो सके।

Consumption/Supply of Wheat in Mohindergarh District

***496. Sh. Kailash Chand Sharma**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state –

(a) the average monthly consumption of wheat in Mohindergarh District during the period from August, 1987 to February, 1988 togetherwith the quantity of wheat supplied for each month;

(b) the Warehouses/Godowns from which the wheat was taken for distribution in the said district during the said period; and

(c) whether there is any porposal under consideration of the Government to construct Godowns for Stroage of Wheat in the said District; if so, the places where these are proposed to be constructed?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुशमा स्वराज):

(क) और (ख): वांछित सूचना जो कि अनुबन्ध में दर्शाई गई है सदन के पटल पर रखी है।

(ग) नहीं।

महेन्द्रगढ़ जिला में जन वितरण प्रणाली के तहत अगस्त, 1987 से फरवरी 1988 तक 1955 टन की मासिक औसतन खपत रही है। मासिक जन वितरण प्रणाली के तहत गेहूं की मात्रा जो इस जिला को इस अवधि में अलाट की गई और उसके विरूद्ध जो मात्रा उठाई गई वह निम्न प्रकार से है:–

		(मात्रा टनों में)
मास	मात्रा जो अलाट की गई	मात्रा जो उठाई गई
8/87	1800	714.3
9/87	3500	1243.4
10/87	3500	305
11/87	3500	1518
12/87	3500	2693.4
1/88	3000	3000
2/88	4200	4200
	23000	13674.1

(ख) मास अगस्त, 1987 से फरवरी, 1988 तक जिन संस्थाओं/वेयरहाउस/गोदाम से जो जन वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं महेन्द्रगढ़ जिला में उठाया गया, उनके नाम निम्न प्रकार से हैं:—

खाद्य विभाग	हैफड	भारतीय खाद्य निगम	हरियाणा भन्डार गृह

			निगम
I-हेली मण्डी	हेली मण्डी	रिवाड़ी	हेली मण्डी
II-सफीदों	कैथल	पलवल	तावडू
III-हथीन	होडल	तावडू	पिगांव

श्री कैलाश चन्द शर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि नारनौल के डी.एफ.एस.सी. के खिलाफ टेलीफोन पर या रिटन में डी.सी. नारनौल की तरफ से कोई शिकायत आई है और अगर आई है तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, डी.एफ.एस.सी. नारनौल के खिलाफ हमारे दफतर में चूंकि कोई शिकायत नहीं आई इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री जगन नाथ: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि सैन्टर द्वारा हरियाणा का गेहूं का कोटा आधा करने के क्या कारण है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ जी ने जो सवाल पूछा है वह उचित है। वास्तव में भारत सरकार हरियाणा को तीस हजार टन गेहूं ऐलोकेट करती थी लेकिन हम उसको लिफ्ट नहीं कर पाते थे। दिसम्बर मास में हमारी मांग

ज्यादा बढ़ गई। मैं डिस्ट्रिक्ट से मांग की फिगर्ज कलैक्ट की थी और उसी बेसिज पर मांग ज्यादा आ गई। हमने भारत सरकार को कहा कि सूखे के कारण हमारी गेहूं की मांग ज्यादा बढ गई है इसलिए 30 हजार टन का जो कोटा है उसमें पन्द्रह हजार टन कोटा और बढ़ा दीजिए। उन्होंने उसको बढ़ाकर 45 हजार टन कर दिया। उस समय के खाद्य मंत्री से मैं स्वयं मिली थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हरियाणा को 45 हजार टन की ऐलोकेशन कर दी जाएगी लेकिन जब ऐलोकेट किया तो चालीस हजार टन ही किया। पांच हजार टन कम कर दिया। इसके बाद मार्च के महीने में अचानक 45 हजार टन के बजाए 20 हजार टन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमें यह देखकर बड़ा ही खेद हुआ। तब तक के खाद्या मंत्री भी बदल गये थे और उसके बाद आने वाले खाद्य मंत्री महोदय से मैं व्यक्तिगत रूप से मिली और मैंने कहा कि हमारी मार्च तक की ही तकलीफ है क्योंकि अप्रैल से हमारा नया गेहूं आना शुय हो जाएगा। हरियाणा सरप्लस स्टेट है। हरियाणा का गेहूं के मामले में सैन्टर पल में मेजर कंट्रीब्यूशन है। केवल एक महिने के लिये हमें ज्यादा गेंहू चाहिये, इसलिये आप हमारी इस तकलीफ पर क्यों नहीं ध्यान देते ? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ करूंगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमारा औरिजीनल कोटा बहाल करके 20 से 30 हजार कर दिया मगर मुझे रंज है कि केवल एक महिने के लिये हमने बढ़ा हुआ कोटा मांगा था उसको भी भारत सरकार ने नहीं माना और वह केवल 30 हजार का कोटा हमें दिया गया।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने की 16 तारीख को नवभारत टाईमज में एक न्यूज छपी थी। क्या वह न्यूज सरकार के नोटिस में है और उसके बारे में डी.सी. नारनौल ने भी जानकारी के लिये फूड एंड सप्लाईज के डायरैक्टर से कोई बातचीत की थी? क्या सरकार के नोटिस में यह बात भी है कि नहीं?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष जी, ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, जो गेहूं सरकार द्वारा उठाया गया था वह उन स्टेशनज से उठाया गया है जो कि रोडज से कनैक्टिड हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो स्टेशनज रेलवे से कनैक्टिड हैं उनसे गेहूं क्यों नहीं उठाया गया? क्या वे यह भी बताएगे कि रेलवे की बजाये रोडज से गेहूं उठाने में ज्यादा खर्चा आता है और उस के क्या कारण हैं?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि अपना गेहूं बहुत कम होता है इसलिये वहां से प्रक्योरमैंट भी कम होती है। वहां से हमेशा 2000 से कम कभी 1800 कभी 1700 टन की प्रक्योरमैंट होती है। उनके यहां कभी टेकऔफ भी नहीं होता क्योंकि कभी जरूरत भी नहीं पड़ती थी। इस साल सूखे के कारण विशेश परिस्थितियों में महेन्द्रगढ़ जिले से मांग बहुत बढ़ी हुई मिली और जो आस पास की जगहें थीं जिनकी ये रेलवे की बात

करते हैं, जो जगहें रेलवे से कुनैकटिड थीं, वहां से चूंकि हमें गुडगांव, नारनौल, फरीदाबाद और भिवानी तक गेहूं देना था इसलिए रेलवे और रोडज दोनों से ही हमें गेहूं भेजना पड़ा। इनके यहां से जो गेहूं हमने उठाया वह कुछ रोडज से सटे हुए गोदामों से ओर कुछ रेलवे से सटे हुए गोदामों से उठाया। इस समय ये सारे गोदाम खाली हो गये हैं। इस तरह से इन हालात को देखते हुए हम यह तहजीब नहीं रख सकते थे कि केवल रेलवे से सटे हुए गोदामों से ही गेहूं उठाया जाता और रोडज से सटे हुए गोदामों से गेहूं ने उठाते।

श्री जगपाल सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि रायपुर रानी क्षेत्र में सरकार द्वारा जो बढ़िया गेहूं बिक्री के लिये भेजा जाता है, वह उस इलाके के गांव में न बिक कर कहीं दूसरी जगहों पर ही बिक जाता है और गांव वाले उससे वंचित रह जाते हैं। उस गेहूं का रेट भी नया ही होता है। पुराने रेटस से वह गेहूं बेचा भी नहीं जाता है? इसके क्या कारण हैं।

श्रीमती सुशमा स्पराज: अध्यक्ष जी, भाई जगपाल जी ने पहली बार यह बात इस सदन में बताई हैं। आज से पहले कभी इन्होंने ऐसी बात मेरी नोटिस में नहीं लाई है। हमने गेहूं ऐलोकेट करने के लिये खासतौर से कमेटियों का गठन किया हुआ है क्योंकि इस बार सूखा था। अध्यक्ष जी आप भली भांति जानत हैं क्योंकि आपके पास यह विभाग रहा है कि पहले कभी गेहूं की

इतनी मांग नहीं आती थी। इस बार काफी ज्यादा ऐलोकेशन हमने करवाई। पिछले दो महीने के आंकड़े यदि आप देखें तो यह पता लग जाएगा। लिफटिंग भी हमने बहुत ज्यादा करवाई और गांव–गांव जो कर के हमने गेहूं बंटवाया है लेकिन किसी पर्टीकुलर गांव की अगर ये बात करते हैं तेा मेरे नोटिस में लाएं मैं देखलूगी कि गेहूं वहां क्यों नहीं बांटा गया। अगर कोई अधिकारी दोशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही विभाग करेगा।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा बांटी गई गेहूं बढ़िया किस्म की थी और डिपो होल्डर्ज ने वह गेहूं न बांट कर घटिया किस्म की गेहूं और आटा लोगों को दिया है। क्या ये बात सरकार के नोटिस में हैं? क्या ऐसी कोई शिकायत इनके पास आई है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष जी, बिल्कुल इस तरह की शिकायत हमें मिली क्योंकि इस बार पंजाब और हरियाणा के अन्दर रेन अफैकटिड व्हीट की औक्शन हुई थी और कुछ डिपो होल्डर्ज ने शायद वह व्हीट खरीदा था इसलिए हो सकात है कि हमारे बढ़िया गेहूं की बजााये उन डिपो होल्डर्ज ने घटिया किस्म का गेहूं वितरित यिका हो लेकिन जहां–जहां से हमें इस तरह कि शिकायत मिली वहां हमने डिपो होल्डर्ज के लाईसैन्स कैनसिल किये और मुकदमें भी दर्ज किये गये और उसके बाद खाद्या विभाग का जो बढ़िया गेहूं था, उसको बंटवाया भी गया।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, हरियाणा से एफ.सी.आई. को जो सैन्ट्रल पूल के लिए गेहूं जाता है उस गेहूं को उठाते समय एफ.सी.आई. के अधिकारीगण रिश्वत मांगते हैं और उस गेहूं को उठाने में डिले करते है जिससे हरियाणा के गेहूं को नुक्सान होता है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस करप्शन को खत्म करने के लिए कोई प्रावधान करने का कश्ट करेंगी।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, जिस रवायात का डा. महा सिंह जी ने जिक्र किया है वह बहुत पहले से चल रही थी। हालांकि एफ.सी.आई. गवर्नमैंट आफ इंडिया के नीचे है फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने खास तौर से चेयरमैन, एफ.सी.आई. के साथ मींटिग की। अभी पिछले दिनों एफ. सी.आई. के चेयरमैन मि. ब्रीका यहां आए थे। उस समय हमने यह बात उनके सामने रखी थी और हमने यह कहा था कि हमने अपने महकमें का भ्रश्टाचार हटाएंगे लेकिन आप बताएं कि एफ.सी.आई. के लोग जो इस तरह से रिश्वत मांगते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि यदि वे लोग इस तरह की रिश्वत लेते हैं तो मैं अपने लैवल पर इस बारे में इन्क्वयारी करके इस क्रप्शन को रोकूंगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एफ.सी.आई. वाल गेहूं उठाते समय रिश्वत मांगते हैं। इस बात को तो मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन

महेन्द्रगढ जिले में अगस्त से लेकर फरवरी तक जितनी गेहूं लिफ्ट हुई हैं उनमें कितनी वेरिएशन है और उसके क्या कारण रहे हैं? एफ.सी.आई. वाले नहीं बल्कि फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैंट के व्यक्ति डिपों होल्डर्ज को टाईम पर गेहूं नहीं देते जिसके कारण वहां पर गेंहू लिफट नही हो सकी। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस बारे में उन्होंने क्या ऐक्शन लिया है और दोशियों को क्या सजा दी है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, आर्य साहब की बात सही नहीं है। यह गेहूं की ऐलोकेशन में और लिफिंटग में वेरिएशन है यह एफ.सी.आई. के अधिकारियों के कारण या हमारे महकमें के अधिकारियों के कारण नहीं है। यह बड़ी जायज जिझासा है कि गेहूं की लिफिटग कम क्यों हुई? मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा में गेहूं सरप्लस है और जो गेहूं की केन्द्रीय दरें हैं जिस पर वे हमें देते हैं उसमें और बाजार भाव में कोई अन्तर नहीं था यानी दिसम्बर के महीने तक कोई अन्तर नहीं था उस समय केन्द्रीय दरें 195 रूपये प्रति क्विंटल थी जो हमने आगे भी इसी भाव पर दी और बाजार में भी उस समय 200 रूपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिकता था इसलिए उस दौरान कंज्यूमर्ज डिपो होल्डर्ज से गेहूं लेने की बजाय बाजार से लेते थे। लेकिन जब 11वें महीने में बाजार में गेहूं के दाम बढ़ने शुरू हुए तक कंज्यूमर्ज ने डिपो होल्डर्ज की तरफ झांकना शुरू किया। यह बात पहली बार की नहीं है। पिछले तमाम सालों में गेहूं की लिफिंटग

हमेशा कम रही है। मैंने सवाल के जवाब में बताया है कि 30 हजार क्विंटल की ऐलोकेशन के अगेंस्ट मुश्लिल से 7 या 8 हजार क्विंटल गेंहू लिफट होती थी। अगर ब्लैक में गेहूं बिकने की गुंजाइश होती तो महकमे के अधिकारी गेहूं ज्यादा लिफट करवाते। अगर गेहूं ज्यादा लिफट करवा दी जाए और बाजार में बिके नहीं तो ब्लैक कैसे होगी। जो वेरिएशन है वह इसलिए है कि डिपो पर गेहूं बिकता नहीं क्योंकि हरियाणा में सरप्लस होने के कारण जो केन्द्रीय इशू दरें हैं वही भाव बाजार में रहता है इसलिये कम लिफ्ट होती है। लेकिन बाजार में भाव ज्यादा होने से कंज्यूमर्ज डिपो होल्डर्ज की तरफ झांकने लगे जिसके कारण डिपोज से गेहूं लिफट होनी शुरू हुई। यह बिल्कुल कोई कारण नहीं है कि अधिकारियों के कारण गेहूं लिफट नहीं हुई।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, 1982–83 में एफ.सी. आई. ने रेन अफैक्टिड गेहूं ले लिया था। उस साल गेहूं का 10 परसैन्ट तक दाना खराब था परन्तु वह एफ.सी.आई. वालों ने ले लिया था लेकिन इस बार बहुत सी गेहूं को जिसका लगभग 5 परसैंअ से भी कम दाना खराब था वह उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें केन्द्रीय सरकार का हमारी वर्तमान सरकार को इस तरह से बदनाम करने का तो कोई मंशा नहीं है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, हमारी वर्तमान सरकार को बदनाम करने की मंशा भारत सरकार की हर योजना

में है लेकिन यह बात भी माननीय सदस्य की बिल्कुल सही है कि इस बार एफ.सी.आई. वालों ने रेन अफैक्टिड गेहूं नहीं लिया। हमने उनको बार बार यही कहा कि आपके गोदाम खाली पड़े हैं आप इस गेहूं को फर्स्ट ग्रेड में नहीं तो सैकिण्ड ग्रेड के माल के दाम दे करके उठा लें लेकिन उन्होंने फिर भी नही उठाया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जब पिछले दिनों चेयरमैन एफ.सी.आई. यहां पर आए थे तो उस समय यह सवाल उनके सामने रखा था कि आप यह गेहूं उठाओ क्योंकि आपके गोदाम खाली पड़े हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में पुनर्विचार करके आपको लैटर लिखेंगे। हो सकता है अब एफ.सी.आई. वाले जो बचा हुआ गेहूं है उसको उठा लें।

Conversion of 30 Bed Hospitals into 50 Bed Hospitals

***485. Dr. Brij Mohan**: Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) whether there is any proposal to convert 30 Bed Hospitals into 50 Bed Hospitals in the State; and

(b) if so, the time by which a decision in the matter is likely to be taken?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा. बृज मोहन: स्पीकर साहब, जहां पर 30 बैडस का हस्पताल है वहां पर शहरों में 5 डाक्टर्ज का नौर्म फिक्स है और गांवों में 3 डाक्टर्ज को नौर्म फिक्स है। यह नौर्मज बहुत पुराने फिक्स किए हुए हैं। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इस नौर्मज को अभी हाल में फिर से निर्धारित करने का विचार है?

श्रीमती कमला वर्मा: इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री भागमल: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर 10 बैडस का हस्पताल है या कम है जैसे सढौरा और बिलासपुर के अस्पताल हैं क्या वहां पर बैडस बढ़ाने का विचार है यानि उन अस्पतालों को 30 बैडज तक करने का विचार है? इन्होंने इस साल के बजट में तो 30 बैडज से 50 बैडज को हस्पताल बनाने का कोई प्रोविजन नहीं रखा है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को हर गांव यानि हर 5 कि.मी. तक ले जाना चाहती है। आपको जानकार यह खुशी होगी कि छठी पंचवर्शीय याहेना के अन्तर्गत सारे हरियाणा में कुल 1591 सब–सैंटर्ज 163 प्राईमरी हैल्थर सैंटर्ज और एक कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर खोला गया था। 7वीं योजना के तहत 776 सब–सैंटर्ज, 231 प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज और 50 कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर्ज खोलने का विचार है। हम अभी तक यानि 1988 तक 411 उप केन्द्र, 123 प्राईमरी हैल्थ सैन्टर और 30 कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर्ज खोल चुके हैं। अभी इस

योजना के खत्म होने में 2 वर्श का समय रहता है। बचे हुए 2 वर्श में हम अपना टारगैट पूरा कर देंगे। जहां तक इन्होंने सढ़ौरा और बिलासपुर में बड़े हौस्पिटल बनाने यानि उनका दर्जा बढ़ाने की बात की है उस सम्बन्ध में मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि वहां पर यदि भूमि उपलब्ध हुई तो उनका दर्जा अवश्य बढ़ाया जायेगा। सरकार का यह इरादा है कि स्थानों की जरूरत और इम्पोरटैन्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जायें और खोले गए सब सैन्टर या प्राईमरी हैल्थ सैंटर या कम्युनिटी हैल्थ सैंटर का दर्जा बढ़ाया जाये।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरे हल्के में शामली कलां एक बहुत बड़ा ग्राम है। यह गांव फोकस गांव भी है। यहां पर पहले एक प्राथमिक हैल्थ सैंटर खुला हुआ था लेकिन भजन लाल ने अपने समय में इसका दर्जा कम कर दिया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उसका दर्जा दुबारा फिर बढ़ाया जायेगा।

श्रीमती कमला वर्मा: जांच करने के बाद, आवश्यकता अनुसार दर्जा जरूर बढ़ाया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, लौहारू में एक पुराना 30 बैडज का हस्पताल है क्या वहां पर मंत्री महोदया का एक बैड भी बढ़ाने का इरादा है?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इनका हस्पताल 30 बैडज हस्पताल का जो नौर्म फिक्स किया हुआ है, उसमें आता है। इसलिए वहां पर अभी कोई बैड बढ़ाने का इरादा नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि टोहाना एक बड़ा कस्बा है। वहां पर काफी पुराना 30 बैडज का हस्पताल है। टोहाना से 70–80 किलोमीटर के फासले पर हिसार का हस्पताल पड़ता है और 100 किलोमीटर के करीब रोहतक का मैडिकल कालेज पड़ता है। टोहाना के आसपास कोई बड़ा हस्पताल न होने की वजह से क्या मंत्री जी बताएंगी कि टोहाना के 30 बैडज हस्पताल को अपग्रेड करने का कोई विचार है?

श्री कमला वर्मा: अभी कोई विचार नहीं है।

डा. बृज मोहन: क्या मंत्री जी बताएंगी कि जगाधरी के सिविल हस्पताल में कैजुअलटी सैन्टर खोलने का विचार है?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, इन्होंने इसके लिए कई बार कहा है। वहां पर काफी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं। जगाधरी एक इण्डस्ट्रीयल कम्पलैक्स होने के नाते वहां पर कैजुअलटी सैन्टर खोलने के लिए विचार किया जा सकता है।

Checking of unauthorised load in Dharuhera Sub-Division

***452@Ch. Tayyab Hussain, Sh. Balbir Pal Shah**: Will the Minister For Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether any checking of unauthorised load by HSEB staff was done in Dharuhera Sub Division during March 1986; and

(b) if so, the amount charged in the Sundry register togetherwith the amount, if any, recovered therefrom?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) 31294.09 रूपये की धन राशि चार्ज की गई थी जो वसूल की जा चुकी है।

चौ. तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह माना है कि सन् 1986 के दौरान धारूहेड़ा उप–मण्डल में अनाधिकृत भार की जांच की गई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड के अधिकारियों और मुलाजिमों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब से मौजूदा सरकार बनी है तब से चौ. तैयब हुसैन जी तीन बार इस किस्म का सवाल पूछ चुके हैं। पिछले सैशन में भी यह सवाल थे लेकिन ये बीमार पड़ गये थे। इस सैशन मे ंभी इस किस्म का सवाल दो बार आया है। एक बार पहले भी यह सवाल आ चुका है उस दिन ये मिस कर गये थे। आज यह सवाल उन अफसरों के खिलाफ ऐक्शन लेने के बारे में नहीं है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि उन

अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उनको सस्पैन्ड किया गया, चार्जशीट सर्व की गई। इनमें से दो को री–इनस्टेट कर दिया है लेकिन री–इनस्टेट करने का मतलब यह है कि उनके खिलाफ सीरियस ऐलीगेशनज नहीं हैं। उन्हें सस्पैन्ड हुए ज्यादा लम्बा अर्सा हो गया था इसलिए री–इनस्टेट कर दिया गया परन्तु उनके खिलाफ कार्यवाही चालू है। अगर वे दोशी है तो उन्हें बिल्कुल नहीं बक्शा जायेगा।

Strike/lock outs in Factories in Sonipat District

***481. Sh. Devi Dass**: Will the Minister to State for Cooperation be pleased to state –

(a) whether the Government is aware of the fact that the labourers of certain factories in District Sonipat are on strike and there is lock out in the said factories;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the names of such factories/industries where there is strike and lock out, separately togetherwith the number of labourers thereof on strike; and

(c) whether it is also a fact that the owners of the factories, as referred to in part (b) above, have suspended, dismissed or compulsory retired their labourers during the period from 1st January, 1987 to 1st March, 1988, if so, the names of such factories together with the number of such employees separately?

सहकारिता राज्य मंत्री (डा. रघुबीर सिंह):

(क) हां। दो कारखानों में श्रमिकों ने हड़ताल की हुई है और एक में स्टे इन स्ट्राइक है। सोनीपत जिला में किसी भी कारखानें में तालाबन्दी नहीं है।

(ख) निम्नलिखित कारखाने हड़ताल/स्टे–इन–स्ट्राइक से प्रभावित हैं:–

प्रभावित श्रमिकों की संख्या भी, प्रत्येक के सामने अंकित की जाती है:–

क्र.स.		कारखाना का नाम	प्रभावित श्रमिकों की संख्या
1		मिल्टन साईकिल इन्डस्ट्रीज लि. सोनीपत	610
2		हरियाणा वनस्पति एण्ड जनरल मिल्ज कुण्डली, सोनीपत	70
3		हरियाणा कण्डक्टर प्रा. लि. कुण्डली, सोनीपत	22
	(ग)	मिल्टन साईकिल इंडस्ट्रीज लि. सोनीपत तथा हरियाणा वनस्पति एंड जनरल मिल्ज,	

		कुण्डली सोनीपत प्रत्येक में 9–9 श्रमिक 1.1. 1987 से 1.3.1988 तक की अवधि के बीच निलम्बित किए हैं। उपरोक्त भाग (ख) में दंर्शाई किसी भी संस्था में उक्त समय दौरान कोई भी श्रमिक निश्कासित या जबरन सेवा निवृत्त नहीं किया है।

श्री देवी लाल: स्पीकर साहब, मंत्री महोद ने अपने जवाब में बताया है कि तीन फैक्टरियों में लगभग साल सौ मजदूर हड़ताल पर हैं और 1.1.1987 से 1.3.1988 तक दो फैक्टरियों के 9–9 मजदूरों को सस्पैन्ड किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन फैक्टरियों के नौ–नौ मजदूरों को काम पर लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? दूसरे मंत्री महोदय ने कहा है कि सोनीपत जिले में और कहीं पर भी कोई हड़ताल नहीं चल रही है। स्पीकर साहब, गैडौर, बी.एस.टी. में भी मजदूरों के साथ ज्यादती हुई है। वहां से मजदूरों को निकाला गया है। क्या सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी?

डा. रघुबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई सवाल मिला दिये हैं। एक तो उन्होंने तीन इंडस्ट्रीज की स्टेज पूछी है कि अब उनकी क्या हालत है? जहां तक मिल्टन साईकिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की हालत की बात है, उसमें सन्

1986 के अन्दर इंडस्ट्रीज डिसप्यूट एक्ट के सैक्शन 12(3) के तहत फाइनैंशियल मैटर्ज की सैटलमैंट हुई थी। वह सैटलमैंट दोनों पार्टीज पर बाईडिंग थी लेकिन इस बीच कुछ फाइनैन्शियल डिमाण्डज वर्कज की तरफ से आयी और वर्कज हड़ताल पर चले गए। उनमें से नौ लोगों को सस्पैंड किया गया। जहां तक डिपार्टमैंट की तरफ से सैटलमैंट का सवाल है वह मैच्योर होने पर ही स्टैप्स लिए जाते हैं। सस्पैंशन को डिपार्टमैंट लीगली तौर पर मैनेजमैंट को कोई ऐक्शन नहीं मानता।

Mr. Speaker: Hon. Members, question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Flights made by the State Government Aeroplanes

***350. Sh. Lachhman Singh Kamboj**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the names of places to which flights were made by the State Government Aeroplanes during the years 1985, 1986 and 1987 alongwiththe number of flights made by them at each place, separately, alongwith the yearwise expenditure incurred thereon; and

(b) the purpose for which each of the said flights was made?

Chief Minister (Ch. Devi Lal):

The requisite information regarding reply to parts (a) and (b) are laid on the table of the House in Annexure-I and II, respectively.

ANNEXURE I

Name of places to which flights were made during			No. of flights made at each place during			Expenditure incurred during		
1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
Ambala	Bhiwani	Ambala	3	5	2	3.46 lacs	7.16 lacs	8.27 lacs
Allahabad	Bikaner	Amritsar	1	1	5			
Bhiwani	Bombay	Adampur	2	1	2			
Banswara	Bareli	Allahabad	1	1	1			
Bhatinda	Bhopal	Bhiwani	1	2	9			
Chadigarh	Chandigarh	Bombay	84	61	7			
Delhi	Delhi	Bareli	82	59	1			
Hisar	Hisar	Bikaner	13	5	2			

Jodhpur	Indore	Chandigarh	1	1	116			
Jaipur	Jaipur	Delhi	3	1	102			
Karnal	Karnal	Dimapur	8	4	1			
Kulu	Lucknow	Gwalior	1	1	1			
Narnaul	Sirsa	Gauhati	2	1	1			
Pinjore	Sarsawa	Hisar	1	3	13			
Patiala		Jammu	1		1			
Sirsa		Jaipur	4		1			
Suratgarh		Karnal	1		8			
Udaipur		Ludhiana	1		2			
		Lucknow			1			
		Narnaul			3			

		Patna			4			
		Sirsa			17			
		Sarsawa			2			
		Suratgarh			1			
		Varanasi			1			

ANNEXURE II

Purpose of each Flight made during 1985, 1986 and 1987

Year 1985 (Total flights 210) Flights related to Delhi: 82		Year 1986 (Total flights 146) Flights related to Delhi: 59		Year 1987 (Total flights 304) Flights related to Delhi: 102	
Sr.	Purpose	Sr.	Purpose	Sr.	Purpose

No.		No.		No.	
1	C.M. & PSCM on board	1	C.M. on board	1	25 hours/15 days inspection of King Air C90A, at Delhi Flying Club.
2	C.M. on board	2	C.M. on board	2	50 hours/30 days inspection of King Air C90A, at Delhi Flying Club.
3	Aircraft positioned for C.M.	3	C.M. on board	3	Governor & Party on board
4	C.M. on board	4	Governor on board	4	Aircraft positioned for Governor.
5	Instrument Rating Test of Chief Executive Pilot.	5	C.M. on board	5	C.M. & Home Minister on board.
6	C.M. on board	6	Aircraft positioned for	6	Governor on board.

			C.M.		
7	Governor & C.M. on board	7	C.M. on board	7	25 hours/15 days inspection of King Air C90A, at Delhi Flying Club.
8	Aircraft positioned for C.M.	8	C.M. on board	8	Aircraft positioned for Governor.
9	C.M. on board	9	C.M. on board	9	C.M. on board
10	C.M. on baord & Ari Craft postioned at Safdarjung Airport for major overhauling by M/s Saraya Aviation (P) Ltd., Delhi	10	Governor on board	10	Revenue Minister Haryana on board.
11	Test flight of the Aircrafts after C. of A. renewal	11	C.M. on board	11	-do-
12	-do-	12	Union Minister of State	12	Home Minister on

			for Transport Mr. Rajesh Pilot on board.		board and 50 hours/30 days inspection of King Air C90A at Delhi Flying Club.
13	C.M. on board	13	C.M. on board	13	C.M. & Party on board.
14	Aircraft positioned for Sh. Arun Nehru, Union Minister of State for Power.	14	Aircraft positioned for Union Minister of State for Tourism Mr. H.K.L. Bhagat.	14	C.M. & F.M. Punjab on board.
15	Sh. Arun Nehru, Union Minister of State for Power on board.	15	C.M. & PSCM on board	15	Aircraft positioned for C.M. Punjab & Party.
16	Sh. Darbara Singh & Sh. Satpal Mittal (Both Members Parliament) on	16	Governor on board	16	For 25 hour/15 days inspection of King Air C90A at

	board				Delhi Flying Club.
17	C.M. on board	17	Aircraft positioned for Governor.	17	Governor Punjab on board
18	C.M. & Party on board	18	Aircraft positioned for PSCm.	18	C.M. on board
19	C.M. on board	19	PSCM on board	19	Governor & Party on board
20	Sh. Buta Singh, Union Minister for Agriculture on board.	20	C.M. on board	20	Ferry flight for 90days/150 hours inspection of aircraft at Delhi Flying Club.
21	-do-	21	Aircraft positioned for C.M.	21	C.M. & Party on board.
22	Aircraft positioned for C.M.	22	C.M. on board	22	Aircraft positioned for Governor

					Haryana.
23	C.M. on board	23	Ferry flight of new Aircraft King Air C90A.	23	PSCM on board.
24	C.M. & PSCM on board	24	Indstrument Rating Test.	24	Aircraft positioned for PSCM.
25	-do-	25	Check flight P.S.C.M. on board	25	IR Checks Wg Cdr. JS Gahlawat NDB & ILS Let down.
26	-do-	26	Aircraft positioned for 15 days inspection at Delhi Flying Club.	26	Aircraft positioned for C.M.
27	Aircraft positioned for C.M.	27	C.M. on board & Aircraft positioned for 30 days insepction.	27	Governor Punjab on Board.
28	C.M. & PSCM on board	28	Aircraft positioned at Delhi Flying Club for 15	28	Ferry flight

			days insepction.		
29	Aircraft positioned for C.M.	29	Governor, Punjab on board.	29	Aircraft positioned for C.M. Dy. PSCM on board.
30	Industries Minister & PSCM on board	30	Aircraft positioned for 30 days/50 hours inspection.	30	Ferry flight for 15days/25 hours inspection of King Air C90A at Delhi Flying Club.
31	C.M. & PSCM on board.	31	Aircraft positioned at Delhi Flying Club for 15 days/25 hrs. insepction.	31	C.M. on board.
32	C.M. on board.	32	Governor, Haryana on board.	32	Governor on board.
33	C.M. on board.	33	Aircraft positioned at Delhi Flying Club for	33	Irrigation and Power Minister on

			maintenance insepction.		board.
34	C.M. & PSCM on board.	34	Local test flight.	34	Aircraft positioned for Governor Haryana and for 30 days/50 hrs. insepction at Delhi Flying Club.
35	C.M. on board.	35	Local test flight.	35	C.M. on board.
36	-do-	36	Aircraft positioned at for Hou'be Governor Haryana.	36	Aircraft positioned for Governor, Haryana.
37	C.M. & PSCM on board.	37	Aircraft positioned at Delhi Flying Club for 15 days/25 hrs. insepction.	37	Governor Haryana on board and for 25hrs. /15days insepction of aircraft at Delhi Flying Club.

38	-do-	38	Aircraft positioned at for Hou'be Governor Haryana.	38	IR Test Flight-Local flight.
39	Sh. Shiv Shanker, M.P. on board	39	Hon'ble C.M. & Party on board.	39	Union Environment Minister on board.
40	C.M. & PSCM on board.	40	Hon'be Governor on board.	40	Local test flight.
41	C.M. on board.	41	Aircraft positioned for 50 hrs/30 days inspection at Delhi Flying Club.	41	Irrigation & Power Minister on board.
42	Aircraft positioned for CM at Delhi.	42	Hon'ble Governor on board.	42	Hon'ble Governor & Chief Secretary on board.
43	C.M. on board.	43	Aircraft positioned for Hon'ble Governor.	43	Ferry flight
44	Chief Secretary to Govt.	44	Governor Punjab on	44	Aircraft positioned

	Haryana board.		Board & 25 hours/15 days insepction of aricraft at Delhi Flyuing Club.		for C.M.
45	Aircraft positioned for PSCM.	45	Governor on board.	45	Ferry flight for inspection of Aircraft at Delhi Flying Club.
46	C.M. & PSCM on board.	46	Aircraft positioned for Governor, Haryana.	46	Local Test Flight after inspection.
47	Local flight at Safderjung	47	Governor Haryana and Party on board.	47	Local test flight for Compass Check.
48	C.M. on board.	48	Aircraft positioned for Governor, Haryana.	48	C.M. on board.
49	Aircraft positioned for C.M.	49	Aircraft positioned at Delhi Flying Club for 50	49	Aircraft positioned for Hon'ble

			hours/30days inspection.		Governor, Haryana.
50	C.M. on board.	50	Governor & Party on board.	50	Ferry flight for 50 hours /30 days inspection of aircraft at Delhi Flying Club.
51	Aircraft positioned for montly inspection.	51	Governor & Party on board.	51	C.M. on board.
52	C.M. & Transport Minister on board.	52	C.S. & F.S. & Party on board.	52	C.M. on board.
53	Aircraft positioned for Union Minister for Fertilizer Mr. Natwar Singh.	53	Aircraft positioned for Governor Haryana.	53	-do-
54	C.M. on board.	54	C.M. on board.	54	Ferry flight for 25 hours/15 days inspection of aircraft at Delhi

					Flying Club.
55	C.M. on board.	55	C.M. on board.	55	C.M. on board.
56	Aircraft positioned at Safdarjung Airpot for monthly inspection.	56	200 hours/180 days inspection of King Air C 90 A at Delhi Flying Club.	56	-do-
57	C.M. on board.	57	Governor Haryana on board.	57	Ferry flight for 50 hours /30 days inspection of aircraft at Delhi Flying Club.
58	Aircraft positioned for C.M.	58	Aircraft positioned for Sh. S.K. Mishra, IAS, Secy. Tourism Govt. of India.	58	C.M. on board.
59	Governor Haryana on	59	Sh. S.K. Mishra, IAS, Secy. Tourism Govt. of	59	C.M. on board.

	board.		India on board.		
60	C.M. on board.		**Flights related to Chandigarh-61**	60	Aircraft positioned for C.M.
61	Aircraft positioned for C.M.	1	Aircraft returned to the base empty.	61	Deputy C.M., C.S. & Home Secretary on board.
62	C.M. on board.	2	C.M., C.S. & PSCM on board.	62	Ferry flight for 15 days/25 hours inspection of aircraft at Delhi Flying Club.
63	Aircraft positioned for C.M.	3	Governor on board	63	C.M. on board.
64	C.M. on board.	4	Aircraft returned to base empty.	64	C.M. on board.
65	C.M. on board.	5	C.M. & PSCM on board.	65	C.M. on board.

66	Aircraft position for Sh. Natwar Singh, Union Minister for Fertilizer.	6	C.M. on board.	66	C.M. on board.
67	C.M. on board.	7	-do-	67	-do-
68	Aircraft positioned for C.M.	8	Governor on board	68	-do-
69	Aircraft positioned for Governor.	9	C.M. on board	69	-do-
70	C.M. on board.	10	Aircraft returned to base empty.	70	-do-
71	C.M. on board.	11	C.M. on board	71	Aircraft positioned for C.M.
72	Aircraft positioned for C.M.	12	PSCM on board	72	C.M. on board.
73	Aircraft positioned at Safdarjung Airport for C of A inspection.	13	C.M. on board	73	Secy. Tourism, Govt. of India & PSCM on board.

74	Aircraft positioned for C.M.	14	C.M. & PSCM on board	74	Governor on board
75	C.M. on board	15	Governor on board	75	Aircraft positioned for Governor.
76	C.M. on board.	16	Aircraft returned to base empty.	76	C.M. on board
77	C.M. on board.	17	C.M. on board	77	-do-
78	Industries Minister Haryana on board.	18	Governor on board	78	-do-
79	C.M. Punjab & F.M. Punjab on board.	19	PSCM on board	79	Governor on board
80	Aircraft positioned for C.M.	20	C.M. & PSCM on board	80	Dy. C.M. & IPM on board.
81	C.M. & PSCM on board	21	Aircraft returned to base empty.	81	Aircraft positioned for Governor.
82	Aircraft positioned for	22	Governor on board	82	C.M. on board.

	Governor.				
	Flights related to Chandigarh- 84	23	C.M. on board	83	-do-
1	C.M. & PSCM on board.	24	Ferry flight	84	Hon'ble Governor on board.
2	C.M. on board.	25	PSCM on board	85	C.M. on board.
3	C.M. & PSCM on board.	26	Ferry flight	86	Aircraft positioned for Hon'ble Governor Hayrana.
4	C.M. on board.	27	Local flight for checking aircraft and checking systems.	87	C.M. on board.
5	C.M. on board.	28	Ch. Bhajan Lal, MLA, ex-C.M. on board and Ferry flight	88	-do-

6	Aircraft positioned at Chandigarh for carrying out 25 hrs/15 days inspection schedule.	29	Local flight for checking aircraft and checking systems.	89	-do-
7	C.M. on board.	30	Ferry flight	90	Aircraft positioned for C.M.
8	C.M. on board.	31	Governor Punjab on board.	91	Aircraft positioned for Hon'ble Governor and 25 hours/15 days insepction of aircraft at Delhi Flying club.
9	Aircraft positioned at the base after the renewal of C. of A.	32	Ferry flight	92	Hon'ble Governor on board.
10	C.M. on board.	33	Local flight for checking aircraft and checking	93	C.M. on board.

			systems.		
11	Sh. Arun Nehru, Union Minister of State for Power on board.	34	Ch. Surinder Singh, M.P., PSCM & JSCA on board.	94	Aircraft positioned for Hon'ble Governor Haryana.
12	Aircraft returned to base empty.	35	Ferry flight	95	Aircraft positioned for C.M.
13	C.M. on board.	36	Governor on board.	96	Governor on board.
14	Aircraft returned to base empty.	37	Ferry flight	97	C.M. on board.
15	Aircraft returned to base empty.	38	Ferry flight after inspection and snag rectification.	98	-do-
16	C.M. & CS on board.	39	Governor on board.	99	Hon'ble Governor on board.
17	Aircraft returned to base	40	Ferry flight	100	C.M. on board and inspection of

	empty.				aircraft at Delhi Flying Club.
18	C.M. & Party on board.	41	Governor on board.	101	C.M. on board.
19	Aircraft returned to base empty.	42	C.M. Education Minister, & DIG (CID) on board.	102	Ferry flight after inspection of aircraft at Delhi Flying Club.
20	Aircraft returned to base empty.	43	Aircraft positioned for Hon'ble Governor Haryana.		**Flights related to Chandigarh- 116**
21	C.M. & PSCM on board.	44	C.M. & Party on board.	1	C.M. & PWD Minister on board.
22	C.M. on board.	45	Governor on board.	2	Local flight air test.
23	C.M. & PSCM on board.	46	Aircraft returned to base.	3	PSCM on board flying.

24	C.M. Industries Minister & P.W.D. Minister on board.	47	Governor, Punjab on board.	4	Ferry flight
25	C.M. & PSCM on board.	48	Aircraft positioned for C.M. and Party.	5	C.M. & Party on board.
26	Aircraft returned to base empty.	49	C.M., F.M. & Party on Board.	6	Ferry flight
27	CM on board.	50	Ferry flight	7	Ferry flight
28	-do-	51	Government, Haryana & Party on board.	8	-do-
29	PSCM on board.	52	Ferry flight	9	-do-
30	C.M. on board.	53	Government, Haryana & Party on board.	10	Governor, Punjab on board.
31	PSCM on board.	54	CS, FS & Party on board.	11	C.M. on board.
32	CM & PSCM on board.	55	Government, Haryana & Party on board.	12	Aircraft was to be positioned for

					Governor but returned to base due to bad weather.
33	C.M. on board.	56	Ferry flight	13	Governor on board.
34	-do-	57	C.M. on Board.	14	Ferry flight
35	CM & PSCM on board.	58	Ferry flight	15	-do-
36	CM on board.	59	-do-	16	Home Minister on board.
37	-do-	60	-do-	17	Governor on board.
38	CM & PSCM on board.	61	-do-	18	F.M. Punjab on board.
39	-do-		**Flights related to Karnal-4**	19	Governor Punjab on board.
40	-do-	1	Aircraft positioned for C.M.	20	C.M. & Party on board.

41	CM on board.	2	Mr. H.K.L. Bhagat on board.	21	Ferry flight
42	CM & PSCM on board.	3	C.M. & Home Secy. on board.	22	-do-
43	Air test the aircraft	4	C.M. & Party on board.	23	C.M. Punjab & F.M. Punjab on board.
44	CM on board.		**Flights related to Hisar-5**	24	Ferry flight
45	Aircraft returned to base empty.	1	C.M. on board.	25	C.M. & Party on board.
46	C.M. & C.S. on board.	2	-do-	26	-do-
47	P.S.C.M. on board.	3	Aircraft positioned for C.M.	27	Ferry flight
48	C.M. & P.S.C.M. on board.	4	C.M. & I.P.M. Haryana on board.	28	-do-

49	C.M. on board.	5	Sh. S.K. Mishra, IAS, Secy. Tourism, Govt. of India on board.	29	-do-
50	-do-		**Flights related to Bhiwan-5**	30	C.M. & Home Minister on board.
51	CM on board.	1	Aircraft positioned for C.M.	31	Ferry flight
52	C.M. & Excise & Taxation Minister on board.	2	PSCM on board.	32	-do-
53	Chief Secy. on board.	3	Local flight.	33	Governor, Punjab on barod
54	Aircraft returned to the base empty.	4	C.M. & Party on board.	34	Governor, Haryana on barod
55	C.M. & Transport Minister Minister on board.	5	IPM & Minister for Social Welfare, Haryana, on board.	35	PSCM on barod

56	Mr. Natvar Singh, Union Minister on board.		**Flight related to Sirsa-1**	36	IR Checks-Wg. Cdr. J.S. Gahlawat NDB & ILS Let down.
57	Governor on board.	1	Governor on board.	37	Ferry flight
58	Aircraft returned to the base empty.		**Flight related to Sarsawa-3**	38	Governor, Punjab on barod
59	C.M. PSCM on board.	1	C.M. on board.	39	-do-
60	CM on board.	2	Aircraft positioned for Union Minister of State for Transport, Mr. Rajesh Pilot.	40	Ferry flight
61	Aircraft returned to the base empty.	3	C.M. on board.	41	Local flight-IR test for Wg. Cdr. J.S. 4Gahlawat.
62	-do-		**Flight related to Bikaner-1**	42	Ferry flight for C. of A.

63	C.M. PSCM on board.	1	Aircraft positioned for C.M.	43	Ferry flight
64	C.M. PSCM on board.		**Flight related to Bombay-1**	44	C.M. & Party on board.
65	Governor on board.	1	Check flight.	45	Ferry flight
66	CM on board.		**Flight related to Jaipur-1**	46	PWD Minister on board.
67	-do-	1	Ferry flight. (Refuelling halt)	47	C.M. on board.
68	-do-		**Flight related to Lucknow-1**	48	Ferry flight
69	Aircraft returned to the base empty.	1	Governor Haryana on board.	49	IPM Haryana on board.
70	Governor on board.		**Flight related to Bareli-1**	50	Governor on board.

71	CM on board.	1	Hon'ble Governor on board.	51	Ferry flight
72	CM on board.		**Flight related to Bhopal-2**	52	Governor on board.
73	Sh. Natvar Singh, Union Minister for Fertilizer on board.	1	Hon'ble Governor, Haryana and Party on board.	53	-do-
74	CM on board.	2	-do-	54	Ferry flight.
75	Governor on board.		**Flight related to Indore-1**	55	-do-
76	CM on board.	1	Governor, Haryana and Party on board.	56	Ferry flight & Aircraft positioned for Hon'ble Governor Haryana.
77	Governor & CM on board.			57	C.M. on board.

78	CM on board.			58	C.S. on board.
79	-do-			59	Aircraft positioned for C.M. but returned back dur to bad weather.
80	Industries Minister, Haryana on board.			60	C.M. on board.
81	CM on board.			61	Ferry flight.
82	Aircraft returned to the base empty.			62	-do-
83	Local airtest			63	C.M. on board.
84	C.M. PSCM on board.			64	-do-
	Flights related to Hisar-13			65	IPM & Industries Minister on board.
1	C.M. on board.			66	C.M. on board.

2	-do-			67	F.M., H. Secy. & Director General of Police on board.
3	-do-			68	Ferry flight.
4	-do-			69	C.M. on board.
5	-do-			70	C.M. on board.
6	-do-			71	Ferry flight.
7	-do-			72	-do-
8	-do-			73	C.M. on board.
9	-do-			74	C.M. on board.
10	Governor on board.			75	-do-
11	C.M. on board.			76	Ferry flight.
12	Aircraft positioned for C.M.			77	DIB (CID) on board.

13	-do-			78	C.M. on board.
	Flights related to Karnal-8			79	-do-
1	Aircraft positioned for C.M.			80	-do-
2	-do-			81	Hon'be Governor & C.M. on board.
3	Aircraft positioned for C.M.			82	C.M. on board.
4	-do-			83	Aircraft positioned for Governor.
5	C.M. on board.			84	Governor on board.
6	-do-			85	Ferry flight.
7	Aircraft positioned for C.M.			86	PSCM on board.
8	C.M. on board.			87	Ferry flight.

	Flights related to Ambala-3			88	Governer on board.
1	Aircraft positioned for C.M.			89	C.M. on board.
2	C.M. & C.S. on board.			90	Governor on board.
3	Smt. Shakuntala Bhagwaria, Aircraft positioned for Industry Ministry, Haryana.			91	Local flight.
	Flights related to Sirsa-4			92	C.M. on board.
1	Governor on board.			93	Governor on board.
2	Aircraft positioned for C.M.			94	Ferry flight.
3	C.M. on board.			95	C.M. on board.
4	-do-			96	Ferry flight-ILS check.

	Flights related to Bhiwani-2			97	Ferry flight-ILS & IF check.
1	Governor on board.			98	Governor on board.
2	Governor on board.			99	C.M. on board.
	Flights related to Narnaul-2			100	Ferry flight.
1	Governor on board.			101	-do-
2	C.M. on board.			102	C.M. on board.
	Flights related to Suratgarh-1			103	-do-
	C.M. on board.			104	-do-
	Flights related to Jodhpur-1			105	Governor on board.
	Sh. Buta Singh, Union Agriculture Minister on			106	Ferry flight.

	board.				
	Flights related to Pinjore-1			107	C.M. on board.
	Trial landing at Civil Aerodrome, Pinjore.			108	Governor on board.
	Flights related to Udaipur-1			109	C.M. on board.
	C.M. Rajasthan on board.			110	Ferry flight.
	Flights related to Bansawara-1			111	C.M. on board.
	Aircraft positioned for C.M. Rajasthan.			112	Governor on board.
	Flights related to Jaipur-3			113	C.M. on board.
1	Mr. Shiv Shankar. M.P. on board.			114	Ferry flight.

2	Aircraft positioned for C.M. Rajasthan.			115	C.M. on board.
3	C.M. Rajasthan on board.			116	-do-
	Flights related to Kulu-1				
	C.M. & PSCM on board.				
	Flights related to Patiala-1				
	C.M. on board.				
	Flights related to Allahabad-1				
	C.M. on board.				
	Flights related to Bhatinda-1				
	C.M. & F.M. Punjab on				

	board.				
	Details of flights relating to year 1987 only.				
	Flights related to Ambala-2				
1	Governor on board.				
2	-do-				
	Flights related to Amritsar-5				
1	Governor, Punjab on board.				
2	Finance Minister Punjab on board.				
3	Governor Punjab and Party on board.				

4	Aircraft positioned for Governor, Punjab.				
5	-do-				
	Flights related to Karnal-8				
1	C.M. on board.				
2	-do-				
3	-do-				
4	-do-				
5	-do-				
6	Aircraft positioned for C.M.				
7	C.M. on board.				
8	-do-				

	Flights related to Sirsa-17				
1	Aircraft positioned for C.M.				
2	Revenue Minister, Haryana on board.				
3	C.M. and Party on board.				
4	C.M. on board.				
5	Aircraft positioned for C.M.				
6	C.M. on board.				
7	Aircraft positioned for C.M.				
8	C.M. on board.				
9	F.M. Home Secy. and Director General of Police on board.				

10	C.M. on board.				
11	-do-				
12	Aircraft positioned for C.M.				
13	C.M. on board.				
14	Secy. Tourism Government of Inida, on board.				
15	C.M. on board.				
16	Aircraft positioned for C.M.				
17	-do-				
	Flights related on Bhiwani-9				
1	C.M. on board.				
2	C.M. on board.				

3	-do-				
4	Minister of State for Railway on barod.				
5	C.M. on board.				
6	-do-				
7	Aircraft positioned for C.M.				
8	C.M. on board.				
9	Governor on board.				
	Fligth realted to Jammu-1				
	C.M. (J&K) on board.				
	Fligth realted to Narnaul-3				
1	C.M. on board.				

2	C.M. on board.				
3	Aircraft positioned for C.M.				
	Fligth realted to Gwaior-1				
	C.M. on board.				
	Fligth realted to Hisar-13				
1	C.M. & Party on board.				
2	Aircraft positioned for C.M.				
3	Aircraft positioned for C.M.				
4	C.M. & Party on board.				
5	Aircraft positioned for Union Environment & Forest Minister.				
6	C.M. on board.				

7	IPM & Industries Minister on board.				
8	Governor on board.				
9	Aircraft positioned for F.M., Home Secy. & Director General of police on board.				
10	C.M. on board.				
11	-do-				
12	Aircraft positioned for C.M.				
13	C.M. on board.				
	Flights related to Adampur-2				
1	Governor, Punjab on board.				
2	C.M. on board.				

	Flights related to Ludhiana-2				
1	Governor, Punjab on board.				
2	Governor, Punjab & Party on board.				
	Flights realted to Patna-4				
1	C.M. on board.				
2	-do-				
3	-do-				
4	-do-				
	Flights realted to Sarsawa-2				
1	Governor on board.				

2	C.M. on board.				
	Flights realted to Barailly-1				
1	Governor on board.				
	Flights realted to Dimapur-1				
1	C.M. on board.				
	Flights realted to Gauhati-1				
1	C.M. on board.				
	Flights realted to Bikaner-2				
1	C.M. on board.				
2	-do-				

	Flights realted to Bombay-1				
1	Ferry flight for C of A and FTD Check of Aircraft.				
2	C of A Test flight.				
3	Test flight.				
4	Ferry flight.				
5	-do-				
6	Test flight.				
7	Ferry flight.				
	Flights realted to Allahabad-1				
1	C.M. on board.				

`	**Flights realted to Varanasi-1**				
1	C.M. on board.				
	Flights realted to Lucknow-1				
1	C.M. on board.				
	Flights realted to Jaipur-1				
1	C.M. on board.				
	Flights realted to Suratgarh-1				
1	C.M. on board.				

Reservation in Class I & II Posts

***488. Sh. Jagan Nath**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposed under consideration of the Government to provide for reservation for Scheduled Castes/Barkward Classes employees in Class I and II category of posts in the State; and

(b) if not, the reasons there for?

मुख्य मंत्री (चौ. देवी लाल):

राज्य सरकार ने पहले ही श्रेणी I तथा II के पदों पर हरियाणा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षण किया हुआ है।

Connecting of Villages with Cooperative Sugar Mill, Jind

***540. Sh. Parma Nand**: Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state whether these is any proposal under consideration of the Government to connect Co-operative Sugar Mill, Jind with the following villages by road to check traffic hazard:-

(i) Abirka to Jhanjh Khurd;

(ii) Kandela to Jhanjh via Roopgarh Barodi;

(iii) Jalalpur to Jhanjh via Julani;

(iv) Julani to Jhanjha;

(v) Sangatpura to Jhanjh via Daryawala Mor; and

(vi) Rajpura to Sangatpura?

लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज): जी नहीं।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

15 मार्च, 1988 को भारत बंद में सम्मिलित होने के लिए आ रहे व्यक्तियों पर लाठीचार्ज करने सम्बन्धी

Mr. Speaker: I have received a notice of Calling Attention Motion No. 6 from Sarvshri Harnam Singh and Harpal Singh M.L.As. regarding lathi charge at dozens of places on the persons coming to attend Bharat Bundh on 15th March, 1988. I admit it. Sh. Harnam Singh may read his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter.

***श्री हरनाम सिंह तथा श्री हरपाल सिंह**: हम इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहते है कि देश की वामपंथी जनवादी व धर्म निरपेक्ष पार्टियों के केन्द्रीय सरकार के त्याग पत्र तथा भ्रश्टाचार और बेरोजगारी की वृद्धि के विरूद्ध मध्यावधि चुनाव कराने के लिये देश की एकता व अखण्डता के लिये राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां देने तथा आर्थिक संकट को दूर करने के लिये अपनी मांगों के सम्बन्ध में 15 मार्च की भारत बन्द की अपील की थी।

पुलिस ने दर्जनों स्थानों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया जो हरियाणा राज्य में 15 मार्च को बन्द करने के लिये अपील कर रहे थे। हजारों लोग गिरफतार किये गये तथा थानों में रखे गये। लड़कियों को पुलिस ने रोहतक थाने में पीटा। रानियां (सिरसा) थाने में भी पुलिस ने लोगों को पीटा, यहां तक कि कामरेड मक्खड सिंह, सचिव, राज्य परिशद सी.पी.आई. हरियाणा को पानीपत में पीटा। कामरेड रघुवीर सिंह हुड्डा, सचिव सी.पी. आई. (एस) राज्य समिति, हरियाणा के विरूद्ध झूठे मुकदमें बनाए गये हैं। यह विशय देश के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्धित है तथा हरियाणा पुलिस ने लोगों के अधिकारों का अपहरण किया है।

इसलिए, वे सरकार से निवेदन करते हैं कि इस विशय पर इस महान सदन में विचार किया जाए।

गृह मंत्री (प्रौ. सम्पत सिंह): बामपंथी, जनवादी तथा धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा केन्द्रीय सरकार के त्याग पत्र तथा नये मध्यावति चुनाव कराए जाने आदि की मांग को लेकर 15.3.88 के ''भारत बन्द'' आवाहन का हरियाणा में बहुत ही कम असर पड़ा। सभी जन उपयोगी सेवायें जैसे कि पानी व बिजली की सप्लाई, स्वास्थ्य सेवायें, संचार इत्यादि राज्य भर में सामान्य रहीं। बस तथा रेल सेवाये भी सामान्य रहीं सिवाये टोहाना (हिसार) व कुछ समय के लिये हिसार, जगाधरी, बिलासपुर (अम्बाला), पानीपत आदि स्थानों पर बस सेवाओं में बाधा पड़ी। लगभग सभी बैंक

कर्मचारियों (भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ कर) सार्वजनिक उद्योगों जैसे भारतीय इलैक्ट्रोनिक लिमिटिड पंचकूला (अम्बाला), इंडियन आयल डिपो अम्बाला छावनी, मारूति उद्योग गुड़गांव के कर्मचारियों ने हड़ताल की। एटक (सी.पी.आई.) तथा सीटू (सी.पी. आई.) वर्कर यूनियन से सम्बन्धित फरीदाबाद के सभी फैक्टरी वर्कर, गोपी चन्द टैक्सटाईल मिल सिरया, के.सी. टैक्सटाईल मिल जीन्द, शावलेस इलेक्सियर व जे.वी. मिल धारूहेड़ा (महेन्द्रगढ़) के वर्करों ने भी हड़पला की। कुछ दुकानें कुछ समय के लिये कालका (अम्बाला), करनाल, पानीपत, घरोन्डा, हिसार, हांसी, फरीदाबाद एंव टोहाना (हिसार) में बन्द रहीं।

भारत बंद के सम्बन्ध में निम्नलिखित 4 केस (2 रोहतक मे तगि 2 सिरसा में) दर्ज किये गये।

1. मुकदमा न. 187 दिनांक 15.3.88 धाराधीन 341/148/149/323 आई.पी.सी. थाना नहर रोहतक।

मोहन स्पिनिंग मिल रोहतक की एक मैटाडोर जो महिला कर्मचारियों को ले जा रही थी, मिल के रास्ते पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया। जिस के फलस्वरूप एक लड़की की आंख पर चोट लगी व कुछ अन्य को भी चोटें लगी। इस केस में 7 व्यक्तियों की गिरफतार कर लिया गया है।

2. मुकदमा न. 188 दिनांक 15.3.88 धाराधीन 148/149/341/506/153 आई.पी.सी. थाना शहर रोहतक।

का. रघुबीर सिंह हुड्डा, सी.पी.एम. तथा श्री उमेद सिंह भूतपूर्व विधायक के नेतृत्व में एक भीड़ बस स्टैण्ड रोहतक के गेट पर एकत्रित हो गई और बसों को रोका। उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों को जान से मारने व बसों को हानि पहुंचाने की धमकी दी यदि वे अपनी डयूटी पर गये। इस केस में 11 व्यक्तियों को गिरफतार किया गया जिन्हें दिनांक 16.3.88 को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों केा जमानत पर रिहा कर दिया।

3. मुकदमा न. 82 दिनांक 15.3.88 धाराधीन 3(1) प्रोटैक्शन आफ पब्लिक प्रापर्टी एक्ट 1948 तथा 426 आई.पी.सी. थाना रानियां जिला सिरसा।

यह केस श्री प्रेम सिंह, फारेस्ट अधिकारी रानियां की दरखासत पर दर्ज यिका गया है कि 15.3.88 को का. लक्षमण सिंह निवासी ननुआना, अजीत सिंह, हुक्म सिंह व गुरमीत सिंह इत्यादि ने बन्द के दौरान पेड़ काटे। सभी अभियुक्त दिनांक 16.3.88 को गिरफतार किये जा चुके हैं।

4. मुकदमा न. 67 दिनांक 15.3.88 धाराधीन 426 आई. पी.सी. तथा 3(1) प्रोटेक्शन आफ पब्लिक प्रापर्टी एक्ट 1984 था ऐलनाबाद जिला सिरसा।

यह केस श्री बलवन्त सिंह फोरेस्ट अधिकारी ऐलनाबाद की दरखास्त पर धर्मचन्द पुत्र राजा राम, निशान सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, गुरदीप सिंह पुत्र मान सिंह आदि 17 व्यक्तियों के विरूद्ध

बन्द दौरान पेड़ काटने के आरोप में दर्ज किया गया। सभी 17 व्यक्तियों को गिरफतार किया जा चुका है।

लड़कियों को रोहतक थाने में पीटने, लोगों की रानियां (सिरसा) थाने में पीटने तथा का. मक्खन सिंह को पानीपत में पीटने तथा का. रघुबीर सिंह हुड्डा सचिव, सी.पी.एम. के विरूद्ध झूठे केस बनाने के आरोप निराधान हैं। का. रघुबीर सिंह हुड्डा वास्तव में मुकदमा न. 188 दिनांक 15.3.88 धाराधीन 148/149/341/506/153 आई.पी.सी. थाना शहर रोहतक में संलिप्त था। इसके अलावा उसके विरूद्ध कोई अन्य केस दर्ज नहीं किया गया। स्थानीय पुलिस हिसार द्वारा शरारती तत्वों पर हल्का लाठी चार्ज किया गया जो हिसार रेलवे स्टेशन पर रिवाड़ी जाने वाली ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अन्य किसी स्थान पर पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया।

राज्य सरकार द्वारा विस्तृत प्रबन्ध करने की वजह से उक्त कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर बन्द शान्तिपूर्ण रहा।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा है उसके बारे मैं पहली अर्ज तो यह कहना चाहता हूं। *@ @ @ @ @ @ @ @ @*

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिए। आप तो प्रोसीजन को खत्म कर रहे हैं।

श्री हरनाम सिंहः मैं सप्लीमैंटरी पूछ रहा हूं। (शोर) इन्होंने कहा है .....

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछें। सवाल के अलावा और कोई बात रिकार्ड में नहीं आएगी।

श्री हरनाम सिंहः मेरे पास मैडिकल रिपोर्ट है * * * *

श्री अध्यक्षः यह कोई बात रिकार्ड नहीं की जाएगी। मैं सवाल के अलावा और बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। (शोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, डा. हरनाम सिंह तथा भाई हरपाल सिंह दो तीन बार सैशन में आ चुके हैं। हमारे बिजनैस के रूल्ज बने हुए हैं कि किस प्रकार से बिजनैस चलना चाहिए। इनको उन रूल्ज से अब तक वाकफियत हो जानी चाहिए थी। इनके काल अटैन्शन मोशन का जवाब गृह मन्त्री जी ने पढ़ दिया है। उसके पश्चात् ये केवल दो सवाल पूछ सकते हैं। इन्होंने अगर कोई बात कही है तो वह बिल्कुल गलत है और वह रिकार्ड से ऐक्सपंज होनी चाहिए।

Mr. Speaker: I will look into it.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने ब्यान दिया है, यह सही नहीं है। (शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: Comrade Sahib, you can put only relevant question. You are not to give speech.

कामरेड हरपाल सिंह: मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या रोहतक जिले के अन्दर मेहम हल्के की, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का हल्का है, दो लड़कियां बबीता और किरण को थाने में ले जाकर उनके गाऊ के सामने पीटा गया या नहीं? (व्यवधान व शोर)

Sh. Verender Singh: Speaker Sir, I think, he wants to stage a walk out.

काररेड हरपाल सिंह: अगर मंत्री महोदय अभी भी इस बात से इन्कार करते हैं तो क्या वह इस बात की जांच के लिए तैयार हैं? (व्यवधान व शोर)

Mr. Speaker: No interruptions please.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, क्या सरकार असैम्बली के मैम्बर्ज की कोई कमेटी बनाने के लिए तैयार है जो जाकर इस बात की इन्कवायरी करे कि सच्चाई क्या है? (व्यवधान व शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। किसी लड़की को किसी वक्त कहीं पर भी नहीं पीटा गया है। बहरहाल बात यह है कि हमारे साथी सी.पी.आई. और सी.पी. एम. से हैं। जब भारत बन्द की बात आई तो हर सदस्य यह जानता है और यह सदन भी जानता है कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय चौ. देवी लाल ने एक अपील की थी। 9 तारीख को सभी जानते हैं कि तकरीबन 30–40 लाख हरियाणा से और दूसरे सूबों से लोग केन्द्रीय सरकार के विरूद्धइ इकट्ठे होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ने क लिए दिल्ली पंहुचे थे। उस दिन सारा हरियाणा प्रदेश बन्द था। एक–एक दुकान बन्द थी। स्पीकर सर, उस सफल बन्द को सैबोटेज करने के लिए ताकि यह बात लोगों में आ जाए कि केन्द्र के विरूद्ध विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वे कमजोर हों, 15 तारीख को इन्होंने एक और बन्द रखा है। हामरी आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्पश्ट शब्दों में कह दिया था (व्यवधान व शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर सर, कामरेड हरपाल सिंह जी जिस किस्म से बीहेव कर रहे हैं उस तरह से इनको नहीं करना चाहिए चौ. देवी लाल जी की कृपा से ही ये असैम्बली में हैं। अगर यह ऐसा ही सोचते हैं तो इस्तीफा दे दें और दोबारा चुनाव लड़ लें। अगर पंचायत के भी मैम्बर बन जाएं तो कहना। इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। मेरा कहना यह है

कि है इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर आएं। (व्यवधान व शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल जी ने स्पश्ट कर दिया था कि ''9 ही काफी, 15 से माफी।'' जो बात चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने कही है, वह बिल्कुल ठीक और दुरूस्त है। इसी असैम्बली चुनाव के बाद म्यूनिस्पिल कमेटीज के इलैक्शन हुए थे। जिस टोहाना हल्के से ये चुनाव जीतकर आए हैं वहां के 30000 वोटों में से कामरेड साहब को 250 वोट भी नहीं मिले हैं। आज ये बड़ी–बड़ी बातें कर रहे हैं। (व्यवधान व शोर) .....

समितियों की रिपोर्टस पेश करना

(i) कमेटी औन पब्लिक अकाउन्टस की 26वीं ओर 27वीं रिपोर्टस

श्री अध्यक्ष: अब पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के चेयरमैन, श्री हीरा नन्द आर्य, कमेटी की वर्श 1987–88 के लिए 26वीं और 27वीं रिपोर्टस पेश करेंगे।

Sh. Hira Nand Arya (Chairman, Committee on Public Accounts): Sir, I beg to present the 26th & 27th Reprots of the Committee on Public Accounts for the year 1987-88 on –

(a) the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1982-83 (Civil and Revenue Receipts); and

(b) The Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1983-84.

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेरे कई मोशन्ज आपके पास पैंडिंग पड़े हुए हैं। कल मैंने एक प्रिविलेज मोशन भी दिया था जिसमें लिखा था कि आपकी शान के बारे में कुछ अखबार के मित्रों ने उल्आ–सीधा लिखा है।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, जीरो आवर खत्म हो चुका है। कल जब जीरो आवर आएगा तो प्यार से बात कर लेंगे।

श्री मंगल सैन: अब कौन सी दुश्मनी से बात कर रहे है? स्पीकर सर, एक मेरा लिबर्टी शूज फैक्टरी के बारे में काल अटैंशन मोशन था।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने तो जिन्दगी में प्यार किया ही नहीं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह काम तो इन्हीं के सुपुर्द कर रखा है खैर स्पीकर साहब, वहां पर बहुत कीमती जानें भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं सरकार को चाहिए कि उनके साथ कुछ बात करे।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, आपका मोशन रिजैक्ट हो गया है उसकी सूचना आपको भेज दी गई है।

(ii) कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की 27वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब चौ. शिव लाल, चेयरमैन, कमेटी औन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की वर्श 1987–88 के लिए 27वीं रिपोर्ट पेश करैंगे।

Ch. Shiv Lal (Chairman, Committee on Public Undertaking): Sir, I beg to present the Twenty Seventh Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1987-88, on the general working of Haryana State Industrial Development Corporation Limited.

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं.1) बिल, 1988

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 1988 को इंट्रोडयूस तथा कंसीडर करने की मोशन मूव करेंगे।

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (सं. 1) विधेयक, 1988 को प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विनियोग (सं. 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker: Question is –

That Scheduled be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बिल को पास करने का मोशन मूव करेंगे।

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाएं।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

वर्श 1988–89 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्श 1988–89 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर डिस्कशन होगी।

पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाइम बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज (सं. 1 से 25) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हों। डिस्कशन के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जायेंगी।

That a sum nto exceeding Rs. 10262000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a sum nto exceeding Rs. 257256000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

That a sum nto exceeding Rs. 677080000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum nto exceeding Rs. 129599000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum nto exceeding Rs. 68599000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum nto exceeding Rs. 322157000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum nto exceeding Rs. 521912000 for revenue expenditure and Rs. 4186000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum nto exceeding Rs. 538911000 for revenue expenditure and Rs 405775000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a sum nto exceeding Rs. 2166407000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum nto exceeding Rs. 1143799000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum nto exceeding Rs. 45416000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum nto exceeding Rs. 116041000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum nto exceeding Rs. 1119362000 for revenue expenditure and Rs. 17304000 for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum nto exceeding Rs. 34061000 for revenue expenditure and Rs. 1627786000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 14- Food and Supplies.

That a sum nto exceeding Rs. 1704217000 for revenue expenditure and Rs. 769482000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 15- Irrigation.

That a sum nto exceeding Rs. 129407000 for revenue expenditure and Rs. 26716000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum nto exceeding Rs. 528070000 for revenue expenditure and Rs. 18000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum nto exceeding Rs. 187618000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 18- Animal Husbandary.

That a sum nto exceeding Rs. 24260000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum nto exceeding Rs. 229099000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum nto exceeding Rs. 439030000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum nto exceeding Rs. 69235000 for revenue expenditure and Rs. 61756000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum nto exceeding Rs. 1164349000 for revenue expenditure and Rs. 144000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum nto exceeding Rs. 17235000 for revenue expenditure and Rs. 12200000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum nto exceeding Rs. 2220076000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, जनरल डिसकशन के दौरान काफी माननीय सदस्य अपने अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और उनका बड़े विस्तार के साथ जवाब भी दिया जा चुका है इसलिये अब मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है वे अब ज्यादा समय इन डिमांडज पर बोलने के लिये न लें।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी डिमांडज सदन के सम्मुख डिस्कशन के लिये रखी गई हैं। मैं उन पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो सरकार इस समय हरियाणा में है, वह जन कल्याण की नीतियां बना रही है अच्छे अच्छे कार्यक्रम घोशित कर ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े संघर्श के बाद हम लोगों ने इस देश के अन्दर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निर्वाचित सदस्य होते है वे जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ही नीतियों बनाते है और जनता के कल्याण के काम करते हैं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेज जब यहां पर राज करते थे और जब इस देश की जनता गुलाम थी, उस समय भी

अधिकारी जनता के सेवक कहलाते थे, उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता था और उन्हें यह कहलवाने में कोई शर्म या गुस्सा नहीं होता था लेकिन आज हम आजाद भारत में जो अधिकारीगण है, वे अपने आपको राजा महाराजाओं से कम नहीं समझते। अगर उन्हें 'पब्लिक सर्वेंट' कहा जाए तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, उन्हें बड़ी शर्म आती हैं। यह बड़े दु:ख की बात है। वर्तमान राज्य सरकार भ्रश्टाचार मिटाने के लिये जुटी हुई है लेकिन यह सच्चाई मुझे यहां पर कहनी पड़ रही है कि आज भीा इस लोकप्रिय सरकार के प्रयासें के बावजूद भी थानों में, तहसीलों में कचहरियों में रिश्वत के हाथ बहुत आगे बढ़े हुए हैं और जब तक इन रिश्वत के बढ़े हुए हाथों को काटा न जाएगा तब तक सरकार की घोशित नीतियों और योजनाओं से आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार सत्ता में आई थी उस समय प्रकृति का भयंकर प्रकोप इस प्रदेश के सिर पर मंडरा रहा था और राज्य को भयंकर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। मेरा क्षेत्र भयंकर सूखे की चपेट में था इस सम्बन्ध में मैंने 5 अगस्त 1987 को आदरणीय मुख्यमंत्री महादय से लिखित रूप में निवेदन भी किया था। अपने इलाके की सारी स्थिति ब्यान करते हुए उनसे कुद राहत कार्य करने की गुजारिश भी की थी। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों को राहत देने का कार्यक्रम शुरू करवायां दो सितम्बर, 1987 को स्वयं मुख्यमंत्री

महोदय सूखा पीड़ित क्षेत्रों में गये थे और 3 सितम्बर को हरियाणा के उस समय के राज्यपाल महोदय श्री एस.एस.सच. बर्नी भी महेन्द्रगढ़ जिले के दौरे पर गये। उसी दिन उन्होंने धारूहेड़ा टूरिस्ट कम्लैक्स में महेन्द्रगढ़ जिले के उच्च अधिकारियों को वहां बुलाकर इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया। उस समय जिला अधिकारियों ने राज्यपाल महोदय के सम्मुख सूखा राहत कार्यो के बड़े लम्बे चौड़े दावे प्रस्तुत किये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में नारनौल में स्थित एक अधीक्षक अभियन्ता श्री सुरेन्द्र कुमार उप्पल ने अपने पक्ष को दोहराते हुए बड़े जोर से राज्यपाल महोदय को बताया कि 25 अगस्त, 1987 तक हमने नारनौल उप–मण्डल में 104 जोहड़ों में से 92 जोहड़ों को नहर के पानी से भरवा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इतफाक से राज्यपाल महोदय और अधिकारीगण की उस बैठक में मैं भी मौजूद था।

श्री बनारसी दास गुप्त: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पर बोल रहा हूं और रेवैन्यू से संबंधित डिमांड पर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने 104 जोहड़ों में से 92 जोहड़ नहरी पानी से भरने का दावा किया था।

श्री बनारसी दास गुप्त: उपाध्यक्ष महोदय, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड में यह जोहड़ भरने वाली बात कहां पर आती है?

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पैसा लिया जा रहा है, इसका रेवैन्यू डिपार्टमैंअ में जो भ्रश्ट तंत्र बैठा है उसकी वजह से पीड़ित किसानों को और आम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए रेवैंन्यू की मांग पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस भ्रश्ट तंत्रों को ठीक करे।

श्री बनारसी दास गुप्त: उपाध्यक्ष महोदय, डिमांडज पर जो डिस्कशन होती है उस पर माननीय सदस्य जो बोलते हैं उसका स्कोप बड़ा लिमिटिड होता है। माननीय सदस्य श्री रघु यादव तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जनरल बजट पर बोल रहे हों। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि वे डिमांड के स्कोप में ही बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 4 जोकि रेवेन्यू के बारे में है उस पर बोल रहा हूं। इस डिपार्टमैंट का काम सूखा पीड़ित किसानों को राहत देना था। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो सूखा पीड़ित किसानों को राहत देना चाहती है लेकिन सूखा पीड़ितों को वांछित लाभ नहीं मिल सका है क्योंकि बीच में जो भ्रश्ट तंत्र हैं, वह रूकावट है। जो 104 जोहड़ों में से 92 जोहड़ नहरी पानी से भरने का दावा किया गया

था वह बिल्कुल असत्य था। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के सम्मुख उस मीटिंग में मैंने एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में यह मांग की थी कि उन 104 जोहड़ों में से 92 जोहड़ कौन से हैं, जो नहरी पानी से भरे गए हैं, मुझे उनकी सूचि दी जाए। मैं अपने खर्चे से उस बारे में इन्कवायरी करूंगा और इस इन्कवारी की सूचना राज्यपाल महोदय को दे दूंगा। राज्यपाल ने मुझे सूचियां देने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया। उपाध्यक्ष महोदय लोकतन्त्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचार–विमर्श से राज चलता है न कि नौकरशाही और अफसरशाही की मनमर्जी से। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के आदेश के बावजूद भी मुझे उन जोहड़ों की सूचि नहीं दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 16 अक्तूबर को ग्रिवेंसिज कमेटी की एक बैठक नारनौल में हुई थी। उस बैठक की अध्यक्षता माननीय पंचायत तथा विकास मंत्री कर रहे थे। उनकी अनुमति से मैंने फिर उन जोहड़ों की सूचि के बारे से सवाल उठाया तो उस सवाल का अधीक्षक अभिरून्ता (सिंचाई विभाग) ने ऐसा जवाब दिया कि शर्म से सिर झुक जाता है। उन्होंने कहा कि मौसम बड़ा खुश्क है और जमीन बड़ी ड्राई है। हम जो जोहड़ भरते हैं वे तीन दिन में ही सूख जाते हैं। आप क्या चैक करेंगे?

Mr. Deputy Speaker: Yadav ji, you are going out of the scope of the discussion. Do not waste the time of the House unnecessarily.

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस गम्भीर मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोद मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहात हूं कि माननीय सदस्य ने यह सारी बातें बजट की जनरल डिस्कशन पर बोलते हुए और गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए कही हुए कही हैं। इसलिए उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट करने से सदन का समय जाना करने के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं है।

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, इस समय मैं जो बातें कह रहा हूं इसके बारे में मैंने उस समय बोलते हुए एक भी शब्द नहीं कहा। आप रिकार्ड निकाल कर देख लैं। यदि मैंने ये बातें पहले कही हैं तो मैं अभी बैठने के लिए तैयार हूं। उस दिन तो मैं आपके आदेश से बीच में ही बैठ गया था। उपाध्यक्ष महोदय, उस चर्चा के दौरान मैंने उपायुक्त से कहा कि आपने केवल कागजों पर ही जोहड़ भरे हैं जमीन पर नहीं? आप मुझे यह बता दें कि आपने कौन से जोहड़ भरे हैं? उन्होंने कहा कि इस तरह से तो अफसरों की बेइज्जती हो रही है। एक जन–प्रतिनिधि को उन्होंने ऐसा जवाब दिया और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बैठक माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हो रही थी उस बैठक का वे अधिकारीगण बहिश्कार करके चले गए। उन्होंने एक जन–प्रतिनिधि के खिलाफ अनर्गल व झूठे लांछन लगाते हुए एक मिथ्या प्रस्ताव पारित किया और अखबार वालों को भेज दिया।

11.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार जो मजबूत है, वह इस तरह की गैर–जिम्मेदाराना बातों को और अनुशासनहीन व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अधिकारियों को इस तरह की बैठकें करने, अनर्गल प्रस्ताव पारित करने और उसे प्रैस में देने का उनके सेवा नियम इजाजत नहीं देते हैं। उन आफिसर्ज ने अपने सेवा नियमों का खुला उल्लंघन किया है और अनुशासनहीनता की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार की तरफ से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हां, मुझे एक कारण बताओ नोटिस जरूर दे दिया गया था जिसका मैंने समय पर ही जवाब भी दे दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के दौरान मैंने एक प्रश्न पूछा था कि नारनौल सब डिवीजन में 17 जून, 1987 से लेकर 25 अगस्त, 1987 तक कितने जोहड़ों को नहरी पानी से भरवाया गया था। जिन जोहड़ों को नहरी पानी से भरा गया है उनकी सूची मेरे पास है। पहले दावा किया गया था कि 104 जोहड़ो में से 92 जोहड़ भरवाए गए हैं लेकिन मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 92 नहीं बल्कि 19 जोहड़ नहरी पानी से भरवाए गए हैं। राज्यपाल के सम्मुख सरासर असत्य बात कही गई। मेरा कहना यह है कि कहां तो अधिकारियों ने 104 में से 92 जोहड़ भरने की बात कही थी और कहां यहां एक अतारांकित प्रश्न के उतर में 104 जोहड़ों में से 19 जोहड़ भरे गए बताए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे

बड़ा भ्रश्टाचार, ढीलापन और असत्य बात क्या हो सकती है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो औफिसर ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री बनारसी दास गुप्त: औन ए 'प्वायंट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्य बिल्कुल इररैलवैंट बोल रहे हैं। इन बातों का डिमांडज से कोई संबंध नहीं है। यदि आप इन्हें इसी तरह बोलने के लिए आज्ञा देते रहेंगे तो इससे सदन का समय बेकार में बर्बाद होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन्हें कहें कि ये डिमांडज के स्कोप के अन्दर ही नियमों के अनुसार बोलें तेा अच्दा रहेगा।

श्री रघु यादव: मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बता रहा हूं कि आप तो घोशणाएं कर रहे हैं, जन कल्याण की योजनाएं बना रहे हैं लेकिन आप जिस व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, अगर उस व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचता तो इन योजनाओं और घोशणाओं का क्या लाभ है? आप कर हे हैं कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। मैं कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा। समय का सदुपयोग तो केवल आप ही करते हैं। आप कभी किसी तहसील में, कोर्ट में या किसी बिजली बोर्ड के औक्सि में या किसी दूसरे औफिस में जाकर तो देखिए कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं या सच बात कर रहा हूं। आज हर जगह रिश्वत का हाथ फैला हुआ है। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Yadav, this is not the procedure of the House. Please address the Chair.

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह है कि –

सच कहूं तो जग गया, झूठ कहूं तो रब।

कबिरा इस दुविधा में, जग रहे न रब।।

मैं झूठ बोल नहीं सकता। आप जैसा प्रतिश्ठित व्यक्ति जब सदन की अध्यक्षता कर रहा हो तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? इस हाउस में भी हमारे सामने वाले 'पोल' पर लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाये तो यहां स्पश्ट और सच बात कही जाये क्योंकि यहां न बोलने से या लगत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुश्य पाप का भागी बन जाता हे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाप का भागी बनना नहीं चाहता। हमारी सरकार जो योजनाएं चला रही है उन्ही के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन योजनाओं के क्रियान्वयन का कोई कारगर व ठोस तरीका होनी चाहिए। प्रश्न काल के दौरान यह बात उठी थी कि सूखा राजत के नाम पर जो कार्य हो रहे हैं उनका आम लोगों तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं? उनमें कोई भ्रश्टाचार तो नहीं हो रहा? इस बारें में सरकार कैसे कार्यवाही करती है? तो बताया गया कि हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारे अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को मैं भ्रश्ट नहीं बताता लेकिन जो अधिकारी अपने आपको 'पब्लिक सर्वेन्ट' कहलवाने में शर्म महसूस करते हैं, जिनकी कांग्रेस शासन के दौरान रिश्वत खाने की आदत पड़ गई है, उनके

बारे में मैं कहूंगा कि या तो रिश्वत को खत्म करिए या 'सेवा शुल्क को' कानूनी बना दीजिए ताकि जो करोड़ों रूपये रिश्वत के रूप में लोगों के लिए जाते हैं उसके आय कर से भी सरकार क्यों वंचित रहे? रिश्वत के 100 रूपये, 200 रूपये कोई ले तो उसकी रसीद काट कर लोगों को दे ताकि कम से कम सरकार भी इनकम टैक्स के जरिए फायदा तो उठा सके। उपाध्यक्ष महोदय मेरा यही निवेदन है कि ये जो डिमांड रखी गई हैं, बहुत अच्छी हैं। यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और करना भी चाहती है। इसमें कोई शक किसी को नहीं हो सकता, हर आदमी इसे महसूस भी कहता हे कि काम ठीक हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात वाइंड अप करते हुए यही कहूंगा कि सदन के पटल पर जो उत्तर आया है उससे साफ जाहिर है कि सूखा राहत के कामों में काफी गड़बड़ हुई है। यह भी सही है कि लोगों को राहत भी मिली है। उसके बावजूद कई जगह घोटाले हुए हैं, कई जगह भ्रश्टाचार हुआ है और कई जगह ढीलापन भी आया है। एक गलत प्रवृत्ति फैल गई है कि अगर किसी विभाग के अधिकारी पर कोई ऊंगली उठाई जाती है तो पूरा विभाग उसको बचाने की कोशिश में लग जाता हैं प्रतिश्ठा का सवाल बना लेता है। इसी तरह का सरकार का भी रवैया होता जा रहा है। अगर किसी पुलिस वाले ने ज्यादती की है, किसी अधिकारी ने ज्यादती की है या भ्रश्टाचार किया है तो सरकार सोचती है कि उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए वरना सरकार बदनाम हो जायेगी। यह तो कांग्रेस पार्टी की संस्कृति थी। लोक दल तो आम लोगों की पार्टी है। लोक दल

भ्रश्टाचार को मिटाने वाली पार्टी है। इसलिए हमने कांग्रेस राज में पनपी भ्रश्टाचार को मिटाने वाली पार्टी है। इसलिए हमने कांग्रेस राज में पनपी भ्रश्टाचार व भ्रश्ट लोगों को सरंक्षण देने की संस्कृति को खत्म करना है। हमें तो एक बात करनी है कि हमारे राज में जो अधिकारी ढील बरतेगे, भ्रश्टाचार करने के दोशी पाये जायेंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब प्रोफेसर सम्पत सिंह को हुड्डा की दो फाईलें नहीं दी गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो अधिकारियों को तुरन्त निलम्बिल कर दिया। मुझे बहुत खुशी हैं लेकिन मुझे जोहड़ों की लिस्ट बार–बार मांगने पर भी नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। अगर उसी समय उन अधिकारियों को निलम्बित कर देते तेा अच्छा होता। श्री सम्पत सिंह को फाईल न देने पर उन दो अधिकारियों को सस्पैन्ड कर दिया लेकिन राज्यपाल के आदेश के बावजूद मुझे जोहड़ों की लिस्ट न दैने पर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया, वे अधिकारी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं हुआ। यह दोहरा मापदण्ड क्यों?

''हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

वे कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती।''

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री मोहिन्द्र (रोहट): उपाध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री महोदय ने जो सन् 1988–89 का बजट पेश किया उनकी अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। उप–मुख्यमंत्री जी ने 22 मार्च को बजट रखा था उस पर भी काफी चच्र माननीय सदस्यों ने की और वह पास होने जा रहा है। हम सरकार के धन्यवादी हैं कि बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। दूसरे बजअ में जितना घाटा होगा उसे कर और राजस्व की बेहतर वसूली द्वारा तथा गेर–योजना खर्च में किफायत करके पूरा किया जायेगा। इससे बड़ी उपलब्धि सरकार की और क्या हो सकती है? अभी अनुदान मांगों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले मांग नम्बर 8 का जिक्र करना चाहता हूं। यह मांग भवन तथा सड़कों के सम्बन्ध में है। इस मांग के तहत जितना पैसा मांगा गया है, यह कम है। हरियाणा प्रदेश में और मेरे हल्के में कुछ सड़कें बनायी जानी हैं। अगर वह अनुदान की राशि कुछ अधिक रखी जाती तो मेरे हिस्से में भी कुछ पैसा अधिक आ जाता।

अब मैं डिमान्ड 9 जो शिक्षा के बारे में है। इसके विशय में भी कुछ कहना चाहता हूं। इस डिमांड के लिए भी और अधिक धन जोड़ा जाना चाहिए था। देहातों में स्कूलों की छतें नहीं है और भी दूसरी काफी सुविधायें नहीं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए। मैं चाहूगा कि सदन इस बारे में विचार कर लें।

मांग संख्या 12 श्रम तथा रोजगार के बारे में है। आप जानते हैं कि सारा हिन्दुस्तान एक ही फिलास्फी पर चलता हैं और

वह फिलास्फी है अनेकता में एकता। यह केवल हरियाणा का ही जिक्र नहीं हैं, यह सारे हिन्दुस्तान की बात है। विभिन्न वर्गों और विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न भाशायें बोलते हुए रह रहे हैं और हमारा हिन्दुस्तान एक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात हरियाणा प्रान्त पर भी लागू होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मांग संख्या–12 का सम्बन्ध श्रम और रोजगार से है। रोजगार की मांग को इसलिए भी महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि 17 जून को जो चुनाव हुए उसमें मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों ने एक नया इतिहास लिखा है और अब इसी तरह से इस प्रदेश के यही नवयुवक हरियाणा के नव–निर्माण का इतिहास भी लिखना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सुविधाएं नौजवानों को दी गई हैं उन सुविधाओं में और योग किया जाए ओर रोजगार के अधिक साधन जुआए जाएं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13 के विशय में अपने विचार रखूंगा। पिछले सात साल तक चौ. भजन लाल का लूट तन्त्र इस प्रदेश में रहा। उसके बाद बीच में एक वर्श तानाशाही शासन के कारण जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का स्तर बहुत गिर गया था। लोगों की सुनवाई खत्म हो गई थी और हर ओर तानाशाही रवैया झलकता था। यह सरकार इसमें कितना सुधार कर पाई है

यह बात जानने के लिए माननीय सदस्यों और हाई आफिशियल्ज की एक सक्रीनिंग कमेटी बनाई जाए। इस सरकार ने भ्रश्टाचार बन्दर का नारा दिया है। हमें देखना चाहिए कि इस नारे को हम किस हद तक पूरा कर पाए हैं। क्या आज पटवारी ने लोगों से फर्द की कीमत में रिश्वल लेना बन्द कर दिया है या कम रिश्वत लेता है या तहसीलदारों ने इन्तकालों पर तथा रजिस्ट्रियों पर किसान को लूटना बन्द कर दिया है या कम किया है? पुलिस स्टेशन्ज में किस हद तक भ्रश्टाचार में कमी आई है। हरियाणा में यह सरकार आई है यह केवल दो पार्टियों की जीत के कारण नहीं आई बल्कि हरियाणा की जनता के पीसफुल जन–आन्दोलन और जन क्रान्ति के कारण आई है और इसमें सारे हरियाणा की जनता की कुर्बानी और शक्ति लगी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा भ्रश्टाचार का था और कहीं हरियाणा के हितों की बात भी साथ जुड़ी हुई थी। भजन लाल के शासन में एस.एस.एस. बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां बेची गई और प्रजातन्त्र पर बुरी तरह से कुल्हाड़ा चलाया गया तथा प्रजातन्त्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया गया। हरियाणा की जनता ने हरियाणा में दोबारा प्रजातन्त्र को बहाल करने के लिए और साथ ही साथ अपनी सुनवाई को कायम करने के लिए और हर मामले में हर कदम पर न्याय प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। इन कुर्बानियों से जो सरकार बनी है, जनता को इस सरकार से बहुत ज्यादा आशाएं हैं। हरियणा की हनता ने जितना बड़ा विश्वास इस सरकार पर किया है। दुनियां के तख्ते पर किसी पार्टी पर या किसी देश में नहीं

किया होगां इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इस सरकार को कुछ ऐसे क्रान्तिकारी पग उठाने चाहिए जिससे भ्रश्टाचार को कुचला जाएं मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि जब हमें हमारे अग्रवाल भाई, मारवाड़ी भाई जो कलकला की तरफ और बंगात की तरफ बिजनैश करते गए हैं और फैक्टरी एरिया में अपनी छोटी–छोटी दुकाने चलाते हैं, वे वहां की सरकार की इस बात के लिए वाह–वाही करते हैं कि बंगाल की सरकार ने वहां कानून और व्यवस्था का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया है। जहां सरमाएदार अपनी फैक्टरी चला रहे हैं, जहां मजदूरों को काम मिल रहा है उसके साथ साथ छोटे छोटे दुकानदारा और बिजनैस मैनज को सुरक्षा भी प्रदान है। वहां पर आज एक प्रकार से स्टैबिल्टी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम यहां पर इस बात की ढील न करें। यह जन क्रान्ति और इतनी बड़ी जीत दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुई जितनी हरियाणा में हुई। पहले क्या था? आप किसी मामले को ले लें चाहे प्लाटों का मामला हो, चाहे कस्टोडियन की जमीन हो उन्हें हड़प कर लिया जाता था। शहरों के अन्दर जहां कहीं भी इस तरह की जमीन पड़ी थी उस पर कब्जा कर लिया जाता था। इसी तरह से फतेहाबाद के अन्दर एक स्पीकर को लगाया गया और उससे चार हजार रूपए लिए गए। सिपाहियों की भर्ती के लिए सात–सात हजार रूपए लिए गए। इसी तरह से क्लर्को के मामले में हुआ। एक डाक्अर का किस्सा मुझे याद हैं। उससे पचास हजार रूपए मांगे गए। उसने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं बीस हजार रूपए से ज्यादा नहीं दे सकता। उसको दूसरी बात

बुलाया गया तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तीसरी बात फिर आखिर में बुलाया गया और कहा कि अच्छा बीस हजार रूपये ही दें दो। तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए क्रान्तिकारी पग उठाए जाने चाहिएं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, होम डिपार्टमैंट और रैवेन्यू डिपार्टमैंट के बारे में एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई जानी चाहिए जो सर्वे करे और जनता के प्रतिनिधियों को मिले। लोक दल, बी.जे.पी. तथा दूसरी पार्टियों के लोगौं को बुलाकर जगह जगह इस प्रकार से सर्वे किया जाए और पता किया जाए कि भ्रश्टाचार कितना कम हुआ हैं। इसके साथ साथ विधान सभा की भी एक अस्थाई समिति बनाई जाए। जैसे ऐन्टी क्रपशन कमेटी बनी हुई है। यह कमेटी ऐसे सुझाव दे ताकि रिश्वत लेने और दैने का मौका ही न मिले। मिसाल के तौर पर मैं सुझाव दूंगा कि पटवारी फर्द देने के लिए बहुत पैसे लेता है। इस काम के लिए सरकार पटवारियों को पहले ही तन्खाह देती है। मैं चाहता हूं जमाबन्दी और गिरदावरी दोनों का दोहरा रिकार्ड तैयार होना चाहिए। फर्द की कीमत को दोगुना करके इस काम के लिए दो पटवारी बिठाए जा सकते हैं और कापी कानूनगों के दफतर में रखी जा सकती है। जिस दिन कोई आदमी फर्द के लिए ऐप्लीकेशन दे उसके सात दिन बाद उसको मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार से उन लोगों को रिश्वत लेने का मौका नहीं मिलेगा। इन्तकाल के बारे में भी सबसे बड़ी लूट चलती है। इसके बारें में भी किसान यह कहे कि मैंने रजिस्ट्री करवाई है और एप्लीकेशन

के साथ उसकी नकल लगा दे तथा तहसीलदार को दे दें। ऐप्लीकेशन की दूसरी कापी पर तहसीलदार दस्तखत करे कि इस दिन उसे ऐप्लीकेशन रिसीव हुई है। उसके बाद दो महीने के अन्दर अन्दर इन्तकाल दर्ज हो जाना चाहिए।

अब मैं सरकार की उपलब्धियों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। हमारे हिसार में एक डी.सी. थे जो आज से दो महीने पहले बदल चुके हैं। उन्होंने अपने टाईम में पटवारी और तहसीलदार की मीटिंग बुलाई और एक दिन के लिए तहसीलदार को हैडक्वार्टर पर बिठा दिया। जितनी रजिस्ट्रीज उस दिन तक हुई थीं वे सारी क्लर्क से मंगवाकर पटवारी से कहा गया कि वह इन्हें तीन दिन के अन्दर अन्दर दर्ज करे। साथ में तहसीलदार को कहा गया कि सभी का इन्तकाल दस दिन में दर्ज होना चाहिए। इस तरह से जब तक हम व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तब तक यह जो करप्शन इंस्टीच्यूशनेलाईज हो गई है और लीगेलाईज हो गई है, इसको दूर नहीं कर सकते। इसके लिए विधान सभा की ऐसी कोई एक कमेटी बनाई जाये जो यह सुझाव दे कि भ्रश्टाचार को पनपने का मौका न मिले, किसी को पैसा लेने का मौका न मिले, किसी का शोशण करने का मौका न मिले और किसी की बेइज्जती करने का मौका न मिले। इस तरह की एक कमेटी विधान सभा की अवश्य बनाई जानी चाहिए। एक स्क्रूटिनी कमेटी विधायकों की और होनी चाहिए जो सब–डिवीजनल हैडक्वार्टर पर बने और सुझाव दे। उसकी महीने की एक निश्चित तिथि को जो

पहले से ही तय हो, एक मंत्री महोदय सारे की सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डी.सी., एस.पी. और जितने महकमों के अफसर हें, वह भी हों, की उपस्थिति में भ्रश्टाचार के बारे में शिकायतें सुने। इस तरह से उन लोगों को जिन लोगों ने उम्मीद की थी कि राज बदलने से उनको सुविधा होगी, कुछ हक तक सुविधा दी जा सकती है। चाहे वह पीने के पानी के बारे में हो, चाहे खेती में पानी न मिलने के बारे में हो, चाहे बिजली की पूरी सप्लाई न होने के कारण से हो, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाये कि हल्के का विधायक और सब–डिविजनल अफसर (सिविल) 6 महीने में कम से कम एक बार हर गांव में जाकर उन लोगों की तकलीफों को सुने ताकि हमने जो लोगों के साथ वायदे किये हैं वे पूरे किए जा सकें और उनकी जो भी तकलीफें हैं, वे दूर हो सकें। छोटे–छोटे काम या छोटे–छोटे तरक्की के काम जो हैं, वे गांव में ही हल किये जा सकें और वहीं पर उनकी व्यवस्था की जाये। कम से कम 6 महीने में एक बार अवश्य ही वहां पर जाकर उनकी तकलीफें सुनी जायें। गांव में तरक्की के लिये जो भी सबसे बड़ी असुविधा हो, उसको दूर करने के लिए कोई न कोई प्रबन्ध अवश्य ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाये कि कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय न हो। इसके लिये मैं एक और सुझाव दूंगा। गांव में शहरों के ठेकों की शराब बहुत जाती है। यह डिमांड न. 5 के बारे में मैं कह रहा हूं। पंचायत उस बारे में एतराज करती है। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि पुलिस

अफसर बड़ी–बड़ी मन्थली लेते हैं और गांव में खुले आम शहरों की शराब पहुंचती है, सरकार इसको रोकने का प्रबन्ध करे ताकि लोगों को यह विश्वास हो कि जिस प्रकार का राज उन्होंने चाहा था या मांगा था, उसी प्रकार का राज उनको मिल है। इसके साथ–साथ शहरी विकास के बारे में डिमांड न. 11 है। उस बारे में जो कानून हरियाणा के अन्दर पास हुआ था, वह 1971 में पास हुआ था कि कालोनाईजर्ज को रोक करके, हुड्डा बनाकर हरियाणा के अन्दर प्लान्ड डिवैल्पमैंट करने के लिये नक्शा बनाया गया था। आज हरियाणा के अन्दर उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। हर शहर के साथ–साथ कालोनाईजर्ज अन–प्लान्ड कालोनीज, अन–डिवेल्पड कालोनीज खुल्लमखुल्ला बना रहे हैं। यहां पर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अन्दर और दूसरे बड़े शहरों में भी ऐसा हो रहा है। दिल्ली जहां पर सैन्ट्रल सरकार का राज है, वह भी इसको रोक नहीं सकती है। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के कदम उठाने चाहिएं जिससे कि जो कानून लागू ही नहीं हो सका है, जिस कानून का हरियाणा को कोई फायदा नहीं हो सका उसके लिये कोई एक सब–कमेटी बनाकर इस बार में देखा जाये कि उसका कैसे फादया हो सकता है। क्यों न हुड्डा केवल विकास के लिए, रोडज बनाने के लिए ओर प्लानिंग आदि करने के लिए टाऊन एंड कंटरी प्लानिंग के साथ मिलकर लोगों को एक सुविधा दे। टाऊन एंड कन्ट्री प्लानिंग विभाग की एक स्कीम है जिसके तहत शहर के अन्दर एक एकड जमीन को प्लैन करके प्लाट बेचने का प्रावधान है। मेरा निवेदन है कि इस लिमिट को

बढ़ाकर 10 एकड़ और शहर के बाहर 50 एकड़ करके इस कानून को लिब्रेलाईज कर दिया जाए। पैसा चाहे लोगों का लगे, जनता का लगे या कालोनाईजर्ज का लगे लेकिन लोगों को सस्ते प्लाट मिलने चाहिए। हुड्डा की जो मौनोपली बनी हुई है, उस वजह से प्लौटस की प्राईसिज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस कारण लोगों की असुविधा बढ़ी है और गरीब लोगौं को जो सस्ते दर पर प्लौट मिलने चाहिए, वह उनको मिल नहीं पा रहे हैं। अगर उस कानून को जो चौधरी बंसी लाल के समय में बना था, देखा जाए तो पता लगता है कि केवल उससे भ्रश्टाचार बढ़ा है और लोगों की लूट बढ़ी है। इसके सिवा उस कानून से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि कालोनाईजर्ज डिपार्टमैंट में एक नया क्रान्किारी एक्ट बनाया जाए ताकि लोगों को सस्ते प्लाट मिल सकें और किसी को भी नाजायज पैसा बनाने का मौका न मिले। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर दो तरह के हरियाणा देखने को मिलते हैं। एक हरियाणा चण्डीगढ़ में है और बड़े शहरों में जैसे हिसार, करनाल और फरीदाबाद में हैं। यह मिनि हरियाणा है। दूसरा हरियाणा वह गरीब हरियाणा है जो गांवों मं बसता है। पिछले चालीस साल में केवल तीन साल को छोड़ कर, जब चौ. देवी लाल और डा. मंगल सैन का सांझा शासन आया था, यानि सैंतीस साल में हरियाणा के गांव में कोई तरक्की नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय पिछले 40 साल से सारे भारत में किसान, मजदूर और गांवों के लोगों की लूट चल रही है। लगातार उनसे सस्ता अनाज लेकर सरकार कारखानों में बना हुआ

मंहगा माल गांव के लोगों को दे रही है। पिछले चालीस साल से उन लोगों को लूटा जा रहा है। उनको केवल लूटा गया है लेकिन उनकी तरक्की कुछ भी नहीं हुई है। गांवों के अन्दर पीने का पानी नहीं पहुंचाया गया, वहां पर फ्लश सिस्टम नहीं है, गलियां पक्की नहीं है, कहीं पर पानी का निकास नहीं है और वहां काफी गन्दगी है। अगर गांवों की तरफ कोई ध्यान दिया जाता तो आज यह हालत गांवों की नहीं होती। मैं कहना चाहूंगा कि एक विलेज डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया जाए जिसका काम केवल गांवों का विकास करना हो। इस काम के लिए अलग से धन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वे पैसा केवल गावों की डिवैल्पमैंट पर ही लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट की मांग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चौ. साहब का लोगों को पैन्शन देने का एक क्रान्तिकारी कदम है। इस पैन्शन से उन बूढे लोगों का जिनका कोई सहारा नहीं था या जिनको घर में कोई पूछता नहीं था, अब आदर सत्कार मिलने लगा है। उपाध्यक्ष महोदय, विधवाओं को और अंगहीनों को पचास रूपए मासिक दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि इनको सौ रूपया प्रति माह मिलना चाहिए ताकि इस कड़ी मंइगाई में उनका गुजारा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने गल्त तरीके से पैन्शन ली थी उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया है लेकिन सरपंच और पटवारी जिन्होंने लोगों से मिलकर यह गल्त काम किया था उनके खिलाु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा कहना है

कि पटवारी और सरपंच के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उन लोगों को पैन्शन देने का सवाल है जो रह गए हैं उनके लिए एक परमानैन्ट सब कमेटी हर डिस्ट्रिक्अ हैडक्वार्टर पर बनाई जानी चाहिए। उस कमेटी में बी.डी. ओ., एस.डी.एम. और एस.एम.ओ. होना चाहिए। यह कमेटी उन लोगों की स्क्रीनिंग करे जो गल्त पैन्शन ले गए और जो रह गए हैं उनको पैन्शन देने की व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं होम डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। रास्ता रोको आन्दोलन में जो नौजवान शहीद हुए थे उनका नाम सड़कों के नाम पर रखकर कुछ करने की कोशिश की है। मेरा कहना है कि उन तीनों परिवारों के सदस्यों को सम्मानजनक नौकरी देना चाहिए ताकि उन लोगों को सहारा मिले जिनका हमेशा के लिए नुक्सान हुआ है। जिन नौजवानों ने अपने आपको शहीद कराया उनका नाम हमेशा के लिए रहना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी पिछले दिनों जो लोग शहीद हुए उनको सरकार ने पचार हजार रूपया दिया है और ऐसा करके हरियाणा की शान के लिए, आन के लिए खून देने वालों का सम्मान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, दरियापुर कांड के अन्दर 34 आदमी मारे गऐ थे। उनके निकट सम्बन्धियों को सरकार ने बीस हजार रूपया दिया था। उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का भी सरकार ने वाददा किया था। सरकार इस बारे में जांच करवाए कि कितने लोगों को अब तक नौरी दी गई है।

लालफीलाशाही के कारण कितने लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकी है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन अफसरों ने इन परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने में अड़चन डाली है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ओर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे कि वे भविश्य में इस प्रकार का रवैया न अपनाएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यहां हाउस के सामने यह कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को दिल्ली के अन्दर जो जन क्रांति हुई थी, वह हर लिहाज से सफल रही और भारत सरकार ने उस रैली को हर लिहाज से फेल करने की खेल खेली ताकि यह रैली सफल न हो सके परन्तु भारत सरकार अपनी इस चाल में सफल नहीं हो सकी और आज यह रैली सारे भारतवर्श के अन्दर बढ़ रही है। इन सभी बातों को सामने रखते हुए भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को सूखा राहत के लिए कोई इमददा नहीं की और हमारी सरकार ने अपने ही बल बूते पर लोगों की हर तरह से मदद की है और आगे भी कर रही है। भारत सरकार का जो इस सरकार को, उस रैली को, फेल करने का ाडयन्त्र था, वह कभी भी कामयाब नहीं होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि उस रैली में जो लोग शहीद हुए उनको 50–50 हजार रूपया दिया गया है, यह सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ–साथ जो सरकार ने वायदा किया था कि उन शहीदों

के हरेक घर से एक को नौकरी भी दी जाएगी इस तरफ सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों में किसी तरह की कोई उदासीनता न हो। जिन परिवारों को रैली की वजह से नुकसान हुआ है, उनकी तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिए ओर हर लिहाज से उन परिवारों की मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली की रैली में मरने वाले लोगौं को 50–50 हजार रूपए की राशि दी गई है, उसी तरह से दरियापुर हत्याकांड में मरने वालों के आश्रितों को भी 20–20 हजार रूपए के स्थान पर 50–50 हजार रूपए की इमदाद करनी चाहिए और मरने वालों के हरेक परिवारों में से एक आदमी को नौकरी पर लगाया जाना चाहिए। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो बातें और कहकर अपना स्थान ले लूंगा।

इससे अगली बात में यहां जोर से कहना चाहता हूं कि इम्पलायमैंट की तरफ भी सरकार को खास ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से पिछली सरकारों के वक्त में प्रजातन्त्र को कत्ल किया गया, नौकरियों को हरियाणा के अन्दर बुरी तरह से नीलाम किया गया, इस तरह की बातें यहां दोबारा हरियाणा के अन्दर इस लोकप्रिय सरकार के होते हुए नहीं होनी चाहिए। यहां पर इस सरकार ने दोबारा प्रजातन्त्र को कायम करना है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही काम करते रहना चाहिए। यही एक लोकप्रिय सरकार का परम कर्तव्य होना है। सरकार द्वारा इस तरह की एक पालिसी बनाई जानी चाहिए ताकि नौकरियों के मामले में

किसी प्रकार की कोई सिफारिश बाजी न चल सके। जिस प्राकर से कर्नाटक सरकार ने इस मामले में रिजर्वेशन की पालसी बनाई है उसी प्रकार से देहातों के अन्दर रहने वाले लोगों के लिए 50 से 60 परसैन्ट तक नौकरियों में रिजर्वेशन दी जानी चाहिए ताकि लोगों को कुछ सुख का सांस मिल सके। हरियाणा के अन्दर जितनी भी कम्युनिटीज हैं चाहे बैकवर्ड क्लासिज के लोग हैं, चाहे पश्चिमी पंजाब से आने वाले लोग हैं, चाहे शडयूल्ड कास्टस हैं इन सबके लिए अपने अपने स्थान पर परसैन्टेज फिक्स कर देना चाहिए ताकि नौकरियेां में कहीं भी कोई धांधलेबाजी न हो। किसी प्रकार की कोई अनदेखी न हो। किसी का हक न मारा जाए। पिछली जो चौ. भजन लाल व चौ. बंसी लाल की सरकारें थीं उन सरकारों ने इस मामले में बड़ी धांधलेबाली मचा रखी थी और जो परसैन्टेज का वायदा शडयूल्ड कास्टस के साथ बैकवर्ड क्लासिज के साथ किया था, वह भी पूरा नहीं किया था। मतलब यह है कि उस समय कोई सुनवाई नहीं थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले नौकरियों के मामले में जो सिफारिश का सिस्टम था, उसको सदा के लिए खत्म किया जाए और इस तरह की रिजर्वेशन पालिसी बनाई जाए ताकि हरेक आदमी को उसका जायज हक मिल सके और न ही कोई सिफारिश करे, न ही कोइ सिफारिश करवाने के लिए आएं और न ही कोई सिफारिश काम ही करे।

डिप्टी स्पीकर साहब, अन्त में, मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन और एस.एस.

एस. बोर्ड के अन्दर नौकरियां देने के मादले में जो घोटाला हुआ है, उसकी जांच कमीशन द्वारा करवाई जाए ताकि असलियत का पता चल सके और जो जो अधिकारी या कोई बड़े आदमी इस घोटाले में शामिल हों, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए और इस तरह से भ्रश्टाचार को समाप्त करके एक नए युग को यहां हरियाणा के अन्दर लाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने यहां पर दिए हैं, सरकार उनकी ओर ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। जयहिन्द।

श्री हजार चन्द (सिरसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 9, 11, 15, 8, 23 और 10 प0र अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मांग संख्या 9 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूगा जोकि शिक्षा से सम्बन्धित हैं। इस बारे मे मैं अपने जिले के कुछ हालात हाउस के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे जिले सिरसा के अन्दर लड़कों के लिए सिर्फ एक ही डिग्री कालेज हे। हालांकि सिरसा जिले के अन्दर बड़े–बड़े कस्बे और भी जहां पर कालेज चल सकते हैं लेकिन उनके अन्दर कालेज नहीं खोले गए। सिरसा में जो एक कालेज है वह 1978 से पहले एक प्राईवेट कालेज था। उस कालेज की उस वक्त चौ. देवी लाल जी की रहनुमाइ में गवर्नमैंट कालेज करार दिया गया था। उस वक्त उस कालेज में 1200 लड़के थे और आज 10 साल के

बाद उस कालेज में 2700 लड़के हैं। लेकिन उस कालेज की आज हालत यह है कि उसके अन्दर 1200 लड़कों के समय में जितने कमरे थे आज 10 साल के बाद भी उतने ही हैं जबकि उसमें लड़कों की संख्या 2700 हो गई है। वहां कोई नया कमरा नहीं बनाया गया। उन्हीं पुराने बने हुए कमरों में इतने लड़कों को ठोंस रखा है। कमरों की संख्या कम होने के कारण लड़कों को बाहर खुले मैदान में बैठकर पढ़ना पड़ता हे। इसके अलावा उस कालेज में कोई साईस ब्लाक भी नहीं है हालांकि वहां पर टैक्नोलोली, बायलौजी और कैमिस्ट्री के कई सब्जैक्टस पढ़ाए जाते हैं लेकिन एक ही छोटे से कमरे के अन्दर दो–दो सब्जैक्टस पढ़ाए जाते हैं। साईस पढ़ाने के लिए एक बड़ा कमरा होना चाहिए लेकिन जिस कमरे में साईस की पढ़ाई होती है उसी में कोई दूसरा सब्जैक्ट भी पढ़ाया जाता है। हालांकि अलग–अलग सब्जैक्ट के लिए अलग–अलग कमरे होने चाहिएं लेकिन उस कालेज में नहीं हैं। उस कालेज के लड़कों को हायर ऐजूकेशन के लिए चण्डीगढ़ रोहतक या दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। इसलिए जो खुशहाल घराने के लड़के हैं वे तो हायर ऐजूकेशन के लिए चले जाते हैं लेकिन गरीब और माध्यम वर्ग के घरानों के लड़के जिनके पास बाहर जाकर हायर ऐजूकेशन पर खर्चा करने की ताकत नहीं है उन लड़कों को हायर एजूकेशन से मजरूम रहना पड़ता है। उस कालेज में एम.ए. की क्लासिज के लिए और सब्जैक्टस मंजूर करने चाहिएं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि सिरसा जिले के अन्दर जितने भी ग्रामीण हाई

स्कूल हैं उनमें से किसी भी स्कूल में साईस रूम नहीं है और न ही उनके अन्दर साईस का सामान है। यहां तक भी है कि कई स्कूलों में तो टीचर्ज भी पूरे नहीं हैं। यह साल खत्म हो गया है लेकिन उन स्कूलों में पूरे टीचर्ज नहीं भेजे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जो कि नगर विकास के बारे में है। मैं कहूंगा कि सिरसा जिला हैडक्वार्टर है, कोई कोई आदमी सिरसा शहर के अन्दर जाकर देखे कि उसकी सड़को की और गलियों की क्या हालत है? उन सड़कों और गलियों की हालत देखकर नया आदमी यह कहेगा कि क्या यह जिला हैडक्वार्टर हैं? मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने सिरसा म्यूनिसिपल कमेटी को सड़कें और गलियों बनाने के लिए जो पैसा दिया था वह उस काम के लिए खर्च नहीं किया गया चाहे आप इसकी इनक्वायरी करवा लें। केवल कागजों में ही शहर के अन्दर सड़कें और गलियां बनी हुई हैं लेकिन वास्तव में वहां पर सड़कों पर एक भी ईट नहीं लगी है। इसी तरह से सारे हरियाणा की हालत बना रखी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरसा शहर की जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसके रिसोर्सिज बहुत कम हैं। वहां की कमेटी को सरकार और ग्रान्ट देने के लिए विचार करे ताकि वह शहर की हालत को सुधार सके। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिरसा शहर की इस समय

आबादी एक लाख से ऊपर हो चुकी है। सरकार का यह क्राईटेरिया है कि जिस शहर की आबादी एक लाख से ज्यादा हो जाए उस शहर को और उस शहर की म्यूनिसिपल कमेटी को 'ए' क्लास का दर्जा दे देती है। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सिरसा शहर को भी 'ए' क्लास का दर्जा प्रदान किया जाए और वहां की कमेटी को भी ए क्लास बना दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड न. 15 के बारे में बोलना चाहता हूं। 1977 में जब जनता सरकार आई थी उस समय चौ. देवी लाल जी की रहनुमाई में आलुपुर हैड से सुखचैन ढाणी रजबाहे की स्कीम चलाई गई थी लेकिन वह स्कीम उस सरकार के चले जाने के साथ ही खत्म कर दी गई थी। इस सुखचैन रजवाहे का एरिया पंजाब के एरिया में भी पड़ता है। पंजाब में कुछ हिस्सा पड़ने की वजह से हमें इस रजवाहे से पूरा पानी नहीं मिल पाता और पानी पंजाब में ही चोरी हो जाता है जिसकी वजह से टेल पर पड़ने वाले खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यदि इस सुखचैन रजबाहे को रोड़ी ब्रांच के साथ जोड़कर घग्गर से ऊपर हरियाणा के एरिया से लाकर मिला दिया जाए तो 52 गांवों को इसका लाभ हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जो इस ओर उचित ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग न. 8 पर बोलना चाहता हूं। मेरे हल्के में इस सरकार के आने से पहले और बाद में जो सड़कें मन्जूर हुई थीं और जिनके ऐस्टिमेटस पास हो चुके हैं

तथा फण्डज भी निर्धारित हो चुके हैं, उनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिन सड़कों के लिए पैसे का प्रबन्ध हो चुका है वहां पर जल्दी से जल्दी सड़कें बतानी शुरू की जायें। मेरे हल्के की फूलकां से कंवरपुरा सड़क पर काम होने के लिए ईटें वगैरा पड़ गई थीं लेकिन बाद में वे वहां से उठा ली गई हैं। इसी प्रकार से केलनियां से सुखचैन ढाणी की सड़क भी अभी तक नहीं बनाई गई है। इसी प्रकार से एक और सड़क सिरसा से वैधमाला तक पौना किलोमीटर की बनाई जानी है। इस सड़क के न बनने की वजह से वहां के लोगों को 5 किलोमीटर का अधिक सफर तय करना पड़ता है। यदि यह सड़क बना दी जाये तो इससे 8 गावों को फायदा हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पौना किलोमीटर के टुकड़े को अवश्य बनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग नं. 23 जो परिवहन से सम्बन्धित हैं, पर बोलना चाहूंगा। यहां पर मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बसों के मामले में पिछली सरकारों द्वारा सिरसा जिला के साथ चौ. देवी लाल जी का होम डिस्ट्रिक्ट होने के कारण ठीक व्यवहार नहीं किया गया। यहां पर हमेशा कम बसें दी जाती रही है। सिरसा जिले की रोडवेज के अन्दर अब भी वही हालत बनी हुई है। उसके अन्दर कोई सुधार नहीं है। जब सरकार मानती है कि वहां पर पिछले सालों में बुरी भावना से काम होता रहा है तो अब उस कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। पिछले साल

जो बसें खरीदी गई थीं उनमें से भी सिरसा जिले को सिर्फ 14 बसें ही दी गई हैं। हिसार पुराना डिपो है और वहां पर पहले ही बहुत ज्यादा बसें हैं फिर भी उनको सिरसा से अधिक यानी 20 बसें दी गई हैं। इस बारे में मेरी सरकार से गुजारिश है कि जब भी भविश्य में नई बसों की खरीद की जाये तो वहां की कमी को सबसे पहले पूरा किया जाये। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक सिरसा डिपों को पूरी बसें नहीं दी जाती तब तक जो आदमी पीटर इन्जन वगैरा रख कर अपनी व्हीकल्ज आदि चला रहे हैं उन पर जो सख्ती बरती जाती है, और जिनके कारण लोग काफी परेशान हैं वह नहीं बरतनी चाहिए। बसें न मिलने के कारण जब लोग परेशान होते हैं तो मजबूरी में इन छोटे वाहनों में बैठ कर घरों को जाते हैं। वे किराया भी दुगुना तिगुना देते हैं। उन वाहनों को बन्द करने से आम देहात के लोग परेशान हैं।

इसी प्रकार से मांग नम्बर 10 जो चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के बारे में हैं, उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि लोक स्वास्थ्य का मसला सारे हरियाणा का है। जल प्रदूशण और वायु प्रदूशण का एक अहम मसला है। अगर इस बजट में नजर डालें तो इस मद के लिए कोई खास पैसे का प्रावधान नहीं रखा गया। हिमाचल प्रदेश का जितना भी जल प्रदूशण है वह सुखना नदी के रास्ते और काला अम्ब के रास्ते हरियाणा में आ रहा है। उसके लिए हमारी सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया है। इसके अलावा

जहां भी बड़ी–बड़ी फैक्टरियां हैं, जैसे फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत या यमुनानगर में उनमें जल प्रदूशण की और वायु प्रदूशण की बहुत बुरी हालत है। यमुनानगर में तो आदमी गुजर भी नहीं सकता। वहां गन्दे पानी की नालियां चल रही हैं। उन फैक्टरीज की तरफ ध्यान दें। वहां एक शराब की फैक्टरी से बहुत ज्यादा बदबू फैलती है। इसी तरह से पानीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी फैक्टरीज ने बदबू फैला रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा कि सरकार की जो इन्डस्ट्री हैं उनकी तरफ भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जब तक खुद मिसाल कायम नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक अपनी फैक्टरियों में वायु प्रदूशण और जल प्रदूशण को कन्ट्रोल नहीं करेगी तक तक दूसरे लोगों पर दबाव नहीं डाल सकेगी। इसलिए जो सरकार फैक्टरियां प्रदूशण फैला रही हैं उन पर कन्ट्रोल किया जाये। जैसे मुरथल में एक बीअर फैक्टरी हैं वह नैशनल हाई–वे पर है। वहां से जब लोग गुजरते हैं तो उन्हें बहुत बदबू आती है। इसी तरह से थर्मल प्लांटस हैं वहां भी राख के ढेर लगे हुए हैं। इसलिए सरकार अदायरों में जल और वायु प्रदूशण को कन्ट्रोल करने के लिए विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए। स्माल इन्डस्ट्रीज की इतनी शक्ति नहीं होती कि वे अपना ट्रीटमैंट प्लांट लगा सकें। जिनकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं है उनकी मांग है कि उनके यहां सरकार अपनी तरफ से ऐसे ट्रीटमैंट प्लांटस लगाये जो इस किस्म की फैक्ट्रीज हैं जैसे रबड़ फैक्टरी हैं उनका एक मुजम्मा बनाये और

उनके लिए एक ट्रीटमैंट प्लान्ट बनाया जाये। जिस प्रकार से सरकार बिजली और पानी का बिल चार्ज करती है उसी तरह से उनसे चार्ज कर लिया जाये। मैं इतना ही कहते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री परमानन्द (जीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैः–

''बदलता है जमाने के साथ इन्सां,

मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं।''

उपाध्यक्ष महोदय, बजट की चर्चा को देखते हुए और उसकी विभिन्न मांगों को देखते हुए आज यह साबित हो रहा है कि हमारे आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी आज जमाने को बदलने जा रहे हैं। जमाने को नई राह दिखाने के लिए इस बजट में जो नई दिशाएं दी हैं, प्रगतिशील कामों को, जो पहले से चल रहे थे, बढ़ावा दिया गया है। इससे यह बात सत्य साबित होती है।

इन सभी मांगों के बारे में जो आम बातें कही गई हैं उनका समर्थन करते हुए मैं विशेश तौर पर मांग न. 8, 9, 13, 16 के बारे में बोलना चाहूंगा। मांग न. 9 में शिक्षा का जिक्र किया गया है। वास्वत में शिक्षा की वह चीज है जिससे किसी देश का नव–निर्माण किया जा सकता है। बदकिस्मती से 40 वर्श के दौरान सरकारों ने शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया। वही पुरानी शिक्षा पद्धति जो लार्ड मैकाले ने चलाई थी, उसी पद्धति पर शिक्षा

का बजट बनता रहा और काम चलता रहा। इस बजट में प्राईमरी ऐजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा धन रखा गया है, यह एक सराहनीय पग है। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि पुरानी लीक से हट कर शिक्षा को नई दिशा दी जाए। कांग्रेस के राज में शिक्षा के मामल में केवल अंकों का फेर होता रहा है। कभी दस के बाद 12 और 14 के एग्जाम और कभी 10 जमा 1 तथा कभी 10 जमा दो के आंकड़ों में लोगों को उलझाने की कोशिश की गई थी लेकिन कभी भी शिक्षा के अन्दर विभिन्न स्तर निश्चित करके एक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यक्रम नहीं दिया गया। कभी शिक्षा के लिए कोई चेश्टा की भी गई तो उसकी इम्पलिमैंटेशन में कमी रहने के कारण उचित परिणाम नहीं निकल पाए जैसे कि दस जमा दो प्रणाली का हश्र है। इस शिक्षा प्रणाली के तहत दसवीं कक्षा को टर्मिनेशन प्वायंट मानकर वहां तक जनरल ऐजुकेशन चले और उसके बाद स्पैशल ऐजुकेशन चलेगी। इस दस जमा दो प्रणाली की शिक्षा को आरम्भ तो कर दिया गया लेकिन जमा दो के अन्तर्गत जिन इलाकों में जिस–जिस प्रकार की हस्तकला या दस्तकारी या दसूरी काम सिखाने जाने हैं, उनमें उनकी जरूरत के मुताबिक प्रबन्ध नहीं किया। मैं अपनी इस प्रगतिशील सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि दस जमा दो शिक्षा प्रणाली के अन्दर दसवीं पास करने के बाद युवकों को और नव–युवतियों को इस काबिल बना दिया जाए कि उन्हें नौकरियों के पीछे न दौड़ना पड़े। अतः शिक्षा संस्थाओं में जमा दो के अन्तर्गत हस्तकला, दस्तकारी तथा दूसरे काम सिखाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध

करवा दिए जाएं। शिक्षा के अन्तर्गत प्राईमरी ऐजुकेशन के क्षेत्र में बहुत से स्कूलों का आज यह हाल है कि कहीं अध्यापक की कमी है तो कहीं टाट–पट्टी नहीं हैं। इनके मुकाबले में बार–बार नवोदय स्कूलों की मांग उठती है। हिन्दुस्तान के संविधान में इक्वैलिटी टू अपचुनिटी की बात कही गई है लेकिन हमारे इन स्कूलों औ नवोदय स्कूलों में कहां 'इक्वैलिटी' है। एक बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है जहां टाट–पट्टी और बोर्ड तक नहीं है और जहां केवल एक अध्यापक है और यदि किसी दिन वह अवकाश ले ले तो स्कूल में छुट्टी करनी पड़ती है और कहां वह नवोदय स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। इसी प्रकार पब्लिक स्कूल के बच्चे भी हैं। इस दोहरी शिक्षा नीति के बच्चों को अगर कम्पीटीशन किया जाए तो यह ऐसा होगा कि जैसे अंगहीन, पांवों के बिना लूले और कार में बैठे हुए व्यक्ति की दौड़ हो। मैं उप–मुख्यमंत्री महोदय ने प्रार्थना करूंगा कि प्राईमरी से लेकर दस जमा दो तक की शिक्षा प्रणाली में विशेश तौर पर पिछड़े इलाकों और गांवों की ओर विशेश ध्यान दे कर उनको अच्छे स्तर पर लाने के लिए सक्रिय और प्रभावशाली पग उठाने की कृपा करें।

इसके बाद मैं मांग न. 13 पर बोलना चाहूंगा जो कि समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। दुर्भाग्य से इस भारत में समाज का एक अंग जो समाज की सबसे बड़ी सेवा करता है और देश के उत्पादन काक वह अकेला ही उत्पादक है उसे हम किसान मजदूर या पिछड़ा हुआ हरिजन भी कह सकते हैं। उस वर्ग की

बहुत बुरी तरह से अपेक्षा होती रही है। इस बजट में इन वर्गों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है। विशेश तौर पर शिडयूल्ड कास्टस के लोगों के लिए 98 करोड़ कुछ लाख रूपये रख गये हैं। अगर हम इन लोगों के सदियों स चले आ रहे दुख की देखें तो यह राशि थोड़ी है क्योंकि इनके ऊपर वहां एक ओर सामाजिक दमन हुआ है वहां दूसरी ओर आर्थिक शोशण भी हुआ है। ये लोग राज्यों की उपेक्षा के शिकार रहे हैं। इन वर्गों की स्थिति यह है कि इन वर्गों में पैदा हुए हर नौजवान, आदमी और मंत्री यह कहते हुए देखे जाते हैं कि –

हम तो अपमानों की घूंट पीकर जीते रहे हैं,

दुनियां ने सीना चाक किया, हम सीते रहे हैं।

क्या इसी तरह से जिएगी संतती हमारी?

जो नरकीय जीवन हम जीते रहे हैं?

इस प्रकार से दुखी लोगों की सहायता के लिए हमारी सरकार ने अपने बजट में पैसे का प्रावधान किया है जो कि एक सराहनीय बात है। मैं तो यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस सहायता को और बढ़ाया जाए ताकि समाज का उपेक्षित वर्ग यह समझे कि मैं भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकता हूं। हरिजन के अतिरिक्त जो दूसरे पिछड़े वर्ग हैं वे भी समाज के उत्पादनकर्ता वर्ग थे। परन्तु संविधान में उन्हें इस प्रकार की कोई सुविधान नहीं मिल पाई थी। काका कलेलकर ने जो रिपोर्ट दी थी

हमने उस पर बीस साल तक संघर्श किया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने और हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। एक बार हम चौ. बंसी लाल के पास एक डैपूटेशन लेकर गये थे। हमने मांग की थी कि आपने बैकवर्ड क्लासिज के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण किया है जो हमारी जनसंख्या को देखते हुए बहुत थोड़ा है। उन्होंने अपनी अकड़ में कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं 2 प्रतिशत को भी हटा दूं। उससे हमें बहुत बड़ा दुख हुआ था और हमने उस शासन को बदलने का तहैया किया था। हमने चौ. देवी लाल जी का नेतृत्व प्राप्त करके 1977 में वह शासन बदला। उस दो परसैन्ट किया। मैं चौ. देवी लाल के दिखाए हुए उस मार्ग की सराहना करता हूं। इसके साथ–साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण की मांग के अन्दर ही प्री–ऐग्जामिनेशन ऐजुकेशन की सुविधा केवल शिडयूल्ड कास्टस को ही प्राप्त है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिडयूल्ड कास्टस आज सबसे दलित और शोशित हैं। आज की इस पूंजीवादी व्यवस्था के परिणामस्वरूप समाज का हर वर्ग कहता है कि कुछ लोग इस प्रकार के गरीब हो गए हैं कि वे न तो कहीं दूर जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और न किसी शहर में जाकर किसी मंहगे इंस्टीच्यूशन से कोचिंग लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

12.00 बजे

मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह फैसिलिटी जो हरिजनों को प्राप्त है, यह समाज के अन्य कमजोर वर्गों जैसे पिछड़ें वर्ग हें, महिलाएं हैं, छोटे किसान हैं जिनके पास का एक या दो एकड़ ही भूमि है, छोटे दुकानदार हैं, जो मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, उन लोगों तक भी बढ़ायी जाए। यह एक अच्छा कदम होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इन मांगों के अन्दर डेरी डिवैल्पमैंट के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम रखी गई है। जहां इसमें यह प्रोवीजन किया गया है कि हरिजनों को 3 जानवरों की डेरी बनाने के लिए सुविधा दी गई है, वहां महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिये भी सुविधा दी गई है। विधवाओं के लिए विशेश कर ऐसा प्रोवीजन करना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। भारत में दुर्भाग्य से महिलाओं की समाज में स्थिति बड़ी ही दयनीय रही है। हमारे इस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए ही मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। हमारी सरकार ने डेर के कामों के लिए जो इस मांग प्रोवीजन किया है, यह उन अबलाओं की आंखों के नीर को, उनके आंसुओं को पोंछने का काम है। मैं साथ–साथ यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि विधवाओं को जो समाज के अन्दर उपेक्षित और दुखी हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं होते, उनकी पैंशन को यदि 50 से बढ़ा कर 100 रूपया कर दिया जाये तो यह बहुत ही उचित और सराहनीय कदम होगा। अन्त में मैं सभी डिमांडज के सम्बन्ध में एक बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। हमारी

सरकार सभी वर्गों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। समाज के उपेक्षित और दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिये और दूसरे आगे बढ़े हुए वर्गों के समान लाने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनायी हैं ताकि इस वर्ग आगे बढ़ाया जा सके परन्तु दुर्भाग्य से ब्यूरोक्रेसी के अन्दर कुछ ऐसे लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो समय समय पर सरकर द्वारा जो सुविधाएं आरक्षण के बारे में उनको दी गई हैं वे उन आरक्षणों के बारे में कोई न कोई मीन–मेख निकाल कर उनको लागू नहीं होने देते। कहने का मतलब यह है कि उनको टाला जा रहा है। हमारे प्रदेश में पंजाब रीआर्ग्रेनाजेशन ऐक्ट के तहत उस समय जो कानून लागू था, उसमें भी वेकैन्सीज के ऊपर रिजर्वेशन अवेलेबल थी। बाद में कुछ इस किस्म के लोग जो इस वर्ग को ऊपर उठने नहीं देना चाहते थे उन लोगों ने वेकैन्सीज के स्थान पर पोस्ट का शब्द जोड़ दिया। पोस्ट शब्द करने से उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। इन लोगों के ऊपर इसका ऐसा असर पड़ा कि किसी विशेश प्रोमोशन के वक्त जब भी कोई बार–बार वैकेन्सी होती है, चाहे वह वेकैन्सी एक दो बार ही नहीं 30 बार खाली हो लेकिन वह पिछड़े वर्ग को और शिडयूल्ड कास्ट को न जाकर दूसरे लोग के जाते हैं। इस तरह से ये लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से ज्वायंट पंजाब के टाईम पर आरक्षण नीति के बारे में रोस्टर बना हुआ था और उसके अनुसार उनके लिए निश्चित पदों पर उनकी प्रोमोशन हो सकती थी, वह बनाया जाये। इस रोस्टर के बनाने की तरफ सरकार तुरन्त ध्यान

दे। अन्त में मैं एक बात अपने जिले को बाबत कहना चाहूंगा। मेरा जिला हरियाणा के सैन्टर में स्थित है। कुछ जिलों में ऐसी चीजें दी गई है जैसे कि कई जिलों में जे.बी.टी. इंस्टीच्यूशन्ज दी गई हैं या कहीं पर अन्य साधन दिये गये हैं परन्तु इस जिसे को न तो कोई कल–कारखाना ही मिला है और न ही कोई ऐसी इंस्टीच्यूशन मिला है। मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारा जीन्द जिला हैडक्वार्टर है वहां पर एक लड़कियों की आई.टी.आई. है। एक तो वह किराये की बिल्डिंग में चल रही है और दूसरे वहां सारी ट्रेडज नहीं है। वहां पर एक फुल फलैज्ड आई.टी.आई. दिया जाना चाहिए और उसमें सारे विशय शुरू किए जाएं और आई.टी. आई. का भवना भी बनाया जाएं जे.बी.टी. स्कूल जो कि पैप्सू के समय में वहां पर होता था उसको दुबारा से जींद में शुरू किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले दो सालों में दूसरी जगहों पर जे.बी.टी. स्कूल खोलने का जो सरकार का विचार है और उनसे जो लड़के–लड़कियों निकलेंगी वे उन वेकेन्सीज को जो क्रिएट होंगी, पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जींद में भी जे.बी.टी. स्कूल खोला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जींद में एक शूगर मिल है। गन्ने से भरे हुए ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां मेन शहर के बीच में से गुजरती हैं जिससे कोई न कोई ऐक्सीडैंट हो जाता हैं और ट्रक तथा ट्रैक्टर ट्रालियों वालों का काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस बारे में मैंने एक क्वैश्चन भी दिया था लेकिन वह भी

दसवें नम्बर पर रह गया। जैसे हम पिछड़े हैं वैसे ही सवाल भी पिछे ही रह गया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि छोटी–छोटी सड़कें हैं उनको बना दिया जाएं जिससे कि ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां बाहर की बाहर मिल में चली जाएं और उनको शहर में न आना पड़े। ये सड़कें दो–दो चार–चार किलोमीटर की हैं और इनके बनने से लोगों को काफी सहूलियतें को जाएंगी और सारा का सारा ट्रेफिक बाहर से निकल जाएगा। छोटे–छोटे लड़के गन्ने निकालते रहते हैं, वे पीछे नहीं देखते और अचानक ट्रक या ट्रैक्टर ट्राली से उनका ऐक्सीडैंट हो जाता है। इस चीज को अवाइड करने के लिए इन सड़कों का बनाना बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, ये सड़क हैं। अहीरका से झांझ खुर्द, कंडेला से झांझ बरास्ता रूपगढ़ बरोदी, जलालपुर से झांझ बरास्ता जुलानी, जुलानी से झांझ, संगपुरा से झांझ, बरास्ता दरियावाला रोड़ तथा राजपुरा से संगतपुरा। उपाध्यक्ष महोदय, इन सड़कों के बनने से सारा ट्रैफिक बाहर का बाहर चला जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कहकर मैं अपना स्थाना लेता हूं।

श्री मनी राम (डबवाली, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर और गवर्नर एडैस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं डिमांड नम्बर 16, 9, 15, 11, और 21 तथा 14 पर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 16 पर बोलना चाहता हूं। मैं अपने इलाके की कुछ समस्याएं आपके सामने रखूंगा। डबवाली ऐसा इलाका है जहां पर कोटन की काफी फसल होती है।

1978–79 में जब चौ. देवी लाल की सरकार थी उस समय वहां पर एक सिपनिंग मिल लगाने की प्रोपोजल थी लेकिन किन्ही आधार पर वहां पर सिपनिंग मिल लगाने की प्रोपोजल कैन्सिल हो गई और वह मिल कहीं ओर लगा दी गई। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर एक जिनिंग मिल लगाई जाए। क्योंकि हमारे यहां बहुत कौटन होता है। हमारा इलाका पंजाब के साथ लगता है। हमारे यहां का सारा कपास मलोट और मुक्तसर आदि मंडियों में चला जाता है। इससे सरकार को सेल्ज टैक्स, इंकम टैक्स और मार्किट टैक्स का नुक्सान होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर जिनिंग मिल लगाई जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हिसार में एक दाल फैक्टरी थी। मैंने सुना है वह बन्द हो गई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह दाल मिल डबवाली में लगाई जाए। मेरे इलाके में चना काफी होता है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐजूकेशन के बारे में कुछेक बातें कहना चाहता हूं। मेरा इलाका शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। सिरसा जिले में केवल एक ही कालिज है। यह इलाका चौ. देवी लाल का होने के कारण काफी नजरअन्दाज रहा है। पिछले चालीस साल में यहां पर शिक्षा का स्तर काफी गिरा है। डबवाली चालीस पैंतालीस हजार की आबादी वाला कस्बा है और वहां पर कोई कालिज नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस साल हमें एक कालिज दिया जाए ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे लोगों के बराबर आ सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमाण्ड नम्बर 15 के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। मेरा जो इलाका है, वह बौर्डर है, वह बौर्डर पर है, टेल पर पड़ता है। रेतीला भी है। खालें कच्ची हैं। लेकिन एम.आई.टी.सी. को इस काम के लिए पैसा बहुत कम दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि खालों को पक्का करने के लिए इलाके की हर लिहाज से बहबूदी के लिए ज्यादा पैसे का प्रोवीजन किया जाए। एम.आई.टी.सी. को और ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि इस इलाके का काम सुचारू रूप से निपटाया जा सके जिससे किसानों को राहत मिले।

इसी तरह से अर्बन डिवैल्पमैंट के कामों के लिए भी बहुत थोड़ा पैसा रखा गया है। नगरपालिकाओं के पास धन की कमी है। सिरसा नगरपालिका को लगभग 10 लाख रूपया सरकार द्वारा दिया गया है। इसका हमं कोई एतराज नही है मगर हमारे इलाके की ओर भी सरकार को कुछ राहत हेतु पैसा देना चाहिए। अगर इस राशि में से थोड़ा सा पैसा कालांवाली और डबवाली मंडी के विकास के लिए लगा दिए जाए तो यह अच्छी बात होगी। उप–मुख्यमंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। शायद उन्हीं के पास नगर पालिकाओं का विभाग है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारी कालांवाली मंडी और डबवाली मंडी के लिए पैसे का प्रोवीजन किया जाए ताकि वहां पर जो गलियों की हालत खस्ता है, टूटी फूटी हैं उनकी मुरम्मत करवाई जा सके। वहां पर बरसात के दिनों में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको निकालने

का कोई साधन वहां पर नहीं है। इसलिए इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। इसी तरह से हरिजनों की बस्तियों में बरसात का पानी रूक जाने से बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और उस पानी के निकलने का कोई साधन नहीं है। आशा है कि सरकार मेरे इस सुझाव पर अवश्य ही ध्यान देगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 10 पर भी अपने विचार रखता हूं जोकि पब्लिक हैल्थ से सम्बन्धित है। इस बारे में, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे इलाके में कोई हस्पताल का बन्दोबस्त नहीं है। यहां पर एक 50 बैडज का हस्पताल होना जरूरी है। वहां की आबादी इतनी है कि जिसके लिए बंड़े हस्पताल की आवश्यकता है जबकि वहां एक छोटा सा हस्पताल है जोकि उस इलाके की जरूरीआत को पूरा नहीं करता। उसकी बिल्डिंग की हालत भी शोचनीय है, अच्छी नहीं है। एक 50 बैडज का हस्पताल कालांवाली मण्डी में पहले से ही मन्जूर हुआ पड़ा है। उस इस्पताल को जल्द से जल्द बना दिया जाए।

एक सुझाव मैं सरकार को और देना चाहता हूं। मेरे इलाके में गांव गंगा, मुढ़ी और मुन्ना वाली है। अगर इन गांवों के बीच एक छोटी सी माईनर बना दी जाए तो उस इलाके के लोगों को काफी राहत मिलेगी और आबपाशी भी अच्छे तरीके से वे लोग कर पाएंगे। वहां पर पानी की बहुत कमी है। दूसरी बात यह है कि उस इलाके में इन गांवों की हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हे। गांव वाले जमीन भी देने को तेयार हैं। अगर सरकार यह गंगा

गांव का जलघर बनवा दे तो उस इलाके की जनता इस सरकार की आभारी होगी। इरीगेशन मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं। मैं उनसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि 1978 में इस तरह की एक पालिसी सरकार द्वारा बनायी गई थी, पता नहीं किन कारणों से बाद में वह योजना रदद कर दी गई। इसलिए मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान दे वह मेरा उनसे आग्रह हैं पब्लिक हैल्थ विभाग से भी मेरी प्रार्थना है कि गंगा गांव के लिए अलग से एक वाटर वर्क्स बनाया जाए। पहले इस गांव को गांव मुन्नावाली से जोड़ा हुआ है और वहां से इस गांव को पानी सप्लाई होता है लेकिन उस गांव की यह प्रार्थना है कि पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए सारकार उस गंगा गांव के निवासियों के लिए अलग से एक वाटर वर्कस का प्रावधान करे। अतः सरकार इस ओर ध्यान दें।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड न. 21 से सम्बन्धित भी कुछेक बातें सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। डिवैल्पमैंट के कामों के लिए सरका ने बहुत कम पैसा रखा है। मेरे हल्के के कुछेक गांव ऐसे हैं जिनको पिछले 40 सालों से बिल्कुल नजर अन्दाज कर रखा है। गलियों की हालत बहुत खस्ता है, कच्ची गलियां हैं। जब तक इस ओर सरका का ध्यान नहीं जाएगा तब तक हरियाणा के अन्दर विकास नहीं हो सकेगा। चौ. हुक्म सिंह जी यहां बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कहीं पर चाहं कोई स्कूलज का काम है, चाहे नहरों का काम है, चाहे कोई दूसरा डिवैल्पमैंट का काम चालू है, लेकिन सभी कामों के लिए पैसा

बहुत थोड़ा अलाट किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पेसा इन कामों के लिए अलौट किया जाए ताकि ऐसे गांवों का जिनकी हालत बहुत खराब है, विकास किया जा सके।

अब मैं डिमांड नम्बर 14 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, सुबह बहुत सुशमा जी को यहां पर प्रश्नोत्तर काल में बताया गया था कि जो सरकारी डिपोज हैं, उन परा बढ़िया गेंहू की बजायें घटिया गेहूं का आटा पिसवा कर बेचा जा रहार है और बड़ी–बड़ी मिलों का भी इस अडल्ट्रेशन में हाथ है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि इन मिलों की भी जांच करवाई जाए और जो दोशी लोग हैं उनको सजा दी जाए। आशा है कि बहन जी इस बारे में अवश्य ध्यान देगी और शीघ्र ही इसकी जांच करवाएंगी। (विघ्न) जो आटा है वह बहुत ही घटिया किस्म का लोगों को सप्लाई किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी फलोर मिल्ज की चैंकिग भी करवाई है? जो आटा आता है उसके अन्दर मिकदार से ज्यादा मुआयश्चर होता है और अडलट्रेशन बहुत होती है लेकिन क्या आपने कभी उन पर छापा मरवाया है ताकि बढ़िया किस्म का आटाल लोगों को मिल सके? अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा। पिछली सरकार ने सड़कों के बारे में एक स्टेटमैंट दी थी कि हमने हरियाणा के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि कई गांव ऐसे है जिनको अभी

सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। मेरे हल्के में कई गांव ऐसे है जो दो–दो या तीन–तीन किलोमीटर के फासले पर हैं और उनको सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। अगर उन गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाए तो लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है और लोगों को एक दूसरी जगह आने जाने में 15 से बीस किलोमीटर तक का कम एरिया तय करना पड़ेगा। जैसे मेरे हल्के में एक गांव भास खेड़ा है उस गांव के लोगों को चौटाला जाने के लिए 15–20 किलोमीटर का एरिया तक करना पड़ता है लेकिन यदि भासखेड़ा से चौटाला तक का जो चार किलोमीटर का टुकडा है उसको सड़क से जोड़ा दिया जाए तो लोगों को इतना चक्कर लगा कर चौटाला नहीं जाना पड़ेगा और वे उस गांव से सीधे चौटाला जा सकते हैं। ऐसे ही एक झूठी गांव है। उस गांव से गोरियांवाला तक दो किलोमीटर सड़क का टुकडा बनना है। वह टुकडा बनाने के लिए मंजूरी भी मिल गई थी लेकि पता नहीं किन कारणों से वह कैंसिल हो गया। इसी तरह से गांव शेरगढ़ से लखवाना तक 7 किलोमीटर सड़क का टुकडा बनना है। अगर यह टुकड़ा बनाकर इन गांवों को जोड़ दिया जाए तो इन गांवों के लोग 15–20 किलोमीटर की दूरी का चक्कर लगाने की बजाय 6–7 किलोमीटर से ही मंडी डबवाली जा सकते हैं। इसी तरह से पाना गांव से मिठड़ी गांव और मिठडी से खोखरा गांव तक 8 या 9 किलोमीटर का फासला है अगर उनको सड़क से जोड़ दिया जाए तो उन गांवों के लोगों को सिरसा जाने में बड़ी आसानी हो सकती है। इन गांवों के लोग 20–25 किलोमीटर का कम फासला तक करके

सिरसा जा सकते हैं। अब मैं बिजली के बारे मे कहना चाहूंगा। मेरे हल्के में जो लोग गांवों में नहीं रहते बल्कि ढ़ाणियों में रहते हैं उनको बिजली की बड़ी भारी दिक्कत है। जब हम लोग उन ढ़ाणियों में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि उन्हें बिजली दिलाई जाए। जब हम बिजली वालेां से कहते हैं तो वे कहते हैं कि साहब हमारे पास पोल्ज की तो कोई कमी नहीं है लेकिन जो तारें या दूसरा बिजली का सामान है उसकी बहुत कमी है। यदि वह सामान मिल जाए तो हम बिजली दे सकते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बिजली की तारें और दूसरे सामान की जहां–जहां पर आवश्यकता है वह दिया जाए। यदि वह सामान दे दिया जाए तो उन ढाण्सिांयों में भी बिजली मिल सकती है नहीं तो वे ढ़ाणियों बिजली से वंचित रह जाएंगी। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मैंने अपने हल्के के बारे में जो–जो डिमांड रखी है। उनके बारे में सरकार गौर करे।

श्री कांति प्रकाश भल्ला (कालका): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमांडज सदन में रखी गई हैं ये सारी की सारी जन कल्याण हित में हैं। जो बजट उप–मुख्य मंत्री ने 22 तारीख को पेश किया था वह भी बहुत सराहनीय था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 8 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मेरा हल्का नदियों और पहाड़ों से सटा हुआ है। मेरे हल्के का बहुत सा हिस्सा घग्घर नदी और टांगरी नदी से प्रभावित है। जब 1977 में चौ. देवी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने उस समय मेरे

हल्के में बहुत से काम हुए थे लेकिन जो बहुत छोटी–छोटी सड़कें बनने से रह गई हैं उनका बनाना बहुत ही जरूरी है। घग्घर नदी की दूसरी साइड में 5 या 6 गांव ऐसे हैं जिनका बरसात के दिनों के कालका का रास्ता बिल्कुल कट जाता है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में इतने पैसे का तो प्रावधान नहीं है कि बड़े–बड़े पुल बनाए जाएं लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में हैंगिग ब्रिज बनाए जाते है, जिनके ऊपर से केवल आदमी या जानवर ही गुजर सकते हैं। उसी तरह का एक पुल चण्डी मंदिर के पास घग्घर नदी पर बनाया जा सकता है। यदि चण्डी मंदिर के पास घग्घर नदी पर हैंगिग ब्रिज बना दिया जाए तो घग्घर नदी के उस पर वाले गांव के आदमियों को इधर आन जाने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह का पुल टांगरी नदी पर बनाया जा सकता है। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि इलैक्शनों के दौरान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, चौ. देवी लाल जी, ने मेरे हल्के में एक जन सभा को सम्बोधित करते हुए यह कहा था कि आप इस हल्के से लोकदल के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं, टांगरी नदी का पुल बना दिया जाएगा। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टांगरी नदी के उस पार जो 10–15 गांव हैं उन गांवों के आदमियों को इधर आने जाने में बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए उस नदी के ऊपर से गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है और न ही कोई साइकिल, मोटर साईकल उस नदी के अन्दर से गुजर सकती है। इसलिए में उप–मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हो सके तो टांगरी

नदी पर पुल बनाये जाने के लिए बजट में कुछ राशि रखने पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग न. 9 की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने बजट में तो प्रावधान किया है कि शिक्षा की तरफ उचित ध्यान दिया जायेगा। ऐजूकेशन के बारे में देखा गया है कि सरकार प्राईमरी स्कूल या राजकीय स्कूल खोलने की बजाये प्राईवेट स्कूलों को ज्यादा ग्रान्ट वगैरा देकर प्रोत्साहन दे रही है। पंचकूला में सिर्फ एक ही गवर्नमैंट हाई स्कूल है लेकिन उसके मुकाबले में प्राईवेट स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है। इस बारे में मेरी सकरारसे प्रार्थना है कि वह सारे हरियाणा में सरकारी स्कूल कायम करने की अधिक से अधिक कोशिश करें न कि प्राईवेट स्कूलों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाये। मेरे हल्के का बहुत सा एरिया पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में जो प्राईमरी स्कूल हैं उनमें टीचर नहीं हैं। इस बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जिन प्राईमरी स्कूलों में टीचर नहीं हैं उनमें टीचर्ज की व्यवस्था की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या न. 11 की तरफ सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा। मेरे हल्के में पंचकूला एक नया शहर बसने जा रहा ळैं वहां पर बहुत सी असुविधाएं लोगों को हो रही हैं। इस बारे में मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के के साथ बरवाला और रायपुर रानी ही जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग अपनी फसल को लेकर जा सकते

हैं। ये दोनों स्थान मेरे हल्के से काफी दूरी पर पड़ते हैं इसलिए यहां के लोग या तो अपना अनाज पंजाब में ले जाकर के बेचते हैं या फिर यू.टी. की ग्रेन मार्किट में लाकर बेचते हैं। वहां पर कोई अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी न होने की वजह से लोगों को काफी तकलीफें हो रही हैं। हमने इस बारे में हुडडा के कई बार बात भी की है। स्टेट नेशनल हाई–वे के पास एक जगह सिलैकट भी की गई थी लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। इस बारे में मेरी सरकार से पुनः प्रार्थना है कि वहां पर जल्दी से जल्दी एक अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी बनाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के अन्दर बहुत सारे स्टोन क्रैशर लगे हुए हैं। इनकी मिट्टी उ़कर पंचकूला शहर में आती है। इस बारे में लोगों ने मैमोरैण्डम भी दिए हैं और मेरी भी मांग है कि उन स्टोन क्रैशरों को वहां से उठाकर कहीं और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाये। इन स्टोन क्रैशरों की धूल आधे से ज्यादा शहर के मकानों पर आ रही है। इन स्टोन क्रैशरों को कहीं और जगह दी जाये। मुझे आशा है कि सरकार इस तरफ ध्यान अवश्य देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं. 21 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे हल्के में एन.आर.ई.पी. और आर. एल.ई.जी.पी. स्कीमों के तहत काम चल रहा है। इन स्कीमों के तहत कूलें पक्कीं बनाई जा रहीं है। सरकार यह एक अच्छा काम कर रही है। मैं सिचाई मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि

घग्घर नदी पर जिस तरफ दो गांवों के एिल अप–लिफ्ट कर के पानी दिया जा रहा है उसी तरह वहां पर और अप–लिफ्ट स्कीम तैयार की जायें ताकि और अधिक लोगों को फायदा हो सके और जमींदारों का काम चल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 23 पर बोलना चाहता हूं। पंचकूला शहर में हरियाणा के कार्यरत अधिकारी और बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं। वहां पर जो बस स्टैण्ड बनाया जा रहा है उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। पंचकूला से इधर उधर आने जाने में लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इसलिए इस बस स्टैंड को जो तकरीबन पूरा हो चुका है पूरा करवाया जाये और बसें वहां से चलाई जायें ताकि लोगों को आने जाने में किन्दी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता चाहूंगा कि कालका का बस स्टैण्ड भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये। कालका से तो हिमाचल प्रदेश की भी बसें जाती है। दूसरे हमारी सरकार बनने से पहले कुछेक बसें चण्डीगढ़ से वाया पंचकूला होते हुए कालका जाती थीं, जो इस सरकार के बनने पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी ने बन्द करवा दी हैं जिससे सच.एम.टी., पिंजौर जाने वाली सवारियों को बड़ी असुविधा हो रही है क्योंकि उनके समय बदल गए हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना हे कि वहां पर जो बसें बन्द की गई हैं वे पुनः चलाई जायें ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। यदि और अधिक बसों की भी आवश्यकता हो तो

वे भी पंचकुला से चलाई जायें। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

मोहम्मद असलख खां (छछरौली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 2, 4, 21, 20 8 और 15 पर बोलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 4 पर बोलूंगा। यह डिमांड सूखे के मुताल्लिक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट की कोई कमेटी आयी थी। उस कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि किस इलाके को सूखा घोशित किया जाये। मैं मानता हूं कि उस कमेटी से गलती हो गई होगी ओर उस कमेटी ने छछरौली तहसील को सूखाग्रस्त घोशित न किया हो। इस बारे में मैं सरकार से गुजारिश यह करूंगा कि किसी दूसरी तरीके से छछरौली इलाके की इमदाद की जाये ताकि वहां के लोग भी यह महसूस करें कि हमारी तरफ भी सरकार ने तवज्जुह दी है। मैं थोड़ा पहाड़ी इलाके के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं। वे उस इलाके के बारे में भली–भांति जानते हैं। उन्होंने वहां के लोक सभा का चुनाव भी लड़ा है। इसलिए हमारे छछरौली इलाके को सूखा राहत घोशित करने से नजर–अन्दाल न यिका जाये। हमारे इलाके को भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। शराब का अब ऐसा हाल हो गया है कि गांव–गांव में शराब बिकती है।

गांव–गांव में ठेके खुल गए हैं। इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया–

गया दौर वह साकी जब छुप–छुप कर पीते थे पीने वाले।

बनेगा सारा जहां महखाना हर कोई बादखार होगा।।

तो स्पीकर साहब, आजकल ऐसा हाल हो रहा है। इसलिए इस सिलसिले में जरूर तवज्जुह दें और लोगों को शराब पीने से रोका जाये।

तीसरी बात मैं वैल्फेयर डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। सारे के सारे गांवों में झुग्गी झोपड़ियों के मकान हैं। वे घास फूस से बनाये हुए होते हैं। जब किसी झोपड़ी में आग लग जाती है तो सारे का सारा गांव जल जाता है, कुछ भी बाकी नहीं बचता है। जिन लोगों की झुग्गी झोंपड़ी जल जाती है और नुक्सान हो जाता है उन्हें उस नुक्सान का उसी वक्त पैसा मिलना चाहिए। पैसा मिलने में साल दो साल लग जाते हैं। इस बारे में कुछ राशि डी.सी. के पास होनी चाहिए ताकि उन लोगों को साथ की साथ ही रिलीफ मिल सके। अगर किसी आदमी का घर जल गया और उसे दो साल के बाद पैसा मिलता है तो उसका कोई फायदा नहीं। डी.सी. एक जिम्मेदार आदमी है। इसलिए उसके पास कुछ ऐसे फन्ड हों कि जहां भी आग लग जाये वह फौरी तौर पर उनकी सहायता कर

सके। किसी आदमी का घर जल जाये वह फौरी तौर पर उनकी सहायता कर सके। किसी आदमी का घर जल जाता है अगर उसको उसी वक्त पैसा न मिले और दा साल बाद मिले तो उस गरीब आदमी को उस पैसे मिलने का कोई फायदा नहीं है, नुक्सान ही है क्योंकि वह उस पैसे को कही काम में खर्च कर लेगा। साथ की साथ ही सुविधा और इमदाद दी जाये ताकि उस गरीब आदमी को फायदा पहुंच सके। इसी से सम्बन्धित फौरेस्ट डिपार्टमैंट भी है। वहां के लोगों को फौरेस्ट में जो हक मिलते थे वे भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे है। जैसे पहले गरीब लोग 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक अपने जानवरों को जंगल में चरा सकते थे लेकिन अब वह अवधि 28 फरवरी तक कर दी है। 28 फरवरी से 31 मार्च तक तो कोई फसल भी नहीं कटती इसलिए मेरा निवेदन है कि 31 मार्च तक ही पशुओं के चरने की इजाजत होनी चाहिए।

इसी फौरेस्ट डिपार्टमैंट के मुताल्लिक मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जंगलात हमारे जीवन के लिए निहायत जरूरी हैं। हम पेड़ों के बगैर जिन्दा नहीं रह सकते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लान्टेशन होनी चाहिए। आज एक जमींदार जो पेड़ लगाता है वह कुछ सालों के बाद मैच्योर हो जाता है। उसे काटने के लिए जमींदार को सरकार ने परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने में बड़ा लम्बा समय लग जाता है। बाज दफा तो पांच–पांच साल लग जाते है। दो पेड़ काटने की इजाजत रेन्ज अफसर दे

देता है। इसमें कोई समस्या या दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गरीब आदमी दो पेड़ बेचना चाहता है तो उन पेड़ों की उसको चीफ कन्जरवेटर से इजाजत लेनी पड़ती है जोकि चण्डीगढ़ से लेनी पड़ती है। पहाड़ी इलाके के लोग निहायत ही गरीब हैं और उनको चण्डीगढ़ आना पड़ता है। चण्डीगढ़ का भारी भरकम किराया तो उस बेचारे को देना ही पड़ता है साथ ही उसको यह भी पता नहीं होता कि चण्डीगढ़ में दफतर कहां है। इस प्रकार दो पेड़ बेचने के लिए भी उसे इतना परेशान होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आखिर पेड़ों के बारे में रिपोर्ट तो रेन्ज आफिसर से ही ली जाती है कि पेड़ काटने के लिए मेच्योर हो गये हैं या कि नहीं। अगर रेन्ज आफिसर को ही ये पावर दे दी जाए तो फाईल चीफ कन्जरवेटर तक नहीं भेजनी पड़ेगी और उन गरीब आदमियों को परेशानी से भी बचाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं मांग नम्बर 8 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब भी इस समय यहां तशरीफ रखे हुए हैं। मैं उनकी तवज्जो अपने हल्के की एक सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं। छछरौली ब्लॉक में मार्किट कमेटी का एक परचेज सैन्टर खारवन में है। गांव बलाचौर से खारवन तक यदि दो किलोमीटर सड़क का टुकड़ा बना दिया जाए तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी क्योंकि इस समय उनको अपना अनाज आदि परचेज सैन्टर तक लाने के लिए

वाया जगाधरी आना पड़ता है और इस प्रकार उन्हें पन्द्रह किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। इस सड़क के बन जाने से उनकी एक तो मुश्किल हल हो जाएगी और इस परचेज सैन्टर की आमदनी भी बढ़ जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक साल में ही इस परचेज सैन्टर की आमदनी से इस सड़क को बनाए जाने का खर्चा पूरा हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मेरा पूरा इलाका पहाड़ी या सब–माउन्टेनियस एरिया है। ज्यादातर गांवों में पीने का पानी की सहूलियत दे दी गई है। मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि जिन गांवों में पीने का पानी अभी तक उपलब्ध नहीं किया गया है उन गांवों में भी जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाने की मेहरबानी करें। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने हल्के में सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाये जाने के सिलसिले में मैं सिचाई मंत्री जी से मिला था और उन्होंने बताया कि यह बहुत बड़ा काम है और न जाने इसको शुरू होने में कितने वर्श लगेंगे। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस इलाके के लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं लोग जानवर पालकर अपना गुजारा करते रहे हैं। ये लोग जंगलों में अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे और दूध बेचकर अपना पेट पालते थे। आज उनका यह धन्धा भी फौरेस्ट, वालों के अंकुश के कारण चौपट होता जा रहा है। फौरेस्ट गार्डज को

मैजिस्ट्रेट फस्ट क्लास की पावर्ज दी हुई हैं और वह लोगों पर एट–दि स्पॉट मनमाना जुर्माना कर सकता है। मैं खुद यह नहीं चाहता कि जंगलात विभाग के तहत जो जंगल हैं, उन्हें पशु नश्ट कर दें। इस बारें मेरा सुझाव है कि यदि इन गांवों में पशुओं की चरागाहें उपलब्ध करवा दी जाएं तो जंगलों में पशु चराने की नौबत ही नहीं आएगी ऐसे गांव जिनके पास चरागाहें नहीं हैं वे अपने पशुओं को तक तक बाहर नहीं निकाल सकते जब तक उनकी फसलें खेतों में खड़ी होती हैं। हर साल ये लोग अपने पशुओ को चराने के लिए यमुना के पार यू.पी. के हल्के में ले जाते हैं क्योंकि उनके पास न तो पशुओं को चराने के एिल कोई माकूल जगह है और न ही पशुओं को पिलाने के लिए पानी मिलता है। सैकड़ों लोग अपने पशुओं के साथ दो–दो तीन–तीन महीने पत्थरीले जंगलों में पड़े रहते हैं। यू.पी. सरकार की ओर से भी अब उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि यदि उन गांवों में एम.आई.टी.सी. के टयूबवैल्ज लगा दिया जाएं जो कि लगाए जा सकते हैं। पता नहीं किसी वजह से इस इलाके के बारे में रिपोर्ट है कि यहां टूयबवैल्ज नहीं लग सकते। वहां, अब टयूबवैल्ज लगवाए जा सकते हैं। यदि एम.आई.टी.सी. एक–एक गांव में एक–एक टयूबवैल ही लगा दे तो लोग उससे बरसीन बो लेंगे या दूसरा हरा चारा बोने की सुविधा उनको हो जाएगी। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूं।

श्री सीतरा राम सिंगला (गुडगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने सभी मैम्बरों की भावना को देखते हुए पैन्शन 1.1.88 की बजाए 1.1.86 से ही कर दी है। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि हरियाणा गांवों में बसता है और यहां पर कुछ कर्मचारियों की ऐसी लौबी है कि जब से वे सर्विस में लगे हैं तब से लेकर अब तक वे शहरों में रह रहे है और उन्होंने देहात की तरफ जाकर भी नहीं देखा। (इस समय भी श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अगर किसी कारण से उनका देहात में ट्रांसफर हो भी जाता है तो वे ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जिसका सरकार पर प्रभाव होता है और अपनी ट्रांसफर कैंसिल करवा लेते हैं। वे लोग शहर में रह कर सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। शहरों में रह कर इनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है जैसे उनको हाउस रैंट मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो नगरों का वर्गीकरण कर रखा है जैसे एक लाख और उससे ऊपर की आबादी का शहर 'ए' क्लास कहलाता है, पचास हजार से ऊपर वाला 'बी' क्लास और 25 हजार से नीचे का 'सी' क्लास कहलाता है इसके अनुसार आप कर्मचारियों को हाउस रैंट की सुविधा देते हैं। मेरा निवेदन है कि हाउस रैंट परपज के लिए अगर 'सी' क्लास को 'ए' क्लास मान लिया जाए तो गांवों में रहने वाले कर्मचारियों को भी शहर वाली सुविधाएं मिल सकती हैं। ऐसा करने से ट्रांसफर वाली बात भी बन्द हो जाएगी। इसके अलावा

गांवों के अन्दर कई ऐसे स्कूल हैं जहां पांच–पांच क्लासों के लिए केवल एक मास्टर है। इसके अलावा हैल्थ डिपार्टमैंट में लोग गांव के अन्दर ट्रांसफर करवा लेते हैं। वे तनखाह तो गांव से लेते हैं और काम शहरों में करते हैं। इस प्रकार के कई मामले आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर मेरे सुझाव को आप मानेंगे तो कर्मचारियों को मालूम होगा कि सरकार बदली है और उसने नियम भी बदले हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कालेज और यूनिवर्सिटीज टीचर के ग्रेड रिवाइज किए हैं। आपने जो प्राइवेट कालेज टेक ओवर किए हैं और उनमें जो प्रोफैसर्ज काम करते हैं उनको सर्विस करते हुए 20–25 साल हो गए है लेकिन आपने उनकी सरकारी नौकरी में उस रोज शो किया है जिस रोज से उस कालेज को लिया है। इस कारण से वे दुविधा में पड़ गए हैं। मिसाल के तौर पर एक शिश्य प्राइवेट कालेज में पढ़ता था और उसने एम.ए. करने के बाद किसी गवर्नमैंट कलोज में सर्विस कर ली तो शिश्य अपने गुरू से ज्यादा तनखाह लेता है और जो गुरू 25 साल से सर्विस कर रहा है वह कम तनखाह लेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे कर्मचारियों को ज्यादा संख्या नहीं है, जब से वे कालेज चल रहे हैं तभी से उन सरकारी नौकरी मानी जाए। जिस प्रकार से आपने व्यापारियों की एक कमेटी बनाई है जिसमें सरकारी सदस्य भी हैं और व्यापारियों के सदस्य भी हैं और वे वक्त–बे–वक्त मीटिंग करके उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं, इस प्रकार से कर्मचारियों की भी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि हों

और सरकार के भी प्रतिनिधि हों। बैठ कर उनकी समस्याओं पर विचार किया जाए। ऐसा करने से उनका असतोश कम हो सकता है। अगली बात में होम डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं कि पुलिए की संख्या जरूरत से कम है। आप देखैंगे कि अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी जिले के दौरे पर आता है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, गवर्नर साहब हो, प्राईम मिनिस्टर हों या केन्द्र के मंत्री हों तो बड़ी तादाद में उनकी सुरक्षा के लिए पुलिए की डियूटी लगाई जाती है और थाने खाली हो जाते है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पुलिस भी भरती की जाए तथा इसकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी बात यह है कि हर थाने के अन्दर एक एक व्हीकल दिया हुआ है। हर थाने के साथ कई–कई चौकियां लगी होती हैं लेकिन उन चौकियों में न तो कोई व्हीकल है और न ही टेलीफोन है। अगर चौकी वालों ने थाने वालों के साथ कोई बात करनी होती है या थाने वालों ने चौकी वालों के साथ बात करनी होती है तो मैसेंजर भेजना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चौकियों में भी टेलीफोन और व्हीकल की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, जो चोरी होती है, आम तौर पर पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। वह उनको यह कह देते हैं कि एक कागज पर लिख जाइये। अगर उन पर एस.पी. से मिलकर या किसी अन्य तरीके से दबाव डालते हैं तो वे रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उनकी कोशिश यह रहती है कि सफेद कागज पर लिखकर आदमी चला जाये और वह

उसको दर्ज नहीं करते। मेरा सरकार से यह कहना है कि उनको हिदायत की जाये कि वे चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज किया करे।

अब मैं एक दो बातें रैवेन्यू विभाग की भी कहना चाहूंगां मैंने पहले भी एक दफा इस सदन में कहा था कि तीन रूपये का कागज या इस तरह से छोटी अमाउन्ट के स्टैम्प पेपर नहीं मिलते। अगर सिकी को ऐफीडविट देने के लिए तीन रूपये का कागज चाहिए तो उसको 20 रूपये का कागज लेना पड़ता है। सरकार इस तरह जरूर ध्यान दे । एक बात मैं और कहना चाहता हूं। सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि कोई भी मंत्री यदि रैस्ट हाउसिंज में ठहरता है तो उसके चाय और खाने–पीने का प्रबन्ध सरकारी स्तर पर नहीं किया जायेगा। इससे पहले तहसीलदार इस नाम पर लोगों को लूटते थे। अब यह प्रथा बन्द कर दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार लोगों को लूट रहे हैं। तहसीलों के अन्दर भ्रश्टाचार अब भी बन्द नहीं हुआ है। आज भी पहले की तरह से ही एक या डेढ़ परसैंट रजिस्ट्री के वक्त लिया जा रहा है और पहले की तरह से ही चन्दा वसूल किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मेरा एक निवेदन और है कि किसान को पास बुक इशू की जाये जिसके कारण उसको बार–बार पटवारी के पास जाना पड़ता है, उसको फर्द की जरूरत पड़ती रहती है। मेरा कहना यह है कि अगर उसको पास बुक इशू कर दी जाये तो उसको बार बार परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा एक निवेदन

और भी है कि जिस तरह से आप जिलों का पुनर्गठन कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप ब्लाकों का भी पुनर्गठन करिये क्योंकि कई गांव अभी ऐसे हैं जिनका ब्लाक दूसरा होता है और थाना दूसरा होता है।

श्री अध्यक्ष: सिंगला साहब, आप वाईन्ड अप करें।

श्री सीता राम सिंगला: मैं तो अभी थोड़ा सा समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, टाईम बहुत थोड़ा है। अभी कई और सदस्यों ने बोलना है।

श्री सीता राम सिंगला: ठीक है जी। मैं अभी खत्म कर देता हूं। ऐजूकेशन बारे में मैं यह कहना चाहूगा कि गुड़गांवा के अन्दर दो कालेज हैं। मैं उनके बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। उन दो कालेजों में से एक लड़कियों का कालेज अलग से कर दिया जाये और लड़को का कालेज अलग से कर दिया जाये। इससे सरकार को भी कोई असुविधा नहीं होगी। वहां पर इए समय दोनों जगहों पर को–ऐजुकेशन है। अगर ऐसा कर देंगे तो ठीक रहेगा। गुड़गांवा एक तो दिल्ली के नजदीक है दूसरे गुड़गांवा शहर काफी बड़ा शहर है। ला कालेज और बी.एड. कालेज मेरे हल्के के अन्दर नहीं हैं। इसके लिए भी कोई न कोई प्रोवीजन अवश्य किया जाये।

एक बात मैं सोशल वैल्फेयर के बारे में कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने यह बताया है कि पैंशन का फार्म जो लोग देने से रह गये हैं, उनके लिये 31 मार्च आखिरी तारीख है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब लोग फार्म भर कर देने जाते हैं तो विभाग वाले लेने से इन्कार कर देते हैं और यह कहते हैं कि दोबारा अफसर फिर गांवों में जायेंगे, तब लेंगे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस बात को स्पश्ट करें कि क्या 31 तारीख लास्ट डेट है या जो सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट वाले कहते हैं, वह ठीक है? इस बारे में सरकार को अपनी पालिसी स्पश्ट करनी चाहिये। (घंटी) अच्छा जी धन्यवाद।

चौ. सतबीर सिंह काययान (नौलथा): स्पीकर साहब, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय ने 22 तारीख को जो बजट पेश किया है, वह बड़ी सूझ–बूझ से और बड़े अच्छे ढंग से पेश किया है। इसके अन्दर चौ. देवी लाल की नीतियों का स्पश्ट तौर पर उल्लेख किया गया है। मैं मांग नं. 6, 8, 9, 10, 17 और 23 के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि इसराना के अन्दर सब–तहसील है लेकिन वहां पर ट्रेजरी अभी तक नहीं खोली गयी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसके लिये भी कुछ न कुछ बजट में प्रोवीजन किया जाये। दूसरी बात मैं सड़क तथा भवन निर्माण के बारे में कहना चाहूंगां बजट में 220 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रोवीजन किया गया है। वह सारे प्रदेश को देखते हुए बहुत कम है। पानीपत के अन्दर

फलाईंग ओवर ब्रिज की मांग काफी देर से चली जा रही है। उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये।

शिक्षा के क्षेत्र में यह कहा गया है कि कोई नये स्कूल अपग्रेड नहीं किए जायेंगे और स्पोर्टस के बारे में भी कम पैसा रखा गया है। हरियाणा की जनता और उसकी जनसंख्या को देखते हुए इस डिमांड में जो पैसा रखा गया है, वह बहुत ही कम है।

स्पीकर साहब, कृशि के क्षेत्र में भी बहुत कम पैसा रखा गया है। कई जगहों पर एच.डी.सी. की जो दुकानें थीं वे बन्द कर दी गई हैं। इससे किसानों की कीटनाशक दवाएं तथा बीज लेने में काफी दिक्कत आ रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कीटनाशक दवाएं लेने के लिए तथा बीज के लिए और अधिक दुकानें खोली जाएं। स्पीकर साहब, मैचिंग ग्रांट के लिए दो करोड़ साठ लाख से बढ़ा कर दो करोड़ छियासठ लाख रूपया किया गया है। यह काफी कम पैसा है। इसको और बढ़ाया जाए ताकि हर गांव और हर शहर का विकास हो सके।

स्पीकर साहब, हैल्थ में दवाओं के लिए जेा पैसा रखा गया है वह भी बहुत ही कम है। उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। पानीपत तहसील में जो इसराना गांव है वहां पर कम्युनिटी सैन्टर खोला जाए ताकि वहां पर ग्राम समूह के लोग उसका फायदा उठा सकें। स्पीकर साहब, गांवों के अन्दर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंअ ने

जो टूटियां लगाई हैं उनमें पानी बिल्कुल नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि गांवों के अन्दर जो लोग अपने घर में निजी तौर पर प्राईवेट कनैक्शन लेना चाहें उन को प्राईवेट कनैक्शन लेने की इजाजत दी जाए। स्पीकर साहब, मैं खास तौर पर सिवाह गांव का जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर पानी बहुत नीचे है। उसका वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। हरियाणा के अन्दर ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिस में लोग अगर प्राईवेट कनैक्शन लेना चाहें तो उनको ऐसा करने की इजाजत होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फौरन ही प्राईवेट कनैक्शन दिए जाएं। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री सरदूल सिंह (सफीदों): स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल की सरकार ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही अच्छा बजट है। बजट आने से पहले कुछ लोग तरह–तरह की बोली बोलते थे कि बहुत अधिक टैक्स बजट में लगाए जाएंगे। माननीय गुप्ता जी ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और बड़ी सूझ बूझ से जो बजट रखा है वह बहुत ही अच्छा बजट है। जिन लोगों की बातों का कोई सिर पांव नहीं था और वैसे ही बात करते थे, इतना अच्छा बजट पेश कर के उन लोगों का मुंह सदा के लिए बन्द कर दिया है। इस बजट में गांवों और शहरों की तरक्की की किरण नजहर आ रही है। उसी किरण की आशा में मैं अपने इलाके के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह इलाका वर्शो से

पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है और इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

मांग न. 16 के द्वारा मैं सरकार से रोजगार के बारे में अपील करना चाहता हूं। यह कस्बा आबादी के लिहाज से काफी बड़ा है और यहां पर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार दिया जाए ताकि वहां पर अधिक से अधिक इंडस्टरी खुल सके।

स्पीकर साहब, मांग न. 10 हैल्थ के बारे में है। सफीदों में एक जनरल अस्पताल है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, अन्त में मैं सफीदों में सड़कों, अस्पतालों, नहरों और मंडियों के लिए सरकार से मांग करता हूं कि वह इन चीजों की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दे। वहां की मंडियों की हालत खराब है और वहां की सड़कें टूटी हुई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दे ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री गुरदयाल सिंह सैनी (थानेसर): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया। मैं डिमांड नम्बर 9, 10 व 15 पर अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा कि थानेसर के अन्दर कन्या उच्च विद्यालय की बिल्डिग की तरफ खास तवज्जो दी

जाए। जगह की काफी कमी है। शिफ्टों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसलिए में शिक्षा मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि स्कूलों की बिल्डिंगों की तरफ ध्यान दिया जाए और थानेसर में इस तरह के स्कूलों की बिल्डिगों का निर्माण जल्दी करवाया जाए। इसी तरह से शहरों में तो पहले ही 10+2 का सिस्टम स्कूलों में हैं लेकिन गांवों में भी इसी तरह का प्रबन्ध सरकार को शीघ्र ही करना चाहिए ताकि गांव के लोग इस सुविधा से वंचित न रह जाए।

इससे अगला प्वायंट मेरा यह है कि आज हरियाणा के अन्दर एक ही सरकारी आयुर्वेदिक कालेज है जो कि कुरूक्षेत्र में है। उस तरफ भी सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये क्योंकि न तो उस कालेज की बिल्डिंग है और न ही वहां पर पूरा पढ़ा लिखा स्टाफ ही है और न ही कोई वहां पर होस्टल है जिसमें बच्चे रह सके लोगों को इन सभी के कारण काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उस कालेज के लिए जो जमीन 30 एकड़ ऐक्वायर की गई थी वहां आज कल सफेदे के दरख्त सरकार द्वारा लगा दिए गये हैं। इसलिए जिस परपज के लिए वह जमीन ऐक्वायर की गई है उसी परपज के लिए उस जमीन का इस्तेमाल होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज ही मुझे पता चला है कि उस कालेज के लिए 3 लाख 15 हजार रूपया दिया गया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और साथ ही यह निवेदन भी करता हूं कि इस पैसे का सदुपयोग करके जल्द दी इस

बिल्डिंग को बनाया जाए और काबिल स्टाफ का भी बन्दोबस्त किया जाए ताकि जब वहां से पढ़ कर बच्चे डाक्टर बन कर निकलें तो कोई यह कहें कि वे लोग हरियाणा के आयुर्वेदिक कालेज के पढ़े हैं। इससे हरियाणा का नाम रोशन होगा। अगर बच्चों को अच्छा स्टाफ लगा कर अच्छी पढ़ाई करवाई जाएगी तो वे आगे चल कर लोगों की अच्छी सेवा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 15 पर विचार रखूंगा। इसके बारे में मैं सिंचाई एंव बिजली मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि लाडवा सिंचाई स्कीम जिसमे लिये पहले से पैसा मन्जू हुआ पड़ा है उसको जल्दी ही पूरा करवाने की कोशिश की जाए। साथ साथ मैं यह भी निवेनद करूंगा कि मेरे हल्के के अन्दर कई शहरों पर पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है इस ओर सरकार ध्यान दे। कई जगहों पर टयूबवैल के गड्ढे गहरे हो ये हैं। क्योंकि वहां से काफी मिट्टी उठा ली गई है। मोटर नीचे लगाने के लिए बहुत गहरा खड्डा बनाना पड़ता है जिस के कारण से वहां मिट्टी गिरने से काफी मौतें भी हो गई हैं। इस ओर ध्यन दिया जाए।

अन्त में मैं एक बात कहूंगा कि कुरूक्षेत्र के अन्दर और नहरां का निर्माण यिका जाए। इस इलाके में लोग भी कुछ पैसा अपने पास से देने के लिये तैयार हैं और कुछ सरकार उनकी मदद करे ताकि वहां पर नहरी पानी का इन्तजाम हो सके। नहीं तो यह कुरूक्षेत्र का इलाका रेगिस्तान बन कर रह जाएगा। मेरी

प्रार्थना है कि इस कुरूक्षेत्र के क्षेत्र को रेगिस्तान होने से बचाया जाए। धन्यवाद।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 5 पर बोलूंगा जिसका सम्बन्ध बिजली और पानी से है। इसके बारे में मैं क्या कहूं? इस सदन के बहुत से सदस्य पहले ही चौ. वीरेन्द्र सिंह जी को और चौ. देवी लाल जी को बधाई दे चुके हैं क्योंकि इस बार सारे प्रदेश में बिजली बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध कराई गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हं कि इस वक्त सारे भारत में नीलोखेड़ का ऐरिया धान की उपज में सबसे आगे है। नीलोखेड़ी का बासमती चावल, अपने देश, प्रदेश में तो क्या, विदेशों में भी बड़ा मशहूर है।

आवाजें: दे दो फिर सभी को एक एक बोरी।

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, एक एक बोरी तो नहीं, पर मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि मैं असैम्बली के सभी माननीय सदस्यों को पांच–पांच किलो चावल तो अवश्य ही दे सकता हूं।

स्पीकर साहब, इससे अगली बात मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बिजली और पानी का ज्यादा प्रबन्ध करवाया जाए। इस सदन में कई बार पहले 33 के. वी. के सब स्टेशन का अपग्रेड करने की बात आई थी लेकिन वह

बात बीच में ही रह गई। अतः निवेदन है कि उस इलाके की ओर विशेश ध्यान दिया जाए और उस सब स्टेशन को अपग्रेड करके वहां 132 के.वी. का लगाया जाए। इससे यहां पर बिजली की सुविधा हो सकेगी। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो सिरसा नहर है उसके साथ साथ लाडवा तक मेरे क्षेत्र का एरिया पड़ता है उस एरिया में नीचे के पानी का स्तर 80 फुट नीचे चला गया है। उस एरिया के लिए नहर के पानी का प्रबन्ध किया जाए। अगर उस एरिया के लिए नहर के पानी का प्रबन्ध जल्दी नहीं किया गया तो जैसे भाई गुरदयाल सिंह ने कहा वह एरिया रेगिस्तार बन जाएगा। वह हरियाणा का बहुत उपजाऊ क्षेत्र है इसके इलावा मैं मांग संख्या 9 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि शिक्षा के बारे में है। मेरे हल्के में दो कस्बे नीलोखेड़ी और तरावड़ी 25–30 हजार की आबादी के हैं लेकिन उनमें कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। सरकार से मेरा निवेदन है कि वहां पर एक डिग्री कालेज जरूर खोला जए। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने रायसन गांव में 10+2 प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी लेकिन उस स्कूल में अभी तक यह प्रणाली लागू नहीं की गई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

अब मैं मांग संख्या 8 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि भवन तथा सड़कों के बारे में है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के नीलोखेडी के अन्दर जितनी भी सड़कें

बनी हुई हैं उनकी बड़ी खस्ता हालत है। यदि कोई पक्की सड़क टूट जाती है तो वह कच्ची सड़क से भी बुरी हो जाती है और उन पर चलने से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इस बारे में मैं पी. डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे नई सड़कें बनाएं या न बनाएं लेकिन जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मुरम्मत होनी बहुत जरूरी है उनकी मुरम्मत अवश्य करवा दें।

अब मैं मांग संख्या 10 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि चिकित्सा एंव लोक स्वास्थ्य के बारे में है। मेरे हल्के में सामाणा बाहू और सगा गांवों में पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि उन गांवों के लोगों के लिए वाटर सप्लाई स्कीम का प्रबन्ध किया जाए।

अब मैं मांग संख्या 23 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि परिवहन के बारे में है। हमारे परिवहन मंत्री जी यहां हाउस में बैठे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि तरावड़ी कस्बें के लिए जो बस स्टैंड बनाया गया है वह कस्बे से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर बनाया है। तरावड़ी से आकर जो सड़क जी. टी. रोड पर मिलती है उस जगह से थोड़ी पीछे हटकर बस स्टैंड बनाया गया है। वह बस स्टैंड शहर से काफी दूर पड़ता है जिसके कारण लोगों को बहुत असुविधा है। वह बस स्टैंड पुराने बस स्टौप से दूर होने के कारण कई ऐक्सीडैटस हो चुके हैं और कई बच्चे तथा बूढ़े मौत के घाट उतर चुके हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस बस स्टैंड को वहां से उठाकर तरावड़ी मोड़ के

नजदीक जी.टी. रोड पर बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो जो बसें तरावड़ी से जी.टी. रोड पर आती हैं वे वहां पर जरूर रूकनी चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब डिसकशन का जवाब देंगे क्योंकि 1 बजने वाला है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरा निवेदन है कि हाउस का टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाए क्योंकि बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: कल हाउस का टाईम काफी ऐक्सटैंड हो चुका है और मेरी लिस्ट के मुताबिक आप कल बोल भी लिए हैं।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, चूंकि और दूसरे सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि हाउस का टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाए।

Mr. Speaker: It is not possible. I am sorry. I cannot do it. You please take your seat.

13.00 बजे

उप–मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास): अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन चार दिन से बजट पर बहस चल रही है और इसमें भाग लेते हुए हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट

किए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने भी सुना होगा लगभग सभी माननीय सदस्यों ने बजट की मूल भावना की हदय से सराहना की है और बतलाया है कि यह बजट बहुत प्रोग्रैसिव है, आम आदमी का बजट है तथा इससे आम आदमी को, हर वर्ग को सुविधाएं मिलेंगी और हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास होगा। इस तरह के विचार यहां सदन में प्रस्तुत किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट के विरोध में दो तीन स्वर यहां उभरे और वे नुक्ताचीनी के लिए उभरे। मैं कहता हूं कि स्वस्थ आलोचना ठीक होती है लेकिन कुछ आलोचना, आलोचना के लिए की जाती है। इसलिए जो दो तीन विरोधी स्वर उभरे वे केवल आलोचना के लिए थे। अध्यक्ष महोदय कल जनरल बजअ की बहस का जवाब देते हुए भी बड़े बिस्तर के साथ मैंने सभी बातों पर प्रकाश डाला था। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात रही हो जिस पर कल प्रकाश न डाला गया हो। जैसे कि प्रथा है मांगों पर भी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है और सदस्यों को बोलने का मौका मिलना भी चाहिए, लेकिन मांगों पर जो बहस होती है उसका दायरा बड़ा सीमित होता है उस सयम केवल मांगों पर ही बोला जाता है। परन्तु हमारे सदस्यों ने इस लिमिट को भी क्रौस किया, उस दायरे से बाहर भी बोले। उस पर मुझे कोई आपति नहीं है। उनके विचार और उनकी भावनाएं आनी चाहिएं। वे किसी न किसी बहाने अपनी बातें रखना चाहते हैं। श्री रघु यादव जी ने भ्रश्टाचार के खिलाफ काफी बातें कही हैं। यह बात सभी मानते हैं कि भ्रश्टाचार अभी प्रदेश के कुछ दायरों में है। जैसा मेंने कल भी

कहा था कि चौ. देवी लाल जी की सरकार का इरादा है और इस सरकार की यह नीयत है कि भ्रश्टाचार को समाप्त किया जाये। भ्रश्टाचार समाप्त करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं वे बहुत प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं। भ्रश्टाचार दूर करने में मुझे इस बात की पूरी आशा है कि हमारे सभी सदस्य हमें इस काम में पूरा सहयोग देंगे। हमें जनता का भी सहयोग मिलेगा। भ्रश्टाचार के सभी सदस्यगण भी परेशान हैं और जनता भी परेशान है। इससे कोई सुखी नहीं है। लेकिन कुछ निहित स्वार्थी तत्व होते हैं जो भ्रश्टाचार को बढ़ावा भी देते हैं और जब कभी भ्रश्ट अधिकारी किसी मामले में फंस जाता है तो उसको बचाने की चेश्टा भी करते हैं। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं काफी अरसा विधान सभा में रहा हूं। हमारे माननीय सदस्यों के सामने कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जो भ्रश्ट अधिकारी कहीं पकड़े जाते हैं या उनको निलम्बित किया जाता है तो हमारे माननीय सदस्य ही उन्हें बहाल करने के लिए सिफारिश करते हैं और जोर डालते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाये। एक सदस्य होने के नाते मैंने भी ऐसी सिफारिशें की हैं। लेकिन मैं यह सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर माननीय सदस्य इस बात से परहेज करें और बड़ी हिम्मत के साथ आने वाले लोगों को यह कहें कि देखिए आपने मेरा समर्थना किया है, मेरा सहयोग दिया है यह ठीक है, इसके लिए मैं आपका अहसानमन्द हूं लेकिन यदि आप उस काम को कहें जो काम रचनात्मक हो, जनता के हित में हो, किसी ग्राम के हित में हो, किसी मोहल्ले के हित में हो या आपका ऐसा व्यक्तिगत

हित हो जिससे दूसरे को नुक्सान न हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं लेकिन भ्रश्टाचार के मामले में उनकी बात न मानें। ऐसा दृढ़ रवैया हमारे सभी सदस्यों को अपनाना चाहिए। इससे हमें भ्रश्टाचार को रोकने में, इसे खत्म करने में काफी सहयोग और सहायता मिलेगी। आजकल हम देखते हैं कि कई बार बड़ा प्रैशर पड़ता है, जोर पड़ता है और उसे अवायड करना बड़ा कठिन हो जाता है। मुझे आशा है कि भ्रश्टाचार को दूर करने में हमारे माननीय सदस्य सहयोग देंगे। मैं श्री रघु जी को बताना चाहता हूं कि सरकार का इरादा है कि भ्रश्टाचार बन्द हो। मैं यह बात भी स्पश्ट करना चाहता हूं कि जो अधिकारी भ्रश्ट हैं और जो चेतावनी के बावजूद भी सही रास्ते पर न आएंगे, उन्हें माफ नहीं किया जायेगा। (विघ्न)

आवाजें: भ्रश्ट अधिकारियों को ही सहन न किया जाये बल्कि भ्रश्ट राजनेताओं केा भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्त: सही बात है। भ्रश्ट अधिकारियों को भी सहन नहीं किया जायेगा और भ्रश्ट राजनेताओं को भी सहन नहीं किया जायेगा। (तालियां) अगर केलव अधिकारियों पर पाबन्दी हो कि वे भ्रश्टाचार न करे ओर राजनीतिज्ञों के लिए छूट हो, यह बात बहुत गलत है। वह जमाना गया जब एक ही आदर्श सामने होता था कि लूटो और लूटने दो। उस टाईम पर जीओ और जीने दो की बजाए यही आदर्श होता था कि लूटो और लूटने

दो। वे खुद भी लूटते थे, मंत्री भी लूटते थे और सभी मैम्बर्ज भी लूटते थे। साथ में अधिकारियों को भी लूटने की छूट थी। अब वह जमाना लद चुका है। अब तो चौ. देवी लाल क राज है। हमारा नारा है कि 'बिजली पानी का प्रबन्ध और भ्रश्टाचार बन्द।'

इसके अलावा सूखा राहत के मामले में कुछ सदस्यों ने कहा है। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय मेरे अपोजीशन के साथियों की बड़ी खराब आदत हो चुकी है। कभी बोलने नहीं देते। यहां ये हाउस में दो आदमी बैठे हैं यदि हमारी तरफ वाले सारे इस बात पर तुल गये तो मेरे ख्याल में ये एक शब्द भी सदन में नहीं कह पायेंगे।

चौ. तैयब हुसैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जबाव, आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने थ्रैटनिंग बात कहीं है कि अगर ये सारे इस बात पर तुल गये तो हम एक शब्द भी इस सदन में नहीं बोल सकेंगे। क्या यह हाउस में थ्रैटनिंग लैग्वेज इस्तेमाल कर सकते है? इस तरह से धमकी की बात कैसे चल सकती है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई धमकी नहीं दी और न ही धमकी देने की भावना थी। अगर चौ. तैयब हुसैन जी इस धमकी समझते हैं तो मैं अपने शब्द वापिस ले लेता हूं। मैंने यह कहा था कि इनकी दो तीन की संख्या है और ये इतनी इन्ट्रप्शन करते हैं अगर सब हमारी तरफ से इन्ट्रप्शन करने

लगे तो ये कैसे बोलेंगे? मैंने यह बात कही थी, कोई धमकी नहीं दी थी। (शोर एवं विघ्न)

चौ. तैयब हुसैन: गुप्ता जी अगर गिनती की ही बात है तो लोक सभा में 542 में से आपके केवल दो मैम्बर्ज हैं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धीर पाल सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं आपकी मार्फल माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब आप लोक सभा के मैम्बर थे, उस समय आपकी संख्या चाहे 400 थीं या 500 थी, आपने कभी भी एक शब्द नहीं बोला।

चौ. तैयब हुसैन: आपको इस बात का क्या पता है कि मैं एक भी शब्द नहीं बोला। मैं रिकार्ड की बात कह रहा हूं कि प्राईवेट मैम्बर रैजोल्यूशन जोकि बहुत ही कम पास होते हैं केवल मेरा पास हुआ था।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी पार्टी का एक सदस्य हो या पचास हो, सब को बोलने का अवसर मिलना चाहिए। कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, इन्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए। किसी माननीय सदस्य को कोई बात खटकनी है तो उसके लिए सारे प्रावधान है। हमारे नियमों के अन्दर यह लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ कहना है तो वे चेयर से इजाजत लेकर कह सकता है और अपनी बात को स्पश्ट कर सकता हैं तथा पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन भी

दे सकता है। इस प्रकार बैठे–बैठे बोलना किसी के लिए भी शोभायमान नहीं है चाहे मैं ही क्यों न बोलूं, मुझे भी खड़े होकर चेयर से इजाजत लेकर ही बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, श्री रघु यादव जी ने कहा कि सूखा राहत का विवरण कई स्थानों पर ठीक ढंग से नहीं हुआ, इसी प्रकार से सारे जोहड़ भी पानी से नहीं भरे गए अथवा किसी अधिकारी ने गलत सूचना दी है। ये सारी बातें आपके माध्यम से मेरे नोटिस में लाएं। इनको चाहिए था कि ये सम्बन्धित मंत्री से मिल कर ऐसे मामले उनके नोटिस में लाते। यदि फिर भी सुधार न होता तो मुख्यमंत्री जी को इस बारे अवगत करवाते। इस प्रकार की कोताही के लिए जो भी अधिकारी/कर्मचारी दोशी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी इस बात का मैं आश्वासन देता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह दहिया जी ने भाशण बहुत ही अच्छी प्रकार से दिया। उन्होंने प्रत्येक डिमांड का हवाला देते हुए उचित ढंग से अपनी बात कही। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा के मद में धन कम रखा गया है इस राशि को बढ़ाना चाहिए। मांग संख्या 12 की ओर भी ध्यान आकर्शित करवाते हुए उन्होंने बल दिया कि नौजवानों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिएं क्योंकि जब संघर्श का बिगुल बजा तो युवकों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्श समिति का साथ दिया और इस सरकार को लाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अब जब हमारी

सरकार बनी है तो हमें उन नवयुवकों को रोजगार देने का प्रबन्ध करना चाहिए। सरकार इस ओर पूरा ध्यान देगी। चौ. बलबीर सिंह ने मांग की कि सड़कों का विकास किया जाए और जो सड़कें मुरम्मत होने वाली हैं उन्हें मुरम्मत किया जाए। इस ओर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।

श्री हजार चन्द जी ने पंजाब के एरिया के निकलने वाले सुखचैन माइनर का जिक्र किया। हमारे सिंचाई मंत्री जी यहीं बैठे हैं। वे इस बारे में सिंचाई मंत्री जी से बात करें कि इस बारे में क्या पग उठाए जा सकते हैं? श्री हजार चंद जी ने जल–प्रदूशण का बिन्दू उठाा है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आपको पता ही है जल–प्रदूशण को रोकने के लिए एक बोर्ड बना हुआ है। यह बोर्ड अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है कि वायु प्रदूशण और जल–प्रदूशण को कम किया जाए। इस विशय में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हल करना काफी कठिन है। लेकिन फिर भी सरकार हर प्रकार के प्रदूशण को रोकने के लिए हर सम्भव कोशिश कर रही है। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस बारे भी सरकार पूरी तरह से जागरूक है।

प्रोफैसर परमानन्द जी ने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी–2 बातें कही। परमानन्द जी खुद एक अच्छे शिक्षा–शास्त्री है और उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। दस जमा दो शिक्षा प्रणाली तथा स्कूलों की हालत के बारे में उन्होंने रोशनी डाली है

कि प्राईमरी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है और बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टीं तक नहीं मिलती, कहीं ब्लैक बोर्ड की कमी है और कहीं अध्यापकों की कमी है। यह भी ठीक है कि पब्लिक स्कूल्ज हर प्रकार से साधन सम्पन्न हैं लेकिन इन पब्लिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना आम आदमी के बस की बात नहीं है क्योंकि इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा होता है समाजवाद में विश्वास रखने वाली प्रत्येक सरकार हर व्यक्ति को शिक्षा के समान अवसर और शिक्षा सेवाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश करती है। यह सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा के समान अवसर और अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की हर सम्भव कोशिश करेगी। शिक्षा के लिए प्राईमेरी स्कूलों को अधिक धन देने की कोशिश इसी कारण की गई है ताकि प्राईमरी स्तर से ही शिक्षा में सुधार लाया जा सके। जहां तक पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, मैंने तो पहले ही यहां तक किया हुआ है कि यदि कोई पब्लिक स्कूल वाला मुझे किसी फंक्शन में बुलाता भी है तो मैं किसी भी ऐसे फंक्शन में भी भाग नहीं लेता और सीधे ही न कह देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि शिक्षा की मद में जितना पैसा होना चाहिए उतना हम नहीं दे पाए हैं लेकिन हमारी कोशिश यह है कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दें। आपने देखा होगा कि समाज कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में हमने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के बारे में भी श्री परमा नन्द जी ने कुछ बातें कहीं थीं उनका सुझाव बड़ा अच्छा है। सरकार पहले

से ही इस बात के लिए सजग है। जीन्द में आई.टी.आई. की लड़कियां सरकारी भवन की बजाए किराए के भवन में पढ़ती हैं, इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। जीन्द में कुछ सड़कें बनाने की बात भी कही गई, और यह भी कहा गया कि जो ट्रैक्टर शूगर मिल में गन्ना ले जाते हैं उनको शहर में से होकर जाना पड़ता है उनके लिए बाई पास बनाया जाए। यह सुझाव भी अच्छा है।

चौ. मनी राम जी ने भी अच्छे सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा में एक जीनिग मिल लगाया जाए और मंडी डबवाली तथा कालांवाली की नगरपालिकाओं का और अनुदान दिया जाए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सही नगरपालिका हो हम पहले से ही अनुदान दे रहे हैं और इन दोनों नगरपालिकाओं को भी मिलेगा। उन्होंने कुछ बातें सिंचाई के बारे में भी कहीं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सिंचाई मंत्री जी से मिलकर अपनी सारी समस्याएं बताएं। इन्होंने यह भी कहा कि डबवाली में 50 बिस्तर का हस्पताल होना चाहिए। (विघ्न) जब स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपको कह दिया है तो न बनने का सवाल ही नहीं है। हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री जी चूंकि यहां विराजमान हैं इसलिए इन्होंने जो कहा कि गंगा ग्रांम में अलग से वाटर वर्कस होना चाहिए, वे बइस बात की और विचार करेंगे।

श्री कान्ति प्रकाश जी भल्ला ने अपने क्षेत्र के बारे में एक बात कही। यह बात ठीक है कि उनका इलाका पहाड़ी क्षेत्र

है। वहां सड़कों की कमी है और पुलों की भी कमी है। इन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि अगर पक्के पुल न बनाएं जा सकें तो हैंगिंग ब्रिज बना दिए जाएं। इस पर विचार किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले उनके हल्के में गए थे और आश्वासन देकर आए थे कि टांगरी नदी पर पुल बनेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो वायदे हैं उनके ऊपर हम फूल चढ़ाते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि उनके सभी वायदों को हम पूरा करेंगे।

चौ. असलम खां ने अपने क्षेत्र के लिए मांगें रखी। ये बहुत भले आदमी हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी है कि इतने भले आदमी आज तक कांग्रेस में कैसे बैठे हैं? भले आदमी तो सारे कांग्रेस छोड़ चुके है। ये बहुत ही सज्जन आदमी हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। इन्होंने कहा कि छछरौली के अन्दर भी सूखा है। केन्द्रीय टीम ने या प्रदेश के अधिकारियों ने अगर गलती से इसको सूखा ग्रस्त नहीं माना है तो मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको दोबारा दिखा लें। अगर वह इलाका सूखे से प्रभावित हो तो वहां भी सूखा राहत के लिए कोई काम जरूर किया जाए। ग्रामों में शराब के विकास की बात भी इन्होंने कही कि हर गांव में शराब का दौर हैं। यह बात जो उन्होंने कही है, यह ठीक बात है कि शराब का तेजी से प्रचार बढ़ रहा हैं इसमें केवल सरकार दोशी है, ऐसी कोई बात है कि शराब का तेजी से प्रचार बढ़ रहा है। इसमें केवल सरकार

दोशी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों में यह आदत बढ़ी है। यदि शराब के ठेके ही बन्द कर दिये जायें तो लोग फिर नाजायज शराब निकालेंगे, बेचेगे, पियेगे और फिर ऐसी घटनाएं ज्यादा होंगी कि इतने लोग जहर पीकर मर गये अब कम से कम ठेकों पर शराब ठीक तेा मिलती है। कहीं न कहीं उसका टैस्ट तो होता है। परीक्षा तो उसकी होती है। (व्यवधन व शोर) पेड़ों के काटने के बारे में चौ. असलम खां ने कहा कि दो पेड़ घर के लिये काटें तो इजाजत मिल जाती है लेकिन अगर बेचने के लिये काटें तो बड़ा कठिन तरीका है। उसका सरलीकरण किया जाये। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। बलाचौर से एक सड़क की बात भी उन्होंने कही है। सिंचाई के प्रबन्ध की बाबत भी उन्होंने कहा है। ये सारी बातें हमने नोट कर ली हैं।

श्री सीता राम सिंगला जी ने निजी कालेज के स्टाफ को ग्रेड देने की बात कही और यह कहा कि जो प्राईवेट कालेजिज हैं, उनको सरकार ने टेकओवर कर लिया था, वहां पर भी सरकारी ग्रेड मिलने चाहियें। जहां तक मुझे पता है जो भी महाविद्यालय ऐसे हैं, उनके अन्दर वही ग्रेड दिये जा रहे हजै जो सरकारी या गर्वनमैंट कालेजिज में दिये जा रहे हैं। मेरे ख्याल में उनके ग्रैड के अन्दर कोई फर्क नहीं हैं। उनको यह शिकायत नहीं होनी चाहिये। एक उन्होंने यह कहा है कि शहरों और गांवों का ए.बी.सी. के आधार पन वर्गीकरण किया गया है। ए. वर्ग के शहरों

में कर्मचारियों को जो सुविधा मिलती हैं, वह भी गांव में रहने वालों को मिलनी चाहियें। इस बात पर हम विचार कर लेंगे।

श्री कादयान साहब ने भी अपने हल्के की कुछ मांगें यहा पर रखी हैं। सड़कों की और दूसरी बातों की बाबत श्री सरदूल सिंह जी ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात कही थी। आज उन्होंने सफीदों की सड़कों, पानी और दूसरी कई समस्याओं का जिक्र किया है। श्री गुरदियाल सिंह जी ने थानेसर में उच्च महाविद्यालय के भवन की कमी का भी जिक्र किया। वहां पर दो शिफ्टें हैं। इस बात के बावजूद वहां पर कमी है। मैं उनका ध्यान इस बात की तरफ दिलाऊंगा कि उन्होंने जो आयुवैर्दिक कालेज की बात कही है, उसके लिये हमने फण्डज रिलीज कर दिये हैं और जो स्टाफ की कमी थी, उसको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है और जल्दी ही उसको भी दूर करवाने की कोशिश करेंगे। कादयान साहब ने एक बात कही कि इसराना के अन्दर सब–तहसील तो है लेकिन वहां पर ट्रैजरी नहीं खुली है। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि वहां के लिये सब–ट्रैजरी मन्जूर हो चुकी है। जल्दी ही इसराना के अन्दर एक सब–ट्रैजरी खोल दी जायेगी। जब सिंह राणा जी ने भी नीलोखेडी हल्के की बातें कहीं। इन सारी बातों की तरफ ध्यान दिया जायेगा अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं यहीं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितनी भी मांगे सदन के सामने प्रस्तुत की गयी हैं, उनको पास किया जाये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, मैं एक क्लैरीफिकेशन देना चाहता हूं। इस समय श्री रघु यादव जी चले गये हैं। एम.एल.ए. साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि 92 जोहड़ों को पानी से भरने का दावा किया गया था लेकिन कम जोहड़ भरे गए। मैं इस बार में एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। इनका एक अन–स्टार्ड क्वैश्चन था। वह इसी सैशन में लगा था। वह सवाल उन्होंने मेरे से पूछा था। उसमें इन्होंने यह पूछा था कि 17 जून से 25 अगस्त तक कितने जोहड़ पानी से भरे गये। उसके जवाब में मैंने बताया कि 98 जोहड़ पानी से भरे गये जिसमेंसे रिवाड़ी उपमण्डल के 79 और नारनौल उपमण्डल के 19 थे। एक सवाल इन्होंने श्री सूरजभान जी से किया। वह तारांकित सवाल है और उसका न. 128 है। वह साारे पीरियड का सवाल है। वह किसी स्पैसिफिक पीरियड का सवाल नहीं था। उसके जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि विभिन्न गांवों में 241 जोहड़ों को पानी से भरा गया। मुझे यह क्लैरिफिकेशन देनी थी।

श्री अध्यक्ष: अब मैं वेरियस डिमांडज फार ग्रान्टस को वोटिंग केक लिये रखता हूं।

आवाजें: सबको एक साथ पुट कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

Mr. Speaker: Question is –

That a sum nto exceeding Rs. 10262000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a sum nto exceeding Rs. 257256000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

That a sum nto exceeding Rs. 677080000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum nto exceeding Rs. 129599000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum nto exceeding Rs. 68599000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum nto exceeding Rs. 322157000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum nto exceeding Rs. 521912000 for revenue expenditure and Rs. 4186000 for capital expenditure

be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum nto exceeding Rs. 538911000 for revenue expenditure and Rs 405775000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a sum nto exceeding Rs. 2166407000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum nto exceeding Rs. 1143799000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum nto exceeding Rs. 45416000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum nto exceeding Rs. 116041000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum nto exceeding Rs. 1119362000 for revenue expenditure and Rs. 17304000 for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum nto exceeding Rs. 34061000 for revenue expenditure and Rs. 1627786000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 14- Food and Supplies.

That a sum nto exceeding Rs. 1704217000 for revenue expenditure and Rs. 769482000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 15- Irrigation.

That a sum nto exceeding Rs. 129407000 for revenue expenditure and Rs. 26716000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum nto exceeding Rs. 528070000 for revenue expenditure and Rs. 18000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum nto exceeding Rs. 187618000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 18- Animal Husbandary.

That a sum nto exceeding Rs. 24260000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum nto exceeding Rs. 229099000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum nto exceeding Rs. 439030000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum nto exceeding Rs. 69235000 for revenue expenditure and Rs. 61756000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum nto exceeding Rs. 1164349000 for revenue expenditure and Rs. 144000000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum nto exceeding Rs. 17235000 for revenue expenditure and Rs. 12200000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum nto exceeding Rs. 2220076000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1988-89 in respect of charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः साढ़े नौ बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

***13.27 बजे**

(तत्पश्चात् सदन बधुवार दिनांक 30.3.1988 को प्रातः 9. 30 बजे तक के लिए *स्थगित हुआ)।